राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ६] तृतीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६६ का १८वां दिवस [संख्या १४

मंगलवार, १५ मार्च, १९६६

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.५ बजे सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(उद्योग, स्वायत्त शासन, यातायात, विद्युत, सहकारी, सार्वजनिक निर्माण, योजना, खनिज, समाज कल्याण, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, सार्वजनिक उद्योग संस्थान, जन स्वास्थ्य-विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न—श्री अब्दुलजब्बार।

विजयनगर शूगर फैक्ट्री

२५२. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि विजयनगर शूगर फैक्ट्री को बन्द हुए अर्सा हो गया है ?

(२) क्या यह सही है कि इस फैक्ट्री का सर्वोत्तम उपयोग इसे निम्बाहेड़ा में लगा कर किया जा सकता है ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद): (१) हांजी।

(२) सरकार के पास इस तरह का कोई निवेदन नहीं है।

श्री अब्दुलजब्बार : आपने निवेदन का फरमाया है कि इस प्रकार का निवेदन नहीं है पर इसका सदुपयोग निम्बाहेड़ा में लगा कर किया जा सकता है।

श्री चन्दनमल वैद : निम्बाहेड़ा में लगाने के लिये कोई प्रोपोजल मांगे, इमदाद मांगे, कोई निवेदन करे, हमें कोई कहें कि लगाओ हमारे पास उनके कोई विचार आवें तो हम कहें।

श्री अब्दुलजब्बार : इस फैक्ट्री के लिये सरकार ने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है क्या ? क्या सरकार ने इस पर पैसा लगाया है क्या ?

श्री चन्दनमल वैद : जी हां, लोन नहीं गारन्टी है ५ लाख की।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या वह ५ लाख का इन्ट्रेस्ट दे रहा है ?

श्री चन्दनमल वैद : इसकी वसूली करने के लिये पी. डी. आर. के तहत कार्यवाही की जा रही है।

श्री अब्दुलजब्बार : पी. डी. आर. के तहत कार्यवाही की जा रही है तो यह

Page No. 2

(श्री अब्दुलजब्बार)
फैक्ट्री इससे लेकर निम्बाहेड़ा में क्यों नहीं लगा दी जाती जिससे कि वहां गन्ने की पेराई की जाकर शूगर का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके ?

श्री चन्दनमल वैद : जुडिशियरी में कार्यवाही हो रही है। यह नहीं हो सकता कि हम किसी में पैसा मांगते हैं तो उसकी फैक्ट्री ले लें।

श्री अब्दुलजब्बार : पी. डी. आर. के तहत कार्यवाही कब शुरू की ?

श्री चन्दनमल वैद : तारीख मेरे पास नहीं है।

प्रश्न संख्या २५३

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री अब्दुलजब्बार : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बड़ा अहम प्रश्न है। सरकार का ५ लाख रुपया यों ही व्यर्थ में रुका पड़ा है। इस फैक्ट्री को लेकर यदि सरकार इसे निम्बाहेड़ा में लगा दे तो इससे शक्कर की कमी को काफी अंशों में दूर किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत !

रोडवेज की बसें

२५४. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या यातायात मंत्री यह बतायेंगे:—

(१) क्या सरकार के ध्यान में है कि राजस्थान स्टेट रोडवेज कोर्पोरेशन की तरफ से देखभाल की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बसें रास्ते में अक्सर खराब हो जाती हैं ?

(२) क्या यह सच है कि कोर्पोरेशन के कर्मचारी व अधिकारी इस ओर भी जागरूक नहीं हैं कि हर मार्ग पर आखिरी गाड़ी अच्छी हालत में भेजी जावे, ताकि यात्रियों को असुविधा नहीं हो ?

(३) जोधपुर-पाली-सोजत-जैतारण मार्ग पर चलने वाली गाड़ी अक्टूबर, १९६४ से जुलाई, १९६५ तक प्रत्येक माह में कब कब खराब हुई ? कितने कितने यात्री उस समय गाड़ी में थे व उनको निर्धारित स्थान पर कब पहुँचाया व जिनको नहीं पहुँचाया गया उसका किराया लौटाया गया या नहीं ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) यह सरकार के ध्यान में है कि बसें पुरानी होने के कारण कभी कभी रास्ते में खराब हो जाती हैं।

(२) जी नहीं। ये पूर्णतया जागरूक हैं।

(३) जौधपुर-पाली-सोजत-जैतारण मार्ग पर माह अक्टूबर १९६४ से माह जुलाई १९६५ तक जो गड़ियां खराब हुई उनमें कितने यात्री थे तथा उन्हें निर्धारित स्थान पर कब पहुँचाया गया—की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। जहां तक किराये के लौटाने का प्रश्न है यात्रा के मध्य में किराया वापिस नहीं किया जाता; आवेदन-पत्र देने पर सम्बन्धित डिपो मेनेजर ही किराया वापिस देने की स्वीकृति देते हैं। यात्रियों को गन्तव्य स्थानों पर दूसरी गाड़ियों से भेजा जाता है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री तेजाराम गहलोत : नं० १ के उत्तर में आपने बताया कि गाड़ियां पुरानी हो

Page No. 3

(श्री तेजाराम गहलोत)

जाने की वजह से खराब हो जाती हैं तो ऐसी पुरानी गाड़ियों को डिपो से रवाना कराने से पहले जांच करके नहीं भेजा जाता है क्या कि यह गन्तव्य स्थान तक पहुंचने के लायक है ?

श्री भीम सिंह : जांच करके भेजते हैं, फिटनैस सर्टिफिकेट भी देते हैं, मेकेनिकली एप्रूव कर लेते हैं; फिर भी मशीनरी तो ग्राखिर मशीनरी ही है, कभी कभी खराब हो जाती है। हमेशा फेल नहीं होती है, कभी कभी फेल हो जाती है। कुल टोटल सर्विसेज में फेल हुई उनका पर्सेन्टेज कितना है, उससे एफिशियेन्सी मालूम होती है।

श्री तेजाराम गहलोत : तो क्या सरकार चाहती है कि हर गाड़ी फेल हो। डिपो से रवाना होती है तो किसी गाड़ी में लाइट नहीं होती है, किसी में कोई खराबी है तो किसी में कोई खराबी, मेरी स्वयं की कम्प्लेन्ट लिखी हुई है, कम्प्लेन्ट बुक में भी ग्रौर डिपो में भी, फिर भी ध्यान नहीं देते हैं। पैसेन्जर्स को तकलीफ होती है। मैं निवेदन करूंगा कि नेशनेलाइज़ेशन की वजह से सरकार बदनाम होती है, उससे तो बचें।

श्री भीमसिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जिस बस से माननीय सदस्य ने सफर किया वह फेल हो गई, पर जिस रूट का ग्रापने कहा उस पर १० महीने में ६०८ सर्विसेज ने रन किया उनमें २१ ब्रेक डाउन हैं।

श्री तेजाराम गहलोत : १० महीने में सिर्फ १० गाड़ियां चली हैं; मैंने नं० १ में पूछा है; जोधपुर से जैतारण का न कि पूरी गाड़ियों की सूचना। जो जैतारण नाइट हाल्ट करती है, जोधपुर के लिये रवाना होती है, सोजत पाली हो कर वह २१ जगह फेल हुई है कभी कहीं रोक दी। कोई ड्राइवर ग्राया उसने देखा कि यहां मेरा गांव है या मेरा रिश्तेदार है ग्रौर मुझे यहां रुकना है, वहीं बस रोक दी।

श्री मजलिस खां (कामां) : क्या यह सही है कि फर्स्ट एड बॉक्सेज इन गाड़ियों में नहीं होते ?

श्री भीमसिंह : होते हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री मजलिस खां।

कस्बा पहाड़ी को बिजली

२५५. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कस्बा पहाड़ी को भाकरा से २५० किलोवाट बिजली की सप्लाई स्वीकृत हो गई है ? यदि हां, तो यह कब तक सप्लाई हो जायेगी ?

(२) क्या यह भी सही है कि कस्बा गोपालगढ ग्रौर सीकरी के लिए पहाड़ी से ही बिजली सप्लाई की जावेगी ? यदि हां, तो क्या इस लाइन का सर्वे करा लिया गया है ग्रौर यदि करा लिया गया है तो लाइन खेंचने का कार्य कब तक शुरू करा दिया जावेगा ?

(३) क्या यह भी सही है कि सब तहसील पहाड़ी ग्रौर थाने के भवनों को बिजली की सप्लाई के लिए राजस्व एवं पुलिस विभाग ने मांग की है ? यदि हां, तो उक्त भवनों को बिजली कब तक सप्लाई कर दी जावेगी ?

Page No. 4

(श्री मजलिस खां)

(४) क्या सरकार कस्बा पहाड़ी के पास पड़ोसी ग्रामों को सिंचाई के लिए बिजली सप्लाई करेगी ? यदि हां, तो वे कौन कौन से ग्राम है और कब तक ?

उप-मंत्री, विद्युत (श्री चन्दनमल) वैद: (१) पहाड़ी को ६-५-६५ को बिजली दे दी गई है । २५० किलोवाट देने का कोई एग्रीमेंट नहीं है ।

(२) अभी कोई योजना नहीं है । सर्वे हुआ था किन्तु डिटेल्ड सर्वे नहीं हुआ है । अभी किसी भी योजना में भी शामिल नहीं है, इस कारण प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(३) जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

(४) जी हां । अभी केवल पहाड़ी में ही सिंचाई के लिए बिजली देने की स्वीकृति है । जैसे २ धनराशि उपलब्ध होगी वैसे ही आस-पास के इलाके में बिजली का फैलाव किया जायेगा ।

श्री मजलिस खां : क्या पंजाब सरकार से यह तय हो गया है कि पहाड़ी को २५० किलोवाट बिजली सप्लाई की जायेगी ?

श्री चन्दनमल वैद : नहीं हुआ ।

श्री मजलिस खां : मैंने सुना है कि तय हो चुका है ।

श्री चन्दनमल वैद : मैंने दो बार इन्कार कर दी, इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह ।

रामगंज मण्डी व सांगोद क्षेत्र में लैंड मोर्टगेज बैंक्स

२५६. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) रामगंज मण्डी व सांगोद क्षेत्र में लैंड मोर्टगेज बैंक्स की स्थापना कब से की गई है ?

(२) इन दोनों क्षेत्रों में बैंक स्थापित होने से अब तक कितना कितना रुपया कृषकों को किन किन मदों में स्वीकार किया गया है ?

(३) क्या यह सही है कि इन लैंड मोर्टगेज बैंक्स द्वारा सुचारु रूप से काम शुरू नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्या कारण है और विभाग द्वारा इन बैंकों को सुदृढ़ व व्यवहारिक बनाने के लिए क्या किया जा रहा है ?

उप-मंत्री, सहकारी (श्री भीमसिंह) : (१) रामगंज मण्डी व सांगोद प्राथमिक भूमि बन्धक बैंकों की स्थापना क्रमशः दिनांक २–३–६५ एवं १६–२–६५ को की गई ।

(२) सांगोद प्राथमिक सहकारी भूमि बन्धक बैंक ने अभी हाल में कार्य प्रारम्भ किया है तथा रामगंज मण्डी सहकारी भूमि बन्धक बैंक के स्थापित होने से अब तक ४०,६०० रु० ऋण विभिन्न कृषि कार्यों के लिए स्वीकृत किया गया है ।

(३) जी नहीं ।

श्री जुझारसिंह : आपने प्रश्न तीन के जवाब में 'जी नहीं' कहा है और एडमिट किया है कि सांगोद बैंक ने काम शुरू नहीं किया है जब कि सैंक्शन साल भर पहले हो गई, फिर कैसे फरमा दिया····

Page No. 5

श्री भीमसिंह : काम जरूर शुरू हो गया, लेकिन उसमें जो सेक्रेटरी था उसने देरी से कार्यभार सम्भाला । बाकी यह कहना कि काम कोई नहीं हुआ, गलत है ।

श्री जुझारसिंह : अभी तक लोन्स कितने एडवांस हुए हैं ? कुछ भी एडवांस नहीं हुआ है । सेक्रेटरी की एपोइन्टमेंट आपने १२ महीने के बाद की, उसके एपोइंट-मेंट होने से ही तो नहीं माना जाता कि काम शुरू हो गया ।

श्री भीमसिंह : पहले ऋण के लिए आवेदन-पत्र नहीं आए थे, बाद में १५ प्रार्थना-पत्र आए हैं जिनका ३९ हजार रुपए जनवरी और फरवरी १९६६ में बकाया है, जिसका कारण यह है कि पिछले १३ वर्षों का रेवेन्यू रेकॉर्ड नहीं दे पाए हैं ।

श्री जुझारसिंह : मैं सांगोद के लिए पूछ रहा हूं, आप रामगंज मंडी के लिए कह रहे हैं । उसमें आपने फरमाया कि ४५,०००) एडवांस कर दिए, १५ केसेज आपने बताये कि रामगंज मंडी के हैं। उसके अलावा सांगोद के लिए कितने लोन्स दिए ?

श्री भीमसिंह : जैसा मैंने निवेदन किया सेक्रेटरी का लेट एपोइंटमेंट होने से हो सकता है कि खामी रही हो मगर आप डिटेल्स दे दें····

श्री जुझारसिंह : आपने काम शुरू नहीं किया, एक पैसा भी लोन नहीं दिया; १२ महीने हो गए बैंक को स्थापित हुए, अब सेक्रेटरी का एपोइंटमेंट हुआ है, यह तो कोई काम नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : इतनी जो शाखाएं आपने खोल दीं उससे तो छोटी छोटी थोड़ी शाखाएं हों ज्यों ज्यों काम बढ़ता जाता है तो अच्छा होगा ।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : क्या यह सही है कि इस प्रोसीजर से जनता को परेशानी होती है ? इस सम्बन्ध में सरकार क्या सोचती है ?

श्री भीमसिंह : नियमों में सुधार करने का सोच रहे हैं और नियमों को रिवाइज कर रहे हैं, ताकि लोगों को मिल्कियत साबित करने में आसानी हो, सारी चीज को ओवर-हॉल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि डिले न हो ।

श्री जुझारसिंह : यह डिले इसलिए होती है कि प्रोसीजर बहुत कॉम्पलीकेटेड है, काश्तकार लोग एप्लीकेशन दे देते हैं उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाते । १३ साल का रिकॉर्ड मिलने में तकलीफ होती है उसकी वजह से ऋण नहीं मिल पाता ।

सहकारी मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : नए एक्ट में प्रोसीजर को बहुत सिम्पलीफाई कर दिया है ।

एक माननीय सदस्य : जिसके पास खातेदारी राइट्स हों, उसको ही आप क्यों नहीं मान लेते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : नए रूल्स के अन्दर प्रावधान किया है ।

श्री गोविन्दसिंह : लागू कब से किया जायगा ?

Page No. 6

श्री मथुरादास माथुर : ये रूल्स लागू हो चुके हैं।

श्री जुझारसिंह : आपके कहने के अनुसार अब आवश्यक नहीं रहा....

श्री मथुरादास माथुर : जानकारी करनी पड़ेगी कि जमीन का मालिक तो नहीं है।

प्रश्न संख्या २५७

श्री मथुरेशबिहारी माथुर।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री पोहूमल ईसरदास।

हरिजन तथा बागड़ियों के नष्ट किये गये झोपड़ों की एवज में जमीन

२५८. श्री पोहूमल ईसरदास (अजमेर पश्चिम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सन् १९६२ में उसरी गेट, अजमेर में नगरपालिका अधिकारियों द्वारा हरिजन तथा बागड़ियों के झोंपड़ों को नष्ट किया गया था? यदि हां, तो क्यों?

(२) क्या यह भी सही है कि हरिजन डिस्पलेस्ड पर्सन्स थे?

(३) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका अधिकारियों द्वारा उन्हें उठाने से पूर्व उनकी प्लान तथा लीज मनी स्वीकार कर ली गई थी? यदि हां, तो लीज पर देने के लिए अनुमति क्यों नहीं दी गई?

(४) क्या उन्हें उनके बदले मुफ्त प्लॉट्स दिये गये?

उप मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां, नगरपरिषद् की बिना स्वीकृति के जमीन पर एन्क्रोचमेंट करने से।

(२) वह सूचना प्राप्त नहीं है।

(३) यह सही नहीं है।

(४) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

श्री पोहूमल ईसरदास : मुझे जानकारी है कि उनको झोंपड़ों से हटाया गया?

श्री दौलतराम सारण : मैंने 'हां' कहा है।

श्री पोहूमल ईसरदास : फिर उनको लीज क्यों नहीं दी जाती है?

श्री दौलतराम सारण : यह नगरपरिषद् के देखने की बात है कि उनको क्यों नहीं दी जाती है, उसके अधिकार क्षेत्र में हैं।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन–सु.) : इनको हटाने का क्या कारण था?

श्री दौलतराम सारण : अनधिकृत कब्जा था।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : ऐसे कई जगह हरिजन हैं, शहरों में भी होते हैं और २०–२० साल का कब्जा होता है, लीज नहीं होता है क्योंकि उनका प्रभाव नहीं होता है और फिर क्या करते हैं? नगरपरिषद वाले आए साल उनको डिस्प्लेस करते हैं, उनको दूसरी जगह आबाद करते हैं, इस संबंध में सरकार की कोई निश्चित पॉलिसी होनी चाहिए; यह १० साल से बराबर हो रहा है

Page No. 7

(श्री राबतराम)
और आप एक ही तरह का जवाब देते आ रहे हो।

श्री पोहूमल ईसरदास : मंत्री महोदय को शायद पूरी जानकारी नहीं है। वे लोग वहां पर बैठे थे जिस प्लाट से उनको हटाया गया। उससे पहले उन्होंने लीज का पैसा दिया, एप्लीकेशन्स दीं। हटाने के बाद भूख-हड़ताल की, ट्रस्ट के सैक्रेटरी के पास गए; एडमिनिस्ट्रेटर के पास गए। सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेंट से ७५०) रु. हरेक को मिलने वाले थे लेकिन नगरपालिका रोड़ा अटका रही है। मंत्री महोदय आश्वासन दे दें कि जानकारी करके उनको अपना हक दे दें!

श्री दौलतराम सारण : इसकी जानकारी नगर परिषद् से करके मैं कह सकता हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सरकार बता सकती है कि हरिजन और वागरियों, जिनको हटाया गया है इस भूमि पर कब से काबिज थे?

श्री दौलतराम सारण : मैं नहीं कह सकता मेरे पास पूरी सूचना नहीं है। लेकिन ये अनधिकृत थे या थोड़े समय से होंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल: क्या सरकार ने इस केस को कभी एग्जामिन किया है कि लोकल बॉडीज का नोटीफिकेशन, जिनके अनुसार ऐसे लोगों के कब्जे को रेग्युलराइज़ करना था और वह जनरल नोटीफिकेशन निकाला था उस लाइट के अन्दर क्या सरकार ने एग्जामिन किया है कि उन लोगों के कब्जे को भी रेग्युलराइज किया जा सकता था या नहीं?

श्री दौलतराम सारण : मैंने इस बारे में आश्वासन दिया है कि सारे मामले की जानकारी करके और जो संभव कार्यवाही होगी की जायगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अजीब स्थिति है। माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है और यह समस्या केवल अजमेर के लिए ही नहीं सारे राजस्थान की समस्या है। सरकार से खास प्रश्न किया गया है जिसकी मन्शा है कि उनको नाजायज ढंग से हटाया गया और सरकार उत्तर दे कि एग्जामिन करवा लेंगे; तो यह प्रश्न टालने की चीज है।

श्री दयाचन्द सोन (बारा–सु.) : क्या भारत सरकार के आदेश हैं कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं और २०-२० साल से रह रहे हैं उनको पट्टे दिये जायं?

श्री दौलतराम सारण : सदन में जानकारी दी जा चुकी है कि राजस्थान सरकार ने अनधिकृत कब्जों को निश्चित आधार पर नियमित करने के आदेश जारी किए है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : एक प्रश्न मैं करना चाहता हूं। ये हरिजन थे, इनको बसाया गया। इसके बाद यह स्थिति हुई कि जो एडमिनिस्ट्रेटर आया उस जमीन से उनको हटाया जबरदस्ती लालच देकर कि पैसा जमा कराओ तो तुमको जमीन देते हैं। उन्होंने पैसा जमा कराया, रसीद ली, रसीद लेकर फिरते रहते हैं। आज वे लोग बिल्कुल बरबाद पड़े हुए हैं। बरसात से ढकने के लिए उनके पास मकान नहीं हैं। यहां भी आये, मिले, सबके साथ बातचीत की। मैं समझता हूं, बहुत बड़ी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
ज्यादती हो रही है। इसलिए इनका वर्षा से पहले पहले इन्तजाम कराइये।

श्री दयाचन्द सोन : हरिजनों के साथ कुठाराघात होता है। दूर बस्तियों में बसते हैं। शहरों का डेवलपमेंट होता है तो उनकी झोपड़ियों को फेंक देते हैं। सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। यह एक ही जगह की समस्या नहीं है, सब जगह की समस्या है; आप सुनते ही नहीं हैं।

श्री दौलतराम सारण : मैं सब सुन रहा हूं। मेरी भी सुन लीजिये।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : वे तो बहरे हैं सुनेंगे क्या? उन्हीं को सुने जाओ।

श्री दौलतराम सारण : आपका ठीक कर लें।

जहां तक इस प्रश्न का सवाल है, इसमें मैं जानकारी करूंगा और क्या किया जा सकता है मुनासिब कार्यवाही उसके सम्बन्ध में की जावेगी।

श्री दयाचन्द सोन : ये २०-२५ वर्ष से बसे हुए हैं।

श्री हरिराम धारू (सिवाना सु.) पट्टे का सवाल सही है। यहां पर १५, १६ बस्तियां हरिजनों की हैं, महतरों की है जिनको पट्टे देते हैं, न प्रमाण-पत्र देते हैं। चालीस वर्ष से उनका कब्जा है। प्रमाण-पत्र दें तो उनको सहायता मिल जाय। सारे राजस्थान के लिये, जहां जहां ४०-५० वर्ष से बसे हुए हैं उनको पट्टे या प्रमाण-पत्र दे देवें; ज्यादा कहना ठीक नहीं समझता। मिलते नहीं हैं, पट्टे साहब, विश्वास देकर रह जाते हैं।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): उदयपुर नगरपरिषद् द्वारा जो लोग जमीनों पर पुराने बसे हुए हैं उनमें एक आना गज लेकर पट्टे दे दिए, क्या इस प्रकार और जगहों के लिये भी करने के लिये तैयार हैं?

श्री दौलतराम सारण : यह अलग प्रश्न है।

श्री रावतराम : आखिर उनका फार्मूला क्या है। अजमेर का ही सवाल नहीं है। यह राजस्थान में सब जगह का सवाल है। लोगों को पट्टा नहीं देते हैं, न उनको लीज देते हैं और वहां से लोगों को हटा रहे हैं।

स्वायत्त शासन मंत्री (बरकतुल्ला खां): जहां तक अजमेर म्युनिसिपेलिटी का सम्बन्ध था उन्होंने बताया कि अनआथोराइज्ड ओक्युपेशन है, म्युनिसिपेलिटि ने लैंड अलॉट नहीं की, बहुत पहले से बैठे थे, उसके साथ यह भी बताया कि बगैर म्युनिसिपेलिटी की मांग किये उन्होंने यह म्युनिसिपेलिटी से मांग की कि यह जमीन उनको देदी जाय और पैसा ले लिया जाय। उन्होंने पैसे दे दिये, प्लान भी दे दिया। यह जमीन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट में चली गई और मेले के पास जमीन थी उनको अलॉट की गई। उन्होने वह जमीन लेने से इन्कार कर दिया। जहां तक हरिजनों का सवाल है गवर्नमेंट ने इन्सट्रक्शन्स दे दिये हैं कि हरिजन जहां पर बैठे हैं उनको बेदखल न किया जाय और एक रुपया लेकर पट्टा दे दिया जाय। निजी तौर पर शिकायतें आती हैं। यह नहीं हो सकता कि जहां अच्छी जमीन है वहां जाकर बैठ जांय और मांग करें कि उनको वहां का पट्टा दे दिया जाय। जहां पर पहले से बसे हैं वहां पर उनसे १)

(श्री बरकतुल्ला खां)
लेकर पट्टा दे दिया जाय जयपुर में भी पर्सनली मैंने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन और म्यूनिसिपेलिटी के चेयरमेन को कहा कि हरिजनों को जहां बसे हैं वहां से न हटायें और उन्हें वहीं पर सेटल कर दीजिए; यह गवर्नमेंट की पोलिसी है।

श्री हरिराम घारू : मंत्रीजी फरमा रहे हैं लेकिन जाते हैं कलेक्टर, म्युनिसिपेलिटी के चेयरमैन, एडमिनिस्ट्रेटर के पास, वे कहते हैं कि हमारे पास, पहले ऑर्डर आ गया कि पट्टे दे दो। नाजायज तौर से म्युनिसिपेलिटी देने लगी इसलिए स्टेट ऑर्डर आगया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने सिद्धांत की बात कह दी। दावे के साथ अजमेर मे दो मेम्बर कह रहे हैं; उनके पास रसीदें मौजूद हैं। लेकिन उनको हटा दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि रिफ्युजीज थे तब उनको बैठाया गया था वहां। दो दफा बैठाया गया, हटा दिया। रावण का मेला लगता है वहां से हटा दिया। फिर उनको बैठाया गया। उनका कोई नाजायज कब्जा नही है। उनसे पैसा लिया गया है, रसीदें दी हैं; फिर हटा दिया।

श्री बरकततुल्ला खां : इस सम्बन्ध में प्रॉपर जानकारी करके कार्यवाही की जावेगी। जहां तक मेरे पास जानकारी आयी है उसमें अनऑथोराइज्ड ऑक्युपेशन लफ्ज है। जिस तरह से अलॉट करना चाहिए नहीं की है और अजमेर से आये माननीय सदस्य जैसा इस सम्बन्ध में कह रहे हैं वैसी बात है तो उस पर ऐक्शन लिया जावेगा।

प्रश्न संख्या २५९

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई!

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या २६०

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल!

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री कृष्णकुमार गोयल!

कोटा में गैस टर्बाइन

२६१. **श्री कृष्णकुमार गोयल :** (कोटा) क्या विद्युत मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) कोटा में गैस टर्बाइन कब आया?

(२) गैस टर्बाइन पर उसके मूल्य; ट्रान्सपोर्टेशन, व इन्स्टालेशन पर कितना कितना व्यय हुआ?

(३) इस पर अतिरिक्त रेकरिंग व्यय माहवारी कितना हो रहा है?

(४) यह टर्बाइन प्रतिदिन कितनी बिजली पैदा करेगा?

(५) इसके अतिरिक्त इसके साथ-साथ गांधी सागर कितनी बिजली प्रतिदिन देता रहेगा?

(६) टर्बाइन के पूर्व गांधी सागर से बिजली का वितरण कोटा शहर में किस प्रकार होता था?

(७) टर्बाइन से बिजली देने पर गांधी सागर व इस टर्बाइन की बिजली का वितरण कोटा शहर में किस प्रकार होगा?

(८) उक्त बिजली का उत्पादन-व्यय क्या होगा तथा भिन्न २ उपभोक्ताओं से क्या चार्ज किया जावेगा?

उप-मन्त्री विद्युत् (श्री चन्दनमल वैद) : (१) गैस टर्बाइन २७-१२-६५ को कोटा जंक्शन पर आई थी। ज्यादातर खास-खास भारी पैकेट डकानिया तालाब रेलवे स्टेशन पर २६-१२-६५ से १-१-६६ तक उतार दिये गये थे।

(२) पूर्ण रूपेण लेखा-जोखा बो बन रहा है। अभी तक खर्चा इस प्रकार हुआ है : मूल्य के मदों में ७० लाख। ट्रान्सपोर्टेशन के मद में १,४८,३९५.६०, इन्सटालेशन पर रु० ७४,५९९.५७।

(३) गैस टर्बाइन २८-२-६६ को ही चालू हुई है। अतः इसके रेकरिंग व्यय के बारे में अभी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(४) इस टर्बाइन से लगभग १,२०,००० यूनिट प्रतिदिन उत्पादन होगी।

(५) पहले किये गये सी. डबल्यू. पी.सी. के अनुमान के अनुसार गांधी सागर से ५०००० यूनिट प्रतिदिन १५ मार्च से राजस्थान को मिलने का प्रावधान था।

(६) कोटा शहर को निम्नलिखित जरियों से बिजली उपलब्ध हो रही है:—

(१) गांधी सागर से ६५,००० युनिट।

(२) जयपुर थर्मल स्टेशन से १,२२,००० युनिट।

(३) कोटा थर्मल स्टेशन से ३३,००० युनिट।

(७) यदि हो सका तो गांधी सागर स्टेशन व गैस टर्बाइन को एक साथ बिजली देने को सम्मिलित रूप से चलाया जायगा। यदि यह सम्भव नहीं हुआ तो गैस टर्बाइन की विद्युत् कोटा को दी जायेगी और गांधी-सागर से उपलब्ध विद्युत् मात्रा को झालावाड़, भीलवाड़ा व उदयपुर क्षेत्रों को दी जावेगी।

(८) प्रश्न विचाराधीन है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : खंड ३ का उत्तर दिया है कि गैस टर्बाइन २८-२-६६ को चालू हुई है। इसलिए इसके रेकरिंग व्यय के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। क्या यह सही है कि इस प्लान्ट को लगाने में स्टाफ ७ महीने पहले से ही वहां पर लगा हुआ था ?

श्री चन्दन मल वैद : रेकरिंग व्यय पूछते हैं, तो चालू हुआ तब से ही तो बताया जायेगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के आदमी उसको लेने के लिए बाहर भी गए, मेहनत भी की; बिजली की दिक्कत को दूर करने के लिए काफी प्रयत्न किए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : माहवारी वेतन कितना देना पड़ रहा था ?

श्री चन्दनमल वैद : अलग से प्रश्न पूछें तो बता सकता हूं।

श्री दयाचन्द सोनी (बारां, सु०) : जानकारी नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद : जानकारी नहीं है तो पूरा प्रश्न कैसे सुन रहे हैं।

श्री दयाचन्द सोनी : जरा अकड़ कर जवाब मत दीजिए, साहब !

श्री अध्यक्ष : कितने मेगावाट का उत्पादन ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): मेक्जिमम लोड ८ मेगावाट; मतलब ८० हजार किलोवाट। कभी कभी खराब भी हो जाता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि गैस टर्बाइन से जितनी बिजली दे रहे हैं वह सारी की सारी डी. सी. एम. को दी जा रही है ?

श्री हरिश्चंद्र : वह गलत है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आरम्भ में स्टार्ट किया था, इसका अनुमान किया था क्या ?

श्री हरिश्चंद्र : मैं अर्ज करूं कि सारा इन्टीग्रेटेड ग्रिड है। चम्बल से जो बिजली उत्पन्न होती है वह, जयपुर से टर्बाइन के द्वारा भेजी जाती है वह, कोटा में थर्मल स्टेशन है वह और गैस टर्बाइन; इन सबका एक ग्रिड है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कोस्ट बढ़ी है उसको ध्यान में रख कर डी. सी. एम. को तीन पैसे युनिट पर बिजली देते हैं, उसकी रेट को बढ़ाने का विचार किया है।

श्री हरिश्चन्द्र : सरकार के यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि गैस टर्बाइन जो आया है उसका क्रेक हो गया था, यह जो ऑटोमेटिक चलना चाहिये मेन व्हील पर चल रहा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : ऑटोमेटिक चल रहा है। क्रेक हो गया था उस क्रेक को रिपेयर भी कर दिया गया, लेकिन रिपेयर से ठीक नहीं हुआ। बेंगलौर से एयरक्राफ्ट मंगाया गया था उससे काम ले रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसके क्रेक हो जाने के कारण बेंगलौर से जो मंगाया है उससे एक्स्ट्रा एक्सपेन्सेज क्या होंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह कहना बड़ा मुश्किल है। इसकी कीमत क्या है, वह तो मेरे पास नहीं है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : इससे जो लॉस होगा क्या वह लॉस डी० सी० एम० को जो बिजली कन्सेशन रेट पर दी जाती है उसको बढ़ाकर उससे मीट आउट किया जायगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी नहीं।

श्री अब्दुलजब्बार : जनता से तो पैसा बढ़ाकर लिया जाता है और इतनी बड़ी फैक्टरी को रियायत दर पर बिजली दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत !

नागौर जिले में जिप्सम की खान

२६२. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुंडावत (भीम) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

१. क्या यह सही है कि नागौर जिले में गांव मांगलोद में जिप्सम की खान है जिसमें से राज्य सरकार द्वारा जिप्सम निकाली जा रही है ?

२. क्या यह सही है कि जिप्सम निकालने का यह सार्वजनिक उद्योग में प्रथम प्रयोग है ?

३. क्या यह सही है कि यहां से निकले हुए जिप्सम की कीमत वित्त विभाग द्वारा साढ़े सात रुपये प्रति टन रखी गई है ?

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

४. क्या यह सही है कि इतना ऊंचा भाव रखने के कारण निजी उद्योग में निकाली जाने वाली जिप्सम की प्रतियोगिता में यह सफल नहीं रह सकेगी ?

५. क्या यह सही है कि रेल्वे स्टेशन से खान दूर होने के कारण खरीददारों को यह और भी मंहगी पड़ती है ?

६. क्या यह सही है कि खनिज विभाग ने वित्त विभाग को इसकी कीमत साढ़े पांच रुपये रखने के लिए कई बार निवेदन किया ?

७. यदि हां, तो खनिज विभाग द्वारा प्रस्तावित साढ़े पांच रुपये का भाव सरकार क्यों नहीं मुकर्रर करती है ?

खनिज मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : जी हां।

२. जी हां।

३. जी हां। यह कीमत ३–४–६४ को निर्धारित की गयी थी और उसे अब रिवाइज करने का प्रश्न सरकार के विचारा-है।

४. यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन धीन है।

५. आशा है कि कीमत रिवाइज्ड हो जाने पर यह कठिनाई दूर हो जायगी।

६. सरकार के विचाराधीन है।

७. सरकार के विचाराधीन है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : विचाराधीन कितनी मुद्दत से चल रहा है और कब तक निर्णय हो जायगा ?

श्री हरिदेव जोशी : जब तक अन्तिम निर्णय न हो जाय।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : क्या इससे राजस्थान सरकार को नुकसान उठाना पड़ रहा है ?

श्री हरिदेव जोशी : नुकसान कुछ नहीं है।

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) : अब तक इसमें कितने लेबरर्स काम कर रहे हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : लेबरर्स की संख्या मेरे पास नहीं है।

श्री गंगासिंह राठौड़ : मुझे जहां तक मालूम है इसमें पचास-साठ आदमी काम करते हैं; फेमीन की कन्डीशन को देखते हुए वहां लेबरर्स की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ?

श्री हरिदेव जोशी : इसके बारे में 'हां' या 'ना' कुछ नहीं कह सकता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : आपके भाव ज्यादा होने की वजह से प्रतियोगिता में जिप्सम महंगा पड़ता है। राज्य सरकार यदि भाव रिवाइज कर देती तो यह उद्योग ज्यादा मुस्तैदी से चल सकता था।

श्री हरिदेव जोशी : रिवाइज किया जाना चाहिए, यह माइन्स डिपार्टमेंट मानता है और फाइनेन्स डिपार्टमेंट को लिखा है।

Page No. 13

(श्री हरिदेव जोशी)
इसी कारण सरकार को नुकसान हो रहा है, यह स्थिति सही नहीं है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : यह विचाराधीन कब से और कितने अर्से से चल रहा है ?

श्री हरिदेव जोशी : विचाराधीन कब से है और कब लिखा गया, यह तो मेरे पास नहीं हैं । लगभग दो-तीन महीने हुए हमने इस बारे में चर्चा करके फाइनेलाइज़ इसको कर दिया है । गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया है कि माइन्स डिपार्टमेंट इसकी प्राइस वगैरह तय करने में डिप्टी फाइनेन्स सेक्रेटरी एज़ एडवाइज़र के रूप में कार्य करेंगे ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : इसमें समस्या यह है कि राजस्थान सरकार यह जो उद्योग चला रही है वह व्यवसायिक बुद्धि से न चलाकर रेड टेपिज्म के आधार पर चलाती है । व्यवसायिक बुद्धि से चलाया जाता है तो यह दिक्कत नहीं हो सकती ?

श्री हरिदेव जोशी : प्राइस तय करने के लिए इसमें देरी न हो इस चीज़ को सरकार ने विचार किया और इसके लिए कागजात बार-बार फाइनेन्स डिपार्टमेंट में न भेजे जायं इसलिए मन्त्रि-मण्डल ने यह निर्णय लिया है कि डिप्टी सेक्रेटरी, फाइनेन्स एडवाइज़र के तौर पर कार्य करेंगे । अगर उसके बाद भी डिफरेन्स ऑफ ओपीनियन हो तो वे कागजात फाइनेन्स मिनिस्टर आदि तक जा सकते हैं । अब मैं समझता हूं, व्यवसाय के तौर पर कार्य होने लग जायगा ।

श्री गंगासिंह राठौड़ : सरकार को इससे क्या आमदनी हो रही है ?

श्री हरिदेव जोशी : अभी तक लगभग ४।। हजार टन जिप्सम बेच चुके हैं, २४०० टन पड़ा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : यह इतना उत्पादन कितने समय में हुआ, कितने महीनों में ?

श्री हरिदेव जोशी : इसकी अवधि मेरे पास में नहीं है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : प्रति-वर्ष इससे कितनी आमदनी होती है ?

श्री हरिदेव जोशी : अभी तक तो इसको एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : ग्राम मांगरोल में जो जिप्सम अवेलेबल है वह कितने एकड़ एरिया के अन्दर है और आपने कितना खनन करना शुरू किया है ?

श्री हरिदेव जोशी : अभी तक बहुत बड़े एरिया को एक्सकेवेट करना शुरू नहीं किया । पिछले मई महीने में ही इसको शुरू किया हुआ समझना चाहिये ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : जिप्सम काफी बड़े एरिया में है, थोड़ी सी जगह में काम शुरू किया जा रहा है ?

श्री हरिदेव जोशी : इसका काफी बड़ा एरिया है जहां हम बल्क सप्लाई के रेट्स तय कर लेना चाहते हैं । बड़ी दिक्कत यह है कि रेलवे स्टेशन के ऊपर प्लॉट्स वगैरह अवेलेबिल नहीं हैं । फर्टीलाइजर फेक्ट्री के लिये और एफ० सी० सी० ने पहले ही वहां प्लॉट्स ले लिये हैं । पिट्स माउथ के रेट्स तय करना और बल्क सप्लाई के रेट्स तय करने के बाद

(श्री हरिदेव जोशी)
यह काम काफी अधिक तेजी से चल सकता है। जहां तक नुकसान का सवाल है, इसमें एक पैसा भी नुकसान नहीं हुआ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : इसमें राष्ट्रीय धन के खोजने का सवाल है; जो प्रचुर मात्रा में भरा पड़ा है, यह राष्ट्रीय धन का नुकसान है ?

श्री हरिदेव जोशी : आपकी इस भावना की कद्र करता हूं, मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। हमारी भावना के अनुकूल कार्य में तेजी हो जाय, यह मुमकिन नहीं हुआ करता है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : इसका डेली प्रोडक्शन कितना है ?

श्री हरिदेव जोशी : अभी हमने इसको इतनी तेजी से शुरू नहीं किया है। ढाई हजार टन माल पड़ा हुआ है, मगर जहां तक प्रोडक्शन का सवाल है वह रेट तय हो जाने के बाद काफी बढ़ सकता है।

श्री गंगासिंह राठौड़ : इस खान से जो माल निकला है वह आसपास के जो लोग हैं जिनके मकान इसी खड्डी बने हुए हैं उन लोगों को खड्डी मिलेगी ? अगर हां, तो कितने अनुपात में ?

श्री हरिदेव जोशी : अभी तक जो उत्पादन हुआ है वह वहीं के लोगों को बेचा है। साढ़े चार हजार टन जो बताया वह लोकल सप्लाई है।

प्रश्न संख्या २६३

श्री अध्यक्ष : श्री दलपतसिंह !
(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

वैद्य श्री गोविन्दसहाय !

दौसा-गंगापुर रूट पर चलने वाली बसें

२६४. **वैद्य श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

१. क्या यह सही है कि दौसा-गंगापुर जो बसें चलती हैं उनकी हालत खराब है ? यदि हां, तो उन्हें क्यों नहीं बन्द किया जाता है ?

२. ये बसें कितनी हैं व कौन से मॉडल की हैं ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) :
१. बसों के खराब होने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

२. कुल बसें ३३ हैं। सूची मय उनके मॉडल के सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : क्या कुछ दिन पहले सरकार ने इस तरह के आदेश जारी किये है कि पुराने मॉडल की बसों को केन्सल करके निश्चित् समय में ६० मॉडल की बसें शुरू की जायं ?

श्री भीमसिंह : ऐसा है कि जैसे-जैसे पुराने मॉडल की गाड़ियां हो जाती है जब वे रिन्यूअल को आती हैं तो उनको रिन्यूअल न किया जाकर उनको नये मॉडल के लिए ऑर्डर दिया जाता है। इस माफिक ३३ में से ११ रिप्लेस

(श्री भीमसिंह)
हो चुकी हैं। बाकी जब रिन्यूअल के लिए आयेंगी तो उनको भी रिप्लेस करने के लिए कहा जायेगा।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : जो लिस्ट आपने दी है उसमें ३२ की, ४१ की और ४५ की मॉडल की भी बसें हैं; क्या वे सब ठीक हालत में हैं?

श्री भीमसिंह : रिन्यूअल जब किया जाता है तब सारी चीजों को देख कर उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। जो गाड़ी हमें बेकार मालूम होती है उसको रिप्लेस करने के लिये कह देते हैं। हरएक रोड्स पर यह मुनस्सर है कि वहां किस-किस मॉडल की बसेज़ चल सकती हैं। जब रिन्यूअल के लिये आर० टी० ए० के पास जाते हैं तो वह खराब कन्डीशन देख कर उसको रिप्लेस करने का ऑर्डर देता है, नहीं तो परमिट केन्सल कर दिया जाता है, उसके लिये दो-तीन महीने का समय दिया जाता है।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : ये बसेज इस प्रकार की हैं कि जो चलते चलते रास्ते में खराब हो जाती हैं। इनसे सफर करने में समय भी ज्यादा लगता है; दौसा से गंगापुर ५१ माइल हैं, जिसमें साढ़े चार घंटे लग जाते हैं। आये दिन बसेज रास्ते में खड़ी दिखाई देती हैं। उसमें ३२, ३७ और ४२ के मॉडल की बसेज हैं। इनकी जगह ६० की मॉडल की बसेज़ रिप्लेस करने के लिये ऑर्डर दिया जाय, अन्यथा इनका परमिट केन्सिल किया जाय।

श्री भीमसिंह : ये कैंसिल तब होंगी जब परमिट रिन्यूअल की स्टेज पर आवेगा। इसमें दो राय नहीं रखता कि जो गाड़ी फिट नहीं हो वह सड़क पर चले। पुराना मोडल होते हुए भी अगर वह गाड़ी ग्रॉक रूप नहीं है, रंग-रोगन ठीक है, ब्रेक ठीक हैं, तो फिटनेस सार्टीफिकेट देना पड़ता है। अगर इसके बावजूद भी कायदे के खिलाफ चीज चलेगी तो फौरन दुरुस्ती की जावेगी, वर्ना रूल्स के अन्दर है तो कुछ नहीं हो सकेगा।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : यह फिटनेस सर्टीफिकेट लेने के लिए कब आते हैं?

श्री भीमसिंह : छः-छः महीने के बाद।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : रिन्यूअल के लिये?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य समझे नहीं; रिन्यूअल और चीज है और परमिट और चीज है। परमिट की मियाद खत्म होगी तो लेटेस्ट सन् के मोडल का नियम लागू करेंगे और बाध्य करेंगे उसे कि नई मोडल की मोटर लगाओ।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : फिटनेस सर्टीफिकेट फिर क्यों दे दिया जाता है?

श्री भीमसिंह : वह तो नियम के अन्तर्गत देना पड़ेगा। जयपुर की सड़कों पर मैंने २२ के मोडल की गाड़ी चलती देखी है। अब वे क्या करते हैं, इन्जन को ओवरऑल करा लेते हैं, इन्जन चलता है। फिटनेस का मतलब सड़क पर चलने के जो नियम हैं उनके अन्तर्गत वह फिट है। इसके कुछ नियम होते हैं कि ब्रेक ठीक होना चाहिए, गाडी चालू हालत में होनी चाहिए, रंग-रोगन पोलिश ठीक होना चाहिये; तो इस तरह के सर्टेन पोइन्ट्स होते हैं जिनको चैक किया जाता है। इसमें मोडल, किस सन् का है इससे मतलब

(श्री भीमसिंह)

नहीं होता, गाड़ी चालू हालत में, अच्छी हालत में रंग-रोगन की दृष्टि से, पोलिश की दृष्टि से और सरटन पोइन्ट्स की दृष्टि से वह फिट उतरनी चाहिये । अब इसमें अगर लेटेस्ट मोडल की भी गाड़ी है, पर उसकी वर्त्ती ठीक नहीं, इन्जन ठीक नहीं चलता, रंग-रोगन पोलिश आदि और ब्रेक आदि ठीक नहीं हैं तो हम उसको भी बन्द कर देते हैं, उसे भी फिटनेस सर्टीफिकेट नहीं मिल सकता; आप तो पुराने मोडल की बात कहते हैं, इस दृष्टि से अगर फिट नहीं है तो लेटेस्ट मोडल की गाड़ी भी अनफिट हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज ।

कृषि व उद्योग को बिजली की सप्लाई

२६५. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि फालना स्थित पॉवर हाउस की क्षमता कम होने से व मशीनरी पुरानी होने से कृषि व उद्योग को आवश्यकतानुसार बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है, और इससे उत्पादन कार्यक्रम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है ?

(२) क्या राज्य सरकार इस विद्युत् गृह की क्षमता बढ़ाने का निकट भविष्य में कोई विचार रखती है, ताकि उत्पादन कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा सके ?

(३) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार अब बिजली सप्लाई के नये कनेक्शन देने में कृषि कार्य हेतु काश्तकारों को प्राथमिकता देने का विचार रखती है ?

उपमंत्री विद्युत् (श्री चन्दनमल वैद) :

(१) क्षमता कम है ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां । इस समय भी कृषि हेतु बिजली लेने वाले काश्तकारों को प्राथमिकता दी जा रही है ।

श्री मोहनराज : जिन किसानों ने इस तरह से प्रार्थना-पत्र दिये हैं क्या उनको प्राथमिकता दी जावेगी ?

श्री चन्दनमल वैद : अवश्य दी जावेगी ।

श्री मोहनराज : क्या सरकार ने ऐसे आदेश दे दिए हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : ऐसे आदेश हैं ।

श्री मोहनराज : कब जारी किये गये हैं और जो इन्जीनियर मौके पर हैं उन तक पहुंचे भी हैं या नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद : बहुत दिनों पहिले दिये जा चुके हैं और अगर आपको संतोष न हो तो इलेक्ट्रिकसिटी बोर्ड को और कह देंगे कि ऐसे आदेश उन तक न पहुंचे हों तो अब फिर से जारी कर दें और उन तक पहुंचा दें ।

प्रश्न संख्या २६६

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल !

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री हरलाल !

प्रतापगढ़–बांसवाड़ा सड़क योजना

२६७. **श्री हरलाल मीणा :** (प्रतापगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा सड़क बनाने की योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना से चल रही है ? यदि हां, तो यह सड़क अब तक कितनी बन चुकी है ?

(२) क्या यह सही है कि गत साल से इस सड़क पर कोई काम नहीं हुआ है और सड़क काफी खराब हो जाने से इस पर मोटर गाड़ियां तक चलना बन्द है । यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ है ?

(३) क्या यह सही है कि इस सड़क के नहीं बनने से प्रतापगढ़ की तरफ बांसवाड़ा के मुसाफिरों को दाहोद की तरफ होकर आना-जाना पड़ता है ? यदि हां, तो इस सड़क को सरकार जल्दी से जल्दी कब तक बनावेगी ?

(४) क्या यह सही है कि यह सड़क बांसवाड़ा से पीपलखूंट तक बन चुकी है ? अगर हां, तो प्रतापगढ़ से पीपलखूंट तक कब तक मिलाई जायगी ?

(५) क्या यह भी सत्य है कि प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के बीच का पूरा इलाका आदिवासी लोगों का है ? यदि हां, तो क्या इस अकाल के समय मे इस सड़क का काम चालू किया जायेगा ।

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री परसराम मदेरणा) : प्रतापगढ़ बांसवाड़ा का निर्माण-कार्य चित्तौड़ जिले में द्वितीय योजना मे तथा बांसवाड़ा जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत हुआ था और बांसवाड़ा जिले में २४ मील लम्बी सड़क का निर्माण हुआ है ।

(२) यह सत्य नहीं है ।

(३) यात्रियों का आवागमन प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा फेयरवेदर रोड पर चलता रहता है ।

(४) बांसवाड़ा से २४ मील तक सड़क बन चुकी है । बाकी कार्य चौथी योजना के अन्त तक पूर्ण होने की आशा है ।

(५) यह कार्य अकाल कार्य में स्वीकृत नहीं है ।

श्री हरलाल मीणा : क्या चौमासे में इस तरफ गाड़ी चलती है ?

श्री परसराम मदेरणा : फेयर वेदर रोड है, बरसात मे बन्द हो भी सकती है ।

श्री अध्यक्ष : फेयरवेदर होती है, तब चलती है ।

श्री रावतराम ।

विभिन्न कॉलेजों के होस्टलों में अनुसूचित जाति के छात्रों के स्थान

२६८. **श्री रावतराम** (सादूलपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों, इन्जीनियरिंग कॉलेजों, एग्रीकल्चर कॉलेजों व सैनिक कॉलेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को सम्बन्धित कॉलेज होस्टल में रहने का पूरा खर्चा सरकार नहीं देती और सिर्फ निश्चित छात्रवृत्ति ही देती है ?

(श्री रावतराम)

(२) क्या यह सही है कि उक्त छात्र-वृत्ति बहुत कम होती है और इतने छात्र कॉलेज होस्टल में रह कर अध्ययन नहीं कर सकते ? यदि हां, तो सरकार ने इसके लिए क्या विचार किया है ?

(३) क्या यह सही है कि इन छात्रों को अनुसूचित जाति के छात्रावासों में मजबूरन रहना पड़ता है, जहां छोटी क्लासों के छात्रों के साथ रहने से उन्हें अध्ययन में कठिनाई पैदा होती है और इससे अनुसूचित जाति के छात्र प्राविधिक शिक्षा में पिछड़ते जा रहे है ?

(४) क्या यह सही है कि सरकार ने दिनांक २८-९-६५ को विधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि प्राविधिक शिक्षा के कॉलेजों के होस्टलों में उक्त जाति के छात्रों के लिए स्थान सुरक्षित किये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध मे विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

समाज कल्याण मंत्री (**श्री अमृतलाल यादव**) : (१) जी हां।

(२) जी हां। केन्द्रीय सरकार को लिखा गया है।

(३) अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के प्राविधिक तथा अन्य उच्च कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत दर के अनुसार समाज कल्याण के मद से शिक्षा विभाग द्वारा पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त विभागीय छात्रावासों में भी उन छात्रों को प्रवेश देते समय प्राथमिकता दी जाती है। इन छात्रावासों में मजबूरन रहने का उनका प्रश्न नहीं है।

(४) शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सभी छात्रावासों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के छात्रों के लिये पांच प्रतिशत स्थान सुरक्षित है।

श्री रावतराम : यह प्रश्न मैंने पूछा उसका मतलब आपके उत्तर से कुछ नहीं निकला।

मैं बराबर तीन साल से पूछ रहा हूं और सरकार बराबर यही उत्तर दोहराती रही है कि हम इसके लिये प्रयत्नशील हैं, लिख रहे हैं। मेरा पूछने का मतलब यह है कि मेडिकल कॉलेज के छात्र और दूसरे इन्जीनियरिंग कॉलेज के छात्र इन होस्टलों में रह कर अध्ययन कर सकते हैं क्या ? और फिर इसके लिये जो छात्रवृत्ति भारत सरकार देती है वह इतनी नाकाफी है कि चार महीने भी वे उन होस्टलों में रह कर नहीं पढ़ सकते।

फिर अगर आपके होस्टलों में रह कर पढ़ाई करें तो एक तो वे पड़ते हैं पांच-पांच मील दूर। फिर जहां चौथी क्लास के लड़के भी पढ़ते हों उन जगहों पर एक एक कमरे में बीस बीस लड़के रहते हों, वहां कैसे मन लगाकर पढ़ाई की जा सकती है ? आप इसके लिए बराबर तीन सालों से कोशिश कर भी रहे है। एडवाइजरी कमेटी में हमें आप यही बताते भी हैं, हमारे से सलाह भी ले ली जाती है। हम आते हैं तो हमें भत्ता देकर विदा भी कर दिया जाता है; हमें भत्ता नहीं चाहिये, आप हमें भत्ता न दें, हमारा भत्ता उनको दे दें, पर आपको इस पर शीघ्रता से डिसीजन लेना चाहिये। अगर आप उनको

(श्री रावतराम)
पढ़ाना चाहते हैं तो पूरी सहूलियतें दीजिये, या फिर यों ही झांसा-पट्टी देना चाहो तो अलग बात है ।

श्री अमृतलाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे निवेदन किया कि पोस्ट मैट्रीकुलेट छात्रों को भारत सरकार छात्रवृत्ति देती है । मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि उनको कुछ अधिक सहूलियतें मिलनी चाहिये छात्र-वृत्ति में वृद्धि होनी चाहिये; इसके लिये बोर्ड ने भी माना है और हमने भारत सरकार को लिखा भी है कि यह रकम कम पड़ती है तो या तो आप बढ़ावें या फिर हमें इजाजत दें । जितना कम पड़ता हो उतना हम अपनी तरफ से दे दें ।

श्री रावतराम : उनका उत्तर आया है आपके पास, ६४ का पत्र है । आपने जो पत्र लिखा है, जिसकी कॉपी मेरे पास भेजी है, मैं उसे पढ़ भी नहीं सकता, खैर !

श्री अमृतलाल यादव : उम्मीद है भारत सरकार मान लेगी ।

श्री अध्यक्ष : यह भारत सरकार की योजना है या राज्य सरकार की है ?

श्री अमृतलाल यादव : मैट्रिक के ऊपर के छात्रों को भारत सरकार ही छात्रवृत्ति देती है, और मैट्रिक के नीचे वालों को स्टेट सरकार । तो इसके लिये हमने भारत सरकार को लिखा है ।

श्री अध्यक्ष : इसमें कोई वैधानिक रुकावट है क्या कि आप मैट्रिक के ऊपर वालों को नहीं दे सकते ?

श्री अमृतलाल यादव : अकाउन्ट्स के नियमों का सवाल है । एक विद्यार्थी दो जगह की स्कॉलरशिपों से लाभ नहीं उठा सकता । हमने कहा कि लाभ उठाने का इसमें सवाल नहीं है, कम पड़ता है । तो या तो जो कम पड़ता है उतना आप दीजिये, या फिर हमें इजाजत दीजिये कि हम अपने पास से दे दें ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि भारत सरकार द्वारा इन छात्रों को छात्रवृत्ति देने के नियम बने हुए हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : जी हां । नियम बने हुए हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : रूल्स के अनुसार कोई भी विद्यार्थी जो कि छात्रवृत्ति लेना चाहता है क्या वह केन्द्रीय सरकार को सीधे लिखता है या उसको राज्य सरकार की मार्फत लिखना पड़ता है ?

श्री अमृतलाल यादव : राजस्थान सरकार के मार्फत लिखना पड़ता है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तो क्या राज्य सरकार के पास इस प्रकार से उन विद्यार्थियों ने कोई प्रार्थना-पत्र नहीं भेजे कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को इसके लिए लिखे ?

श्री अध्यक्ष : उससे तो ज्यादा कर चुके हैं । वे स्वयं लिख चुके हैं भारत सरकार को ।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी कि यह पृथकतावाद जिसको मैं कम्युनेलिज्म कहता हूं, जो आम छात्रावास और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रावासों को अलग अलग रखती है, यह क्या [illegible]

(श्री अब्दुलजब्बार)
छुआछूत को मिटाने के लिए इन दोनों तरह के छात्रावासों को एक ही बनाया जाये, क्या सरकार इसे जरूरी नहीं समझती ?

वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : अभी कुछ समय पहले केलादेवी में हरिजन सम्मेलन हुआ था, वहां पर आपने बड़े जोरदार शब्दों में कहा था कि हमारे छात्रों के साथ भेदभाव होता है और हमारी सरकार उस पर विचार नहीं करती है और अब आप मंत्री बन गये हैं और मंत्री बनने के बाद अब आप कहने लग गए हैं कि भारत सरकार विचार कर रही है । तो आपने गत वर्ष कहा था कि हमारे छात्रों के साथ बड़ा भेदभाव होता है, उनके साथ अन्याय होता है और सरकार हमारे साथ ज्यादती करती है । आपने यह सब वहां हरिजन सम्मेलन हुआ था जिसमें हमने हजारों रुपया खर्च किया था उस समय आपने कहा था और आज कुर्सी पर आने के बाद में आप इस तरह का जवाब देते हैं ! आप फिर यहां बैठ कर क्या करते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्ष, मैं तो अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रहा हूं । अब माननीय सदस्य का कितना सहयोग मिलेगा और माननीय सदस्य के अन्य समाज के लोगों का कितना सहयोग मिलेगा, उस पर मेरी सफलता निर्भर करेगी और जहां तक इसका सवाल है मैं हाउस के सामने कमिटमेन्ट करता हूं कि इसको मैं करवा कर लाऊंगा ।

वैद्य श्री गोविन्द सहाय : मेरा निवेदन यह है कि केलादेवी में हमने हरिजन सम्मेलन किया था, उसमें आप भी आये थे और हजारों रुपया खर्च किया था और उसके बाद आज आप मंत्रि-पद पर आ गए तो इस तरह से कहने लग गए.........

श्री अमृतलाल यादव : यह आप सहयोग देंगे कि जो ब्राह्मण हरिजनों को और दूसरे लोगों को कुओं पर नहीं आने देते हैं उनको लाने में आप सहयोग देंगे ?

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : मंत्री महोदय ने कहा उसको मैं मानता हूं । मेरा निजी कुआं है और उस पर मैं सबको आने देता हूं । मैं दूसरों के लिए क्या कहूं, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि गत वर्ष बड़ी लम्बी चौड़ी पेम्फलेटबाजी की और यही सब आपने कहा कि हमारे लोगों के साथ सरकार का अच्छा व्यवहार नहीं है, अन्याय है, ज्यादती है और मंत्री बनने के बाद आज वे खुद इस तरह का जवाब देते हैं !

श्री अमृतलाल यादव : मंत्री बनने के बाद ही कहता हूं कि मैं इसको करवाऊंगा ।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : गत वर्ष सरकार ने भी जवाब दिया है और आपसे पहले जो इस विभाग के मंत्री महोदय थे उन्होंने भी यही जवाब दिया था ।

श्री अमृतलाल यादव : मंत्री होने से पहले मैंने क्या कहा है और मंत्री होने के बाद कहां उससे बैक-आउट हुआ हूं, यह बतायें ?

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : आपने गत वर्ष मांग की थी कि हरिजन-छात्रों के साथ अन्याय होता है, ज्यादती होती है; होस्टल की सैंक्शन्स नहीं मिलती हैं और सेन्टर के मिनिस्टर आये

(वैद्य श्री गोविन्दसहाय)
थे, उनके सामने भी कहा और मैं पूछना चाहता हूं कि आपने मंत्री बनने के बाद कितने अधिकार दिलाये ?

श्री अमृतलाल यादव : मंत्री होने के बाद जहां तक अधिकार दिलाने की बात है मैं रात और दिन कोशिश करता हूं, लेकिन उसके अन्दर सफलता ग्राम समाज के साथ मिलने की होती है।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : समाज का कोई दोष नहीं है। उस पर तो जो आप नियम और व्यवस्था लागू कर देंगे, उसी के अनुसार समाज चलेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : पहले भी यहां थे तब भी कहते थे। पब्लिक ओपीनियन से होता है।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : मंत्री बनने से पहले आप सरकार की आलोचना करते थे, अब खुद के छात्रों को छात्रवृत्ति मिल गई और दूसरों को नसीहत देने लग गए कि मैंने भारत सरकार को लिख दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने मंत्री बनने के बाद क्या प्रयत्न किए ? आपने नयी क्या कोशिश की ?

श्री अमृतलाल यादव : मैं पूरे-पूरे प्रयत्न कर रहा हूं और पहले भी कर रहा था।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा रामगढ़) : १९६४ से आज तक सेन्टर से उत्तर नहीं आया। दूसरी बात यह है कि हमने कई बार कहा है कि छात्रावास जितने भी हैं वे सब एक जगह हों तो इसके बारे में जो भी आपको कहते हैं उसके बारे में आप कान बन्द करके, उत्तर नहीं देकर चुपचाप बैठ जाते हैं। तीसरी बात·······

श्री अमृतलाल यादव : दूसरी बात क्या है ? कोई प्रश्न आपका साफ भी तो हो।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : पहले सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप (श्री डूंगाराम) पहली बात से शुरू करें।

श्री अमृतलाल यादव : आप मेहरबानी करके एक-एक बात कहें।

श्री अध्यक्ष : आप (श्री अमृतलाल यादव) इतने उतावले क्यों हो रहे हैं ?

श्री डूंगाराम राजोरिया : आपने १९६४ में पत्र दिया था केन्द्रीय सरकार को और उसका उत्तर क्या मिला और उस बीच में आपने क्या क्या कार्यवाही की, पहले इसका उत्तर दीजिए।

श्री अमृतलाल यादव : किस बात का ? १९६४ में पत्र लिखा ? मांगों से ज्यादा पैसे बढ़ाने का। इसका पत्र ६४ या ६५ में लिखा, लेकिन जब मैं आपको यह बात कह रहा हूं कि इसकी कोशिश कर रहा हूं और मैंने हाउस में कमिटमेन्ट किया है कि इसको करवाकर लाऊंगा तो इसके बाद में आप क्या चाहते है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न स्पष्ट है कि १९६४ के बाद में सरकार की तरफ से क्या प्रयत्न किये गये, कृपया संक्षेप में बतायें ?

श्री अमृतलाल यादव : इसके लिए प्रयत्न एक दिन में नहीं हो ते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपने पत्र तो लिखा ही नहीं होगा। प्रयत्न कर रहे हैं, आपने कहा, तो ६४ में जो पत्र लिखा उसके बाद में आप वहां पर गए या क्या किया, कुछ सदन को संतोष तो करायें।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन-सु.) : अपने लड़कों को सेंट जेवियर में भेज सकते हैं और दूसरों का हित क्या कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय मैंने भी कुछ कहा है उसका भी तो उत्तर दें।

वैद्य श्री गोविन्द सहाय : कोई उत्तर ही नहीं है तो क्या दें !

श्री अमृतलाल यादव : उन्होंने पत्र की बात कही; मैंने कहा कि वह पत्र लिखा गया उसकी कॉपी मेरे पास है; लेकिन समय ज्यादा नहीं होने की वजह से इसको पढ़ कर सुनाया नहीं और आखिर में मैंने कहा कि गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया से, जब मैंने २ जून से चार्ज लिया है तब से मैं चार-पांच बार होकर आया हूं और उनको इस बात के लिए राजी करके आया हूं और करीब-करीब यह तय हो गया है और यह बात उन्होंने मान ली है और वह देंगे।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आम छात्रावासों में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लड़कों के लिए सुरक्षित स्थान कितने रखे हैं, उसके लिए क्या कहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : ५ परसेन्ट स्थान सुरक्षित हैं।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : ५ परसेन्ट तो पहले से ही सुरक्षित हैं; मंत्री बनने के बाद क्या किया ? अध्यक्ष महोदय ने यही कहा कि ६४ के बाद क्या कार्यवाही हुई, इसका भी जवाब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जोधसिंह।

उदयपुर गवर्नमेन्ट प्रेस में प्रूफ रीडर का रिक्त स्थान

२६६. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : क्या मंत्री, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर गवर्नमेन्ट प्रेस में दो साल से प्रूफ रीडर की जगह खाली पड़ी है ?

(२) उसके एवेन्स्ट में कौन कार्य करते हैं?

(३) जो कार्य करते हैं वे उदयपुर प्रेस के अधिकारी के कौन लगते हैं ?

(४) उनके कार्य पर जाने का क्या समय है ?

(५) इसी प्रकार दूसरे सुपरवाइजर के कितने रिश्तेदार हैं ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

मंत्री, मुद्रण एवं लेखन सामग्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) जी हां, प्रूफ रीडर, द्वितीय श्रेणी, के दो पद रिक्त हैं।

(२) इन पदों पर समय समय पर कार्य की अधिकता को दृष्टि में रखते हुए जब भी आवश्यकता हुई अस्थाई रूप से निम्नलिखित व्यक्तियों को लगाया गया :

(१) श्री शान्तिलाल १-४-६४ से ५-६-६४ तक।

(श्री मथुरादास माथुर)

(२) श्री सूरजमल १०-४-६४ से ३०-४-६४ तक।

इनमें से श्री सूरजमल के चले जाने पर श्री कैलाश नारायण को १५-६-६४ को रखा गया, जो अभी तक कार्य कर रहे हैं। श्री शान्तिलाल के चले जाने पर श्री कन्हैयालाल पाटीदार को २४-१०-६४ को रखा गया जो यहां ७-११-६४ तक रहे। उनके चले जाने पर श्री लोकेन्द्र को रखा गया जो अभी तक कार्य कर रहे हैं।

(३) श्री कैलाश नारायण अधीक्षक के साले हैं तथा श्री लोकेन्द्र दूर के रिश्ते में भाई हैं।

(४) कार्य पर जाने का समय नियमित है। राज्य सरकार के कार्य को ध्यान में रखते हुए कुछ समय से १ व्यक्ति का समय २ बजे मध्याह्न पश्चात् से रात्रि ६ बजे तक का कर दिया गया है।

(५) (१) श्री पृथ्वीसिंह मुख्याकार्यदेशक का भानजा श्री बिजयसिंह, मुद्रक द्वितीय श्रेणी के पद पर दिनांक १-५-६४ से कार्य कर रहे हैं।

(२) श्री गोबिन्ददास मुद्रण कार्यदेशन इनका पुत्र श्री भंवरलाल वैष्णव दिनांक ७-८-५६ से व भाई श्री रघुवीरदास दिनांक १-१०-४६ से क्रमशः मुद्रक द्वितीय व प्रथम श्रेणी के पद पर कार्य कर रहे हैं।

(३) श्री मोहम्मद हुसैन, बन्धन कार्यदेशन के पुत्र श्री अयूबअली दिनांक ६-७-६४ से बन्धक द्वितीय श्रेणी तथा भाई श्री सज्जाद हुसैन दिनांक १०-२-५१ से बन्धक प्रथम श्रेणी के पद पर कार्य कर रहे हैं।

श्री जोधसिंह चौहान : उनके रिश्तेदार श्री कैलाशनाथ को रखा गया, तो उनकी एज क्या है?

श्री मथुरादास माथुर : एज तो बालिग होगी तभी रखा गया है। वर्ना एज लिखी नहीं है।

श्री जोधसिंह चौहान : वह अण्डर एज है और विद्यार्थी है, फिर भी प्रवेश के तौर पर लिया गया!

श्री मथुरादास माथुर : अगर अण्डर एज है तो मैं जांच करूंगा।

श्री जोधसिंह चौहान : क्या इसकी छानबीन करके पता लगायेंगे?

श्री मथुरादास माथुर : जांच का मतलब ही यही है कि छानबीन करके पता लगायेंगे।

श्री जोधसिंह चौहान : आपने कहा है कि रिक्त स्थान है....

श्री मथुरादास माथुर : पब्लिक सर्विस कमीशन को लिख दिया गया है। वह नोटिफिकेशन निकाल करके भर्ती करते हैं।

श्री जोधसिंह चौहान : पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा है तो बीच में कितना समय गुजर गया?

श्री मथुरादास माथुर : करीब दो साल से ज्यादा हो गया।

श्री अध्यक्ष : पब्लिक सर्विस कमीशन देरी करता है तो टेम्पोरेरी नोटिस निकाल कर अपोइन्टमेन्ट किया जा सकता है।

श्री मथुरादास माथुर : यह तो ठीक है। डेली वेजेज् पर रखा है।

श्री अध्यक्ष : पब्लिक सर्विस कमिशन की पव्यू में है ?

श्री मथुरादास माथुर : अब हमने इनको डेली वेजेज़ पर रख लिया है।

श्री अध्यक्ष : तभी तो शिकायतें होती हैं। उसका भी नोटिस निकाल कर टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट कर सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : ऐसा सुपरिन्टेन्डेन्ट को लिख देंगे।

श्री अध्यक्ष : नियम है, साहब।

श्री जोधसिंह चौहान : क्या यह सही है कि वहां की इस प्रकार की व्यवस्था से प्रेस के प्रोडक्शन में कमी हो रही है, प्रेस के अन्दर पूरा काम नहीं हो रहा है और इसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो रहा है और इससे लॉस हो रहा है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह :

(१२.०० मध्यान्ह)

नगरपालिका चुंगी दर

२७०. **श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां)**: क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार के ध्यान में है कि राजस्थान नगरपालिकाओं की चुंगी दरों में भारी असमानता होने से व्यापारी वर्ग दुखी है ?

(२) क्या समस्त राज्य में सरकार सैल्स टैक्स की भांति नगरपालिका चुंगी दर एक समान लागू नहीं कर सकती ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी नहीं। (२) जी नहीं। हर क्षेत्र की समस्या भिन्न होने से ऐसा नहीं किया गया है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेटर ऑफ पोलिसी का प्रश्न है। ऑक्ट्रोय की रेट अलग अलग होने से बड़ी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, इसलिए सरकार क्यों नहीं सैल्स टैक्स की भांति ऑक्ट्रोय की रेट भी यूनिफॉर्म करती ?

श्री अध्यक्ष : यह बहस का प्रश्न है। इसे आप बहस के द्वारा उठाएं।

श्री मोहरसिंह।

रतनगढ़–बीरमसर राजमार्ग पर निर्माण-कार्य

२७१. **श्री मोहनसिंह (चूरू)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) रतनगढ़ से बीरमसर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ११ पर निर्माण कार्य शुरू हुआ या नहीं ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्य हुआ है तथा उस पर कितना रुपया व्यय हुआ है ?

Page No. 25

(श्री मोहरसिंह)

(२) इस राजमार्ग की लम्बाई क्या होगी और उस पर कितना खर्चा होगा ?

(३) क्या इस निर्माण-कार्य हेतु भूमि अवाप्त की गई है ? यदि हां, तो क्या ऐसी भूमि का मुआवजा किसानों को दे दिया गया है ?

(४) यदि अब तक इस कार्य के लिए भूमि अवाप्त नही की गई है तो क्यों ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री परसराम मदेरणा) : (१) कार्य आरम्भ नही हुआ है ।

(२) रतनगढ़ से बीरमसर सड़क की लम्बाई १२ मील ४ फर्लांग होगी और १७,००,०००) रु० व्यय होने का अनुमान है ।

(३) प्लान खसरा बनवाये जाकर राजस्व विभाग को भेज दिये गये हैं, मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया है ।

(४) यह राजस्व विभाग के विचाराधीन है ।

श्री मोहरसिंह : क्या यह सही है कि वह सड़क अकाल के समय काम करवाने के प्लान में भी थी, फिर भी उस सड़क पर काम नहीं करवाने से मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है और दूसरी योजनाओं के काम भी नहीं होते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, रतनगढ़ से बीरमसर तक जो सड़क बनानी है उसके मोडीफाइड एस्टीमेट्स बनाकर गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के पास में १९-१०-६५ को हमने भेज दिये हैं । गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में अभी तक हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन नहीं आई है ।

श्री मोहरसिंह : सैंक्शन प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री परसराम मदेरणा : हमने कई रिमाइण्डर दिये हैं, हमने मोडीफाइड एस्टीमेट्स बना कर भेज दिये हैं; लेकिन अभी तक सैंक्शन नहीं आई है । फिर भी हमने टेंडर काल कर लिए हैं और टेण्डर की डेट ५-५-६६ है और तब तक हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की सैंक्शन भी आ जावेगी ।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : फिर तो दो महीने बाद वर्षा हो ही जाएगी, फिर काम चलाने से क्या फायदा होगा?

श्री परसराम मदेरणा : हमें गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने लिखा कि इसका मोडीफाइड एस्टीमेट बना कर भेजो, वे हमने भेज दिए; उसके बाद हमने उनको कई रिमाइण्डर भी दिए हैं लेकिन अभी तक उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन नहीं आई है । यह तो नेशनल हाईवे का मामला है। हम जो इसमें कर सकते थे वह यह कर लिया है कि उनकी सैंक्शन आने से पहले ही टेंडर कॉल कर लिए हैं, इस एण्टीसिपेशन में कि सैंक्शन आ जाएगी तब जल्दी ही काम शुरू हो सकेगा ।

श्री मोहरसिंह : आपने कहा कि मोडीफाइड एस्टीमेट भेजे हैं तो आपके पास जो पहले का प्लान था उसके अनुसार काम तो शुरू करवा देते, उसके बाद मोडीफाइड प्लान पर भी सैंक्शन आ जाती ।

श्री परसराम मदेरणा : पहले की सैंक्शन कौनसी है ? इस सड़क के लिए हमने गवर्न-

(श्री परसराम मदेरणा)

मेंट ग्रॉफ इण्डिया से कहा, तो गवर्नमेंट ग्रॉफ इण्डिया ने हमसे कहा कि मोडीफाइड प्लान इस तरह से तैयार करके भेजा कि जिसमें इतनी चौड़ी सड़क हो ग्रौर उसमें इतनी कंकरीट डाली जाये, वगैरह वगैरह । उसके ग्रनुसार हमने मोडीफाइड एस्टीमेट्स बना कर गवर्नमेंट ग्रॉफ इण्डिया के पास भेज दिये हैं ग्रौर उस पर ग्रभी तक उनकी सैंक्शन नहीं ग्राई है ग्रौर जैसा मैंने ग्रापसे कहा कि यह प्लान सत्रह लाख रुपये का है, जिसकी सैंक्शन ग्राने पर काम शुरू होगा, तब तक हमने टेण्डर कॉल कर लिए हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

ब्रिकेटिंग प्लांट की खरीद

२७२. **श्री भीमसेन (लूणकरणसर)** : क्या सार्वजनिक उद्योग संस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि नेवेली लिग्नाइट प्रोजेक्ट से राज्य सरकार ने ब्रिकेटिंग प्लान्ट खरीदने की बात कर ली थी ? ग्रगर हां, तो इस प्लांट को पलाना खान पर लगाने में कितना समय लग जावेगा ?

सार्वजनिक उद्योग संस्थान मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : नेवेली लिग्नाइट प्रोजेक्ट से राज्य सरकार का ब्रिकेटिंग प्लांट प्राप्त करने के बारे में पत्र-व्यवहार चल रहा है । इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है । प्लांट प्राप्त करने के विषय में मामला विचाराधीन है ।

श्री भीमसेन : यह पत्र-व्यवहार कब से चल रहा है ग्रौर इसमें निर्णय लेने में इतना बिलम्ब होने का क्या कारण है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने ग्रापको निवेदन किया कि नेवेली लिग्नाइट के बारे में मामला विचाराधीन है कि उसे लगाया जाये या नहीं ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : सरकार के पास कितने मामले विचाराधीन हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : ग्रापका कोई मामला विचाराधीन नहीं है ।

श्री भीमसेन : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, पलाना में जो कोयला निकलता है, वह ग्राग पकड़ लेता है; वहां पर ब्रिकेटिंग प्लांट लगाना जरूरी है । इसके बिना पलाना के कोयले की बिक्री घट रही है ग्रौर खान घाटे में जा रही है । इस प्रोजेक्ट के लगाने से सरकार को मुनाफा हो सकता है ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन करता हूं कि यह नेवेली लिग्लाइट प्रोजेक्ट का ब्रिकेटिंग प्लांट काफी पुराना है । इसको मैं खुद भी देख ग्राया हूं ग्रौर हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स भी देख ग्राये हैं । यह ३० टन का ब्रिकेटिंग प्लांट काफी पुराना है ग्रौर उसकी कीमत भी ज्यादा है । उसका राइट यूटिलाइजेशन नहीं हो सकेगा । हम समझते हैं कि यह पलाना के लिए खास उपयोगी नहीं हो सकेगा, ऐसी हमारे एक्सपर्ट्स की राय है, लेकिन ग्रभी तक हमने इस पर फाइनल डिसीजन नहीं लिया है ग्रौर इसके साथ ही मैं यह भी बता दूं कि हम ग्रोपन कास्ट माइनिंग करके, उसके कोयले को ब्रिकेटिंग करके, हम उसको ग्राग में जलाना नहीं चाहते, उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं पॉवर के लिए ।

प्रश्न सं० २७३

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

श्री गोविन्दसिंह !

रोडवेज की बसों द्वारा डाक

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) राजस्थान रोडवेज की बसों द्वारा दरा रेल्वे स्टेशन से झालावाड़ व झालरापाटन डाक कब से लाने ले जाने का कार्य प्रारम्भ हुआ ?

(२) राजस्थान रोडवेज को इस डाक के लाने लेजाने के लिए पोस्ट ऑफिस द्वारा क्या मिलता है ?

(३) क्या उपरोक्त शहरों को डाक ले जाने व लाने के लिए कोई खास बस का इन्तजाम है ? यदि नहीं, तो कौन कौन सी बसों को यह काम सुपुर्द कर रखा है ?

(४) दरा स्टेशन से जो बस डाक ले जाती है, यदि ट्रेन लेट हुई तो क्या यह बस ट्रेन आने का इन्तजार करती है और ट्रेन आने पर डाक ले कर ही झालावाड़ को रवाना होती है ? यदि नहीं, तो डाक के लिए क्या व्यवस्था की जाती है ?

(५) क्या यह भी सही है कि जब से राजस्थान रोडवेज को बसों द्वारा दरा से डाक झालावाड़ व झालरापाटन ले जाने का कार्य प्रारम्भ हुआ है, कभी कभी झालावाड़ व झालरापाटन को दो-दो तीन-तीन दिन तक डाक ही नहीं मिल पाती है ?

(६) क्या यह भी सही है कि जनता ने डाक समय पर न मिलने की शिकायतें यातायात विभाग को व जिलाधीश झालावाड़ को की हैं ?

(७) यदि हां, तो अब राज्य सरकार इस व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाने के बारे में क्या सोचती है ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) दरा रेल्वे स्टेशन से झालावाड़ व झालरापाटन डाक ले जाने का कार्य निगम द्वारा १-७-६५ से शुरू किया गया।

(२) डाक ले जाने व लाने के लिए निगम द्वारा डाक व तार विभाग से निम्न दरों पर पैसा वसूल किया जाता है :—

(१) जिन मार्गों पर डाक का भार एक मन से अधिक होता है उनको दरें ए-बी एण्ड सी मार्गों पर क्रमशः ४-१/४, ५-३/४ व ७-१/४ पाई प्रति मन प्रति मील की दर से। (२) जिन मार्गों पर डाक का भार एक मन या इससे कम होता है उन पर ए-बी एण्ड सी क्लास मार्गों पर क्रमशः ४-१/३, ६ व ७-३/४ प्रतिमन प्रति मील की दर से। यह डाक का भार प्रति वर्ष माह अप्रेल व सितम्बर में पूरे एक सप्ताह तक लिया जाता है और डाक का औसतन भार ज्ञात करके उसी आधार पर किराया तय किया जाता है।

(३) दरा स्टेशन से डाक ले जाने का कार्य ६ बजे कोटा-इकलेरा तथा १०.३० बजे कोटा से झालरापाटन जाने वाली वाहन सेवाओं के सुपुर्द था। लेकिन डाक विभाग ने दरा स्टेशन के बजाय अब श्री छतरपुरा (झालावाड़ रोड) से डाक भिजवाने का प्रबन्ध कर लिया है। वहां निगम की गाड़ियां

(श्री भीमसिंह)
नहीं चलती हैं, इसलिए अब डाक व तार विभाग ने डाक की व्यवस्था प्राईवेट गाड़ियों से की है।

(४) अगर दरा स्टेशन पर गाड़ी लेट हो जाती थी तो निगम की बस आधे घन्टे तक इन्तजार करती और इसके बाद रवाना हो जाती थी और डाक उसके बाद चलने वाली दूसरी गाड़ी द्वारा ले जाई जाती थी।

(५) यह सही है कि कोटा डिपो की गाड़ियों की स्थिति अधिकांश खराब होने के कारण गाड़ियों के रास्ते में खराब होने पर या गाड़ियों के कैंसल हो जाने पर कभी कभी डाक समय पर नहीं पहुंच पाती थी।

(६) निगम को जनता से इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। डाक व तार विभाग से अवश्य कुछ शिकायतें प्राप्त हुई जिनको दूर करने का निगम द्वारा पूरा पूरा प्रयास किया गया।

(७) अब डाक श्री छतरपुरा से प्राईवेट बसों द्वारा लाई व ले जाई जाती है, इसलिए अब इसका प्रश्न नहीं उठता है।

श्री गोविन्दसिंह : क्या यह सही है कि अगर आपका डाक लेजाने का काम ठीक तरह से चलता तो इससे निगम को पैदा होती रहती। अब झालावाड़ रोड से व्यवस्था हो जाने से वह काम प्राईवेट बसों के पास चला गया है और इससे निगम को नुकसान हुआ है? अगर आप ठीक टाइम से डाक लाने ले जाने की व्यवस्था रखते तो इससे निगम को पैदा होती।

श्री भीमसिंह : हो सकता है यह कारण हो।

श्री गोविन्दसिंह : यह ठीक है तो फिर ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं की ?

श्री भीमसिंह : ठीक करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन अब तो डाक तार विभाग ने इसका लोकेशन चेंज कर दिया है। और जो इन्होंने लोकेशन चेंज किया है तो इसमें यह भी हो सकता है कि वहां से डाक जल्दी पहुंचती हो। यह ठीक है कि गाड़ियां फेल होती थीं और इससे डाक पहुंचने में भी देरी हो जाती थी, इसकी शिकायत डाक तार विभाग को रही है।

श्री गोविन्दसिंह : वहां पर डाक पहुंचाने में तीन-तीन दिन तक की देरी हुई है और लोगों की शिकायतें रही हैं कि उनको डाक समय पर नहीं मिलती है। अब जिस लोकेशन का इन्तजाम किया है वह भी पर्मानेन्ट नहीं है बरसात में आहू नदि पर पुल नहीं बन्धा हुआ है और इससे फिर डाक देर से पहुंचने की शिकायत होगी। मैं यह कह सकता हूं कि दरा स्टेशन से झालावाड़ को डाक जल्दी मिल सकती है, लेकिन डाक तार विभाग को यह चेंज आपके निगम की इनएफिशियेंसी की वजह से करना पड़ा है। अब बरसात में फिर जनता को टाइम से डाक नहीं मिलने की शिकायत होगी तो मेरा निवेदन है कि आप इस ओर ध्यान क्यों नहीं देते, जिससे जनता को भी डाक समय पर मिल जाय और निगम को आमदनी भी हो।

श्री भीमसिंह : अध्यक्ष महोदय, शिकायत सही है, आयन्दा कोशिश की जायगी कि यह शिकायत दूर हो।

प्रश्न संख्या २७५

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत

सार्वजनिक क्षेत्र में खोले गये उद्योगों की सफलता

२७६. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या मंत्री सार्वजनिक उद्योग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सार्वजनिक क्षेत्र में खोले गये उद्योग इतनी सफलता से नहीं चल रहे हैं जितनी अपेक्षा थी ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन कारणों पर कभी विचार किया है ?

(३) क्या यह सही है कि रेडटेपिज्म आदि कारणों से इन उद्योगों का सुचारु रूप से काम नहीं चलता इसलिए आमदनी में कमी रहती है ?

(४) क्या सरकार मौजूदा प्रशासनिक नियमों में कुछ हेर फेर करने पर विचार कर रही है या करने का विचार रखती हैं ?

राजकीय उपक्रम मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) नहीं, यह सही नहीं है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) मौजूदा प्रशासन द्वारा उचित कार्य किया जा रहा है। जब सरकार उचित समझती है राजकीय उद्योग चलाने के लिये नियमों में उचित परिवर्तन करती रहती है। और इस आधार पर कुछ नियम स्थापित किये गये हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने पहले सवाल में कहा जी नहीं। आपके पास तीन स्टेट एन्टर-प्राइसेज हैं और तीनों ही असफलता पूर्वक चल रहे हैं, चाहे वह गंगानगर शुगर फैक्ट्री हो, चाहे धौलपुर हाइटेक हो, चाहे सोडियम सल्फेट प्लान्ट को ले लीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : हमारे पास स्टेट एन्टरप्राइजेज में, नमक के उद्योग में साढ़े पांच लाख का प्रोफिट है, सोडियम सल्फेट में साढ़े पांच लाख का प्राफिट है, सोडियम सलफेट इन्डीजिनस में सवा लाख का प्राफिट मिल रहा है, गंगानगर शूगर फैक्ट्री ने बहुत प्राफिट दिया है। इसके लिए दो महिने का बोनस भी लेबर को दिया जा रहा है। एक हाइटेक ग्लास फैक्ट्री है····

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : प्रोफिट बता रहे हैं तो उसके साथ घाटा भी बता दें। सोडियम सलफेट कितने साल बाद चला यह भी हिसाब बता दें।

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो इस वक्त इस साल की बात कर रहा हूं। इस बेसिक इयर में जो कि खत्म हुआ है, उसमें सोडियम सल्फेट ने साढ़े पांच लाख का प्रोफिट दिया है, इन्डिजिनस से सवा लाख का और नमक ने साढ़े पांच लाख का दिया है। उसके बाद में शूगर फैक्ट्री ने करीब करीब ११ लाख का प्राफिट दिया है। उसने इन्कम टैक्स चुकाया है और दो महीने का बोनस दिया हैं। उसके बाद में एक ग्लास फैक्ट्री है जो कि पूरी तरह से चालू नहीं हुई है। एकही भट्टी चालू हुई है जबकि प्लान में दो भट्टियां थीं। इस साल हम सितम्बर महिने तक ७० हजार का २३२ डिफरेन्ट टाइप

(श्री मथुरादास माथुर)
ग्रॉफ वेराइटीज का ग्लास प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसमें साढ़े छः लाख का इन्वेस्मेंट है सिर्फ, ज्यादा नहीं है। उसमें ग्रौर इवेन्स्टमेंट करके चलाने की बात कर रहे हैं। ग्लास टैकनोलॉजिस्ट को लाये हैं ग्रौर गवर्नमेंट ग्रॉफ इंडिया के ग्लास टैक्नोलाजी एक्सपर्ट से भी एडवाइस ले रहे हैं। हाईटैक को वास्तव में हाइटैक बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है फिर भी बहनजी कह रही हैं कि घाटा हो रहा है।

श्री ग्रध्यक्ष : (श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत के पुनः खड़े होने पर) इसमें बहस की बात नहीं है। प्रश्नोत्तर में इस तरह की बहस नहीं हो सकती है।

श्री मोहरसिंह !

सरदारशहर कालू सड़क का निर्माण

२७७. **मोहरसिंह** (चूरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) सरदारशहर से कालू सड़क निर्माण कार्य कब शुरू किया गया ग्रौर उस पर ग्रब तक क्या क्या कार्य हुग्रा है ? इस कार्य पर कुल कितना व्यय हुग्रा है ?

(२) यह कार्य कहां से कहां तक हुग्रा है ग्रौर इसमें क्या कार्य बाकी है।

(३) इस सड़क की कुल लम्बाई क्या है ग्रौर कुल संभावित खर्चा क्या होगा।

(४) इस ग्रधूरे कार्य को सरकार कब पूरा करवायेगी। ऐसा करने तक इस सड़क पर पड़े हुए पत्थर ग्रादि की रखवाली की सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

(५) क्या इस सड़क के लिए ली गई भूमि का मुग्रावजा किसानों को दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? ग्रब कब तक यह मुग्रावजा दिया जावेगा ग्रौर वह कितनी धनराशि होगी ?

उप-मंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री परसराम मदेरणा) : ग्रध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के सम्बन्ध में ग्रभी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है इसलिए इसको एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया जाये।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री मजलिस खां।

जल प्रदाय योजना, कस्बा कामां

२७८. **श्री मजलिस खां** (कामां): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कस्बा कामां की जलप्रदाय योजना की, जो ७,६६,०००रु० की है, मंजूरी भारत सरकार से ग्रा गई है ?

(२) क्या यह भी सही है कि म्युनिसिपिल बोर्ड कामां ने पहली किश्त दाखिल करादी है ? यदि हां, तो कुल कितनी किश्तें हैं ग्रौर उनकी कितनी धनराशि बनती है ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के कुछ टेन्डर हो गये हैं ग्रौर कुछ बाकी हैं ? यदि हां, तो बाकी टेन्डर कब तक हो जायेंगे ?

(४) क्या यह भी सही है कि कुछ पाइप कामां पहुंचा दिये हैं ग्रौर कुछ बाकी हैं ? बाकी पाइप कब तक पहुँचा दिये जायेंगे ?

(५) उक्त योजना के लिये पानी कहां से सप्लाई किया जावेगा ग्रौर टंकी के लिए स्थान कहां पर चुना गया है ?

(श्री मजलिसखां)

(६) योजना कब तक पूरी करादी जायेगी ?

जन-स्वास्थ्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (१) जी हां, कस्बा कामां की जल प्रदाय योजना के लिए ६.८७ लाख रु० की मंजूरी भारत सरकार से आ गई है।

(२) नगरपालिका कामां ने कुल ५०,००० रु० जन सहयोग के रूप में देने के लिये मंजूर किया था, उसमें से अभी तक कुल ३५,००० रु० प्राप्त हुआ है।

(३) जी हां, कुछ टेन्डर हो चुके हैं और कार्य प्रारम्भ करने का आदेश जारी हो चुका है। कुछ टेंडर विचाराधीन हैं और बाकी टेंडर निकट भविष्य मे कर लिये जावेंगे।

(४) जी हां।

(५) पानी के लिये नल कूप गोवर्धन-कामां ड्रेन के आस-पास खोदे जावेंगे। टंकी के लिये स्थान कामां-फुरेहरा सड़क पर हनुमान पाठशाला के पास चुन लिया गया हैं।

(६) साधारणतया योजना को पूर्ण करने में दो से तीन साल की अवधि लग जाती है और यह सब आवश्यक सामग्री एवं वित्त व्यवस्था पर निर्भर करता है।

खरंजों व पुलों का मेन्टीनेन्स

२७६. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) भूतपूर्व कोटा स्टेट द्वारा बनाये गये बड़े बड़े खरंजों व पुलो को जो चालू सड़कों पर नहीं होने से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अब तक नहीं मेन्टेन किये गये हैं, किस प्रकार मेन्टेन किये जाने की योजना हैं ?

(२) क्या सरकार ने उक्त प्रकार के खरंजों व पुलों का सर्वे करवा लिया है ? यदि हां, तो उनकी सूची मय उनकी अनुमानित लागत के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) क्या यह सही है कि गागरोन से सुकेत आने के लिए अमभार पर बनाई गई गंडी बारां नाम की हजारों रुपये की पुलिया मेन्टीनेन्स के अभाव में ही खराब हो गई है ? क्या सरकार इसके लिए विशेष मरम्मत का प्रबन्ध करेगी ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री परसराम मदेरणा) : (१) विचाराधीन हैं।

(२) सर्वे कराई जा रही है।

(३) पुलियां विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं हैं।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो है दो साल पहले भी मैंने पूछा था और इसी तरह से पूछा था कि सर्वे पूरी हुई है या नहीं और यहां मुझे एश्योरेन्स दिया गया था कि आफ रोड ब्रिजेज जो हैं उनकी रिपेयर्स सरकार करेगी ये ब्रिजेज लाखों रुपयों की हैं और अभी तक रिपेयर्स नहीं होने के कारण बड़ी खराब हालत में हो रही है। जब एश्योरेन्स मिल चुका हो तो मेन्टेन की जानी चाहिये। ये राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं और इसके लिए कुछ न कुछ किया जाना

(श्री जुझारसिंह)
चाहिए। उसके लिए इस तरह का जवाब मिलता है तो खेदजनक है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय जब माननीय सदस्य ने पहले यह प्रश्न पूछा था....

श्री अध्यक्ष : तब भी यही जवाब दिया था। (हंसी)

श्री परसराम मदेरणा : नहीं यह जवाब नहीं दिया था। माननीय सदस्य के प्रश्न पूछने के बाद १८ मार्च ६३ को चीफ इन्जीनियर ने चिट्ठी लिखी कि इस प्रकार की जितनी भी कलवर्ट्स, ब्रिजेज़ जो पी० डब्ल्यू०डी० की रोड लिस्ट पर नहीं हैं। लेकिन यों ही बनी हुई हैं और उनकी उपयोगिता है और किसी समय कोलेप्स हो सकती हैं, तो उसमें बाद में ज्यादा पैसा लगेगा। इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके चीफ इन्जीनियर के पास भेजो। वह नहीं आई हैं तो उसके लिए रिमाइन्डर भी भेज दिया गया है और उनको टाइम भी दे दिया गया है कि इस टाइम तक इन्फॉर्मेशन हमारे पास भेज दो। इन्फॉर्मेशन आने के बाद में अर्थ को देखते हुए मुनासिब कार्यवाही की जायेगी।

श्री जुझारसिंह : आपने खुद ने मन्जूर किया है कि १९६३ के बाद जानकारी के लिए लिखा है तो उसको भी आज तीन साल हो गये हैं तो इन तीन सालों में तो उनकी और भी हालत खराब हो गई होगी। आप फिर दुबारा प्रश्न आयेगा तो दूसरी जानकारी करेंगे और दुबारा लेटर लिख देंगे, लेकिन यह जानकारी नहीं आयेगी और एवरी इअर (every year) डिटेरियोरेट हो रही है तो उन पर जल्दी ही कार्यवाही फर्माई जावे।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न पूरे राजस्थान का है और राजस्थान में ३२ हजार गांव हैं और उनमें हजारों कलवर्ट्स और ब्रिजेज इस तरह की होंगी तो उनकी लिस्ट मंगाई है वह इंफॉर्मेशन देना संभव नहीं था। पूरे राजस्थान का प्रश्न है तो उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। इन्फॉर्मेशन जब आवेगी तो किस को टॉप प्रॉयोरिटी दी जायेगी और किस को नहीं यह तय किया जायेगा।

श्री जुझारसिंह : मेरा प्रश्न कोटा स्टेट के बारे में रहा है। न तो राजस्थान के बारे में पहले पहले पूछा था न आज पूछा जा रहा है। इसमें साफ है कि कोटा स्टेट के टाइम की ऐसी पुलियां कितनी हैं जो आफ रोड्स हैं। न मैं पूरे राजस्थान का प्रश्न पूछ रहा हूं। तीन साल से मैं उसी के बारे में पूछ रहा हूं और राजस्थान सरकार उसका सर्वे करवा रही है। डिफिकल्टी कहां है? मैंने छोटा सा सवाल किया है उसकी जानकारी करने में दिक्कत नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य तो केवल कोटा में ही इन्ट्रस्टेड हैं, लेकिन सरकार को तो पूरे राजस्थान की जानकारी चाहिए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : इसके सम्बन्ध में क्या प्लान है राजस्थान सरकार के पास? इस प्रकार की पुलियों की मरम्मत के सम्बन्ध में आपकी कोई योजना तो होनी चाहिए।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक अपोजि-

[redacted]

(श्री हरिश्चन्द्र)

शन के लीडर ने कहा है उसके सम्बन्ध में यह अर्ज है कि जो पुलियां रेगुलर रोड़ की मेन्टीनेन्स लिस्ट में हैं उनकी रिपेयर्स तो हम करते है, लेकिन जो माननीय सदस्य चेचट से आये हैं वे पूछ रहे हैं उनके लिए एक विशेष परिस्थिति है, और इनके पहले प्रश्न के उत्तर में यहां इस सदन में अर्ज किया गया है कि कोटा में कई कच्ची सड़कों पर सरकार ने पुलियां बनवा रखी थीं, लेकिन वे हमारी रेग्युलर मेन्टीनेन्स की लिस्ट में नहीं हैं इसलिए उनकी रिपेयर्स नहीं होती थी। इस सदन में मैंने खुद ने कहा था कि हम जो हैं ऐसी पुलियों की रिपेयर्स करें, लेकिन मेरे सामने सवाल है कि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध नहीं हो रही है इसलिए मैं उस हैड में उनको डेबिट नहीं कर सकता हूं। यह मेरी परेशानी है, लेकिन इतना जरूर हो सकता है कि कोई भी पुलिया जो टूटने वाली हो तो उसको हम थोड़ी बहुत पेच रिपेयर्स करके सुरक्षित रखने के लिए काम कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति हमारी जरूर हो सकती है, लेकिन इनको हम फुल मेन्टीनेन्स लिस्ट में अभी नहीं ले सकते है, क्योंकि हमारे पास इतनी धनराशि नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): इन्कार भी मत करिये और करिये भी मत।

श्री हरिश्चन्द्र: आपकी इच्छा यह है तो मेरे पास भी पैसा नहीं है नहीं करूंगा।

एक प्रश्न माननीय सदस्य ने रखा है वह अहम मसला है कि इतने लाखों रुपया खर्च करके कच्ची सड़कों पर पुलियां बनवाई गई हैं, लेकिन मेरे पास उनके लिए कोई पैसा नहीं है। मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि मैं रेग्युलर रोड्स के मेंटीनेन्स का खर्चा उठा सकूं, ऐसी हालत में और पैसा कहां से लाऊं लेकिन अगर कोई भी पुलिया जो बिल्कुल ही गिर रही हो या टूट रही हो तो उसके लिए ध्यान देंगे।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा): आपने फर्माया कि मेरी परेशानी है तो परेशानी से आपको मुब्तिला कौन कर रहा है? क्या कारण है परेशानी दूर नहीं होती है?

श्री जुझार सिंह: अध्यक्ष महोदय, आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि १८ साल से जिन पुलियों की मरम्मत नहीं हुई होगी तो उनकी क्या दशा होगी? क्रेक बहुत ज्यादा हो गई होंगी। आपने कहा कि पुलियों का नाम नहीं बताया। तो मेने 'मंडी-बारां' के बारे में जिक्र किया है कि वह टूट रही है ऐसा प्रश्न है।

श्री हरिश्चन्द्र: लेकिन अभी कोई टूटी नहीं हैं। दूसरी मेरे पास इन्फर्मेशन कलेक्टेड है कि पी० डब्लू० डी० ने कौन-कौन सी पुलियों को देखा है। उन्होंने एस्टीमेट भी भेजे हैं। उन सब का मेन्टीनेन्स करने के लिए आप कहेंगे, तो कम से कम २०-२५ लाख रुपये चाहिए। इतना पैसा नहीं है, इसलिए जो सुरक्षित हालत में नहीं हैं उनकी रिपेयर कराने के लिए इजाजत चीफ इन्जीनियर से कहकर दिलवा दूंगा।

एक माननीय सदस्य: इसके लिए स्पेशल फण्ड के लिए वित्त मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट की है?

वित्त मन्त्री (श्री बालकृष्ण कौल): हाउस से लाना जी।

श्री प्रभुलाल सेन्टर (खानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय, को सूचित कर दूं कि जो कनवास और खानपुर रोड पर पुल है अगर उसकी मरम्मत नहीं हुई तो दो-तीन लाख रुपये लगकर भी पुलिया तैयार नहीं होगी।

श्री हरिश्चन्द्र : उस पुलिया के बारे में आप लिखकर दे दें। मैं आज ही हुक्म निकाल दूंगा

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : क्या ये पुलियाएं पी० डब्लू० डी० के चार्ज में हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप भी हुक्म लिखवा लें यह कहकर।

श्री हरिश्चन्द्र : आपके कहने का मतलब यह है कि जो चार्ज में हो उन्हीं की रिपेयर्स हो और औरों की नहीं। आप एक निर्णय तो लें।

श्री गोविन्दसिंह : अगर पी० डब्लू० डी० के चार्ज में नहीं है, तो क्या उनको उसके चार्ज में ले लें।

श्री हरिश्चन्द्र : यह जो पुलियायें जो माननीय सदस्य चेचट से आये हैं उन्होंने बतलाई हैं एक भी मैन्टीनेन्स की लिस्ट पर नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सजेशन देना चाहता हूं कि आप भी कर्जा लेकर प्रॉस्पेरिटी बढ़ा लें। २५ लाख रुपये चाहिये तो आप लगा दें।

श्री हरिश्चन्द्र : मुझे ऐसी जगह बता दीजिये जहां से रुपया मिलता हो।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वह तो आप लीजिये फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मंत्री महोदय ने इस संबंध में प्रकाश डाला, एक हद तक मेरी सहानुभूति अवश्य है। परन्तु ऐसे खुरंजे और पुलियां हैं, जो उपयोगी हैं और उनकी उपयोगिता को मद्देनजर रख कर प्राथमिकता देकर मरम्मत करायेंगे तो ठीक होगा। कोटा में बहुत सी जगह हैं जहां खुरंजे और पुलिया हैं, पक्की सड़कें नहीं हैं, लेकिन उनकी उपयोगिता आज भी हैं। ऐसी पुलियां कायम रहनी चाहिए। आपके फंड्स अलॉट करें तो इन की मरम्मत कराना ठीक है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : एक प्रश्न श्री सतीशचन्द्रजी का २६० नम्बर का और है।

श्री अध्यक्ष : यह तो बहस के समय उठाया जा सकता है।

श्री मानधातासिंह।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

नगरपालिकाओं का वर्गीकरण

२५३. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ३०३ की उप-धारा (१) के खण्ड [ए] के अन्तर्गत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक ७(६९) ९ (डी) १२५ ल. जस. जी. । ।५६

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दिनांक २१-५-६० द्वारा नगरपालिकाओं का जो वर्गीकरण किया गया था वह केवल राजस्थान नगरपालिका सेवा के सदस्यों के प्रयोजनार्थ ही था ?

उत्तर

१. जी हां।

पुलों का निर्माण

२५७. **श्री मथुरेशबिहारी माथुर**(बांदीकुई): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

क्या सिकन्दरा से बांदीकुई तक जाने वाली सड़क पर बानगंगा नदी व सावां नदी पर पुल बनाने की योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित थी ? यदि हां, तो इन पुलों का कार्य अब तक न होने के क्या कारण हैं व अब कब तक बनाने की संभावना है ?

उत्तर

जी हां। अर्थाभाव के कारण कार्य अभी तक नहीं हो सका। आशा है चतुर्थ योजना-काल में यह कार्य पूरा हो जायगा।

कुशलगढ़ में मिट्टी के तेल की समस्या

२५९. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या जिला बांसवाड़ा की तहसील कुशलगढ़ में मिट्टी का तेल मिलना कतई बन्द हो गया है ? अगर हां, तो कब से और क्यों ?

(२) क्या सरकार उक्त समस्या को हल करने के लिए तेल की व्यवस्था कुशलगढ़ में करेगी ? अगर हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) तेल मिल रहा है।

प्रति व्यक्ति औसत आय

२६०. श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में राज्य में प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी आंकी गई थी और कितनी उपलब्धि का अनुमान है ?

(२) क्या राज्य सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि जिन आधारों पर केन्द्रीय सरकार प्रति व्यक्ति, व्यक्ति औसत आय का अनुमान लगाती है उन आधारों पर यदि राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय का हिसाब जावे तो यह काफी कम आती है और केन्द्र और राज्य के बीच का अन्तर कम होता नहीं दिखाई देता है ?

(३) इन्हीं आधारों पर भारत के अन्य राज्यों में जो आय का निर्धारण किया गया है उसमें राजस्थान का कौनसा स्थान है ?

(४) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति औसत आय का सर्वेक्षण कराया था ? यदि हां, तो जिले-वार प्रति व्यक्ति औसतन आय ग्रामीण क्षेत्रों की बताने की कृपा करें।

[redacted]

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(५) क्या यह सही है कि कुछ जिलों की सर्वेक्षण रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई थी ? यदि हां, तो शेष जिलों की रिपोर्ट्स क्यों नही तैयार कराई गई व काम क्यों रोक दिया गया ?

उत्तर

(१) तृतीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण के समय राज्य में प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े इस योजनाकाल के अन्त तक के लिए आंके नहीं गये थे। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक ज्ञापन को तैयार करते समय उपलब्ध सामग्री के अनुसार जो प्रक्षेप (Projections) किये गये थे उनके अनुसार इस वर्ष में प्रति व्यक्ति आय १९६०-६१ की कीमतों पर ३५५ रु० हो जाने की आशा थी। सन् १९६५-६६ में प्रति व्यक्ति औसत आय के अनुमान अभी तैयार नहीं हुए हैं।

(२) राज्य सरकार द्वारा राजकीय आय के अनुमान लगभग केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्य में लाई गई विधि के अनुसार ही अनुमानित किये जाते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित अनुमान १९४८-४९ के स्थिर मूल्यों पर उपलब्ध हैं। इस आधार—वर्ष के मूल्यों पर राज्य आय के अनुमान उपलब्ध नहीं है। इस कारण राज्य-आय और केन्द्रीय-आय के अनुमान तुलनात्मक नहीं हैं। चालू मूल्यों के आधार पर उपलब्ध आंकड़ों से निम्न स्थिति व्यक्त होती है :—

प्रति व्यक्ति आय चालू मूल्यों पर

(रुपयों में)

	१९५५-५६	१९६०-६१	१९६१-६२	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५
राज्य	२६०	३२३	३४३	३४२	३३७ +	३८२ ❀
भारत	२५५.०	३२५.७	३३३.६	३३६.४	३७०.७ †	अप्राप्त

+ प्रारम्भिक ❀ अग्रिम † अस्थायी

(३) विभिन्न राज्यों के अनुमानों के आधार वर्ष भिन्न होने के कारण अनुमान तुलनात्मक नहीं हैं। तुलनात्मक कार्य विधि पर आधारित अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं। यह अनुमान भारत सरकार द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं। इसलिए राज्य की स्थिति का अन्य राज्यों की तुलना में अनुमान लगाना इस समय सम्भव नहीं है।

(४) भूतपूर्व आर्थिक व औद्योगिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा राजस्थान के सभी जिलों में ग्रामीण आर्थिक दशा के विषय पर सर्वेक्षण कराया गया था और प्राप्त परिणामों का संकलन कराया जा रहा है। अभी इस सर्वेक्षण के आधार पर प्रति व्यक्ति औसतन आय के आंकड़े तैयार नहीं हैं।

(श्री योजना मंत्री)

(५) कुछ जिलों की रिपोर्ट के प्रारूप प्राप्त हुए थे जिनको अंतिम रूप देने का कार्य तथा शेष जिलों की रिपोर्ट तैयार करने का कार्य आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय को सौंप दिया गया। सभी जिलों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है और यह काम रोका नहीं गया है।

कुओं के लिए बिजली, तहसील रेवदर

२६३. श्री दलपतसिंह (आबू): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने रेवदर तहसील (सिरोही डिस्ट्रिक्ट) में पूरे पंचायत समिति के क्षेत्र में गत जनवरी से पहले पहले कुओं के लिए बिजली देना तय किया था ?

(२) क्या यह सही है कि अभी तक एक भी कूए पर बिजली नहीं दी गई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(३) क्या निकट भविष्य में जल्दी ही उपरोक्त पंचायत समिति क्षेत्र में बिजली दी जायेगी ?

उत्तर

(१) जी नहीं, केवल रेवदर ग्राम एवं समीपवर्ती क्षेत्र में बिजली देने का निश्चय किया था।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

हथरोही कॉलोनी, जयपुर

२९६. श्री मांगीलाल (रायपुर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतायेंगे:—

(१) क्या जयपुर नगर में हथरोही नामक एक निजी कालोनी श्री रामेश्वरलाल सहरिया ने बसाने की मंजूरी मांगी थी ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त कालोनी की मंजूरी इस बात के बावजूद दे दी गई है कि उपरोक्त सेठ ने न तो कालोनी में सड़कें बनाई हैं और न बिजली का प्रबन्ध ही किया है ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त कालोनी में से सरकार अपने खर्चे से एक चौड़ी सड़क बनाना चाहती है जो सड़क अजमेर रोड और मिर्जा स्माइल रोड को मिलायेगी ?

(४) क्या यह सही है कि सरकार उपरोक्त सड़क अपने खर्चे से न बनाकर कालोनी की मंजूरी देते समय उपरोक्त सेठ को ही बाध्य कर सकती थी कि वह एक सड़क निर्धारित चौड़ाई की अपने खर्चे से बनाये ?

(५) यदि हां, तो सरकारी खर्चे से उपरोक्त सड़क क्यों बनाई जा रही है जब कि इस सड़क का मुख्य लाभ उपरोक्त निजी कालोनी के निवासियों को और उपरोक्त सेठ को ही होगा ?

उत्तर

१. जी हां।

२. सड़कें व बिजली के प्रबन्ध का प्रश्न योजना की स्वीकृति से पूर्व नहीं उठता।

(श्री स्वायत्त शासन मंत्री)

(३) जी नहीं केवल सड़क को ४० फुट के बजाय ६० फुट चौड़ा यातायात की दृष्टि से करेगी।

(४) स्वीकृति योजना में प्रावधान के अनुसार श्री सहरिया ने ४० फीट चौड़ी सड़क बनाने का कार्य आरंभ किया, परन्तु इसी बीच में उनका देहान्त हो गया। शेष कार्य को पूरा कराने हेतु उनके उत्तराधिकारियों को लिखा गया है।

(५) जी नहीं। केवल २० फीट चौड़ी सड़क बनाने का खर्चा नगर विकास न्यास करेगा, क्यों कि सड़क चौड़ी करने से लाभ कालोनी तक सीमित न रख कर यातायात की समस्या को हल करेगा व मिर्जा इस्माइल रोड को नेशनल हाई-वे से मिलायेगा।

बस्ती का निर्माण

२७३. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) आकाशवाणी अजमेर के पास जो कालबेलियों की बस्ती बसाई गई है उसका निर्माण कब हुआ और उस पर कितना खर्चा हुआ?

(२) क्या यह सही है कि इस बस्ती में जो मकान बनाये गये हैं वे बहुत छोटे हैं?

उत्तर

(१) आकाशवाणी अजमेर के पास जो कालबेलियों की बस्ती बसाई गई है उसका निर्माण १९६० में सम्पूर्ण हुआ जिसके निर्माण हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा कालबेलियों के १६ परिवारों को १२ हजार रुपया का अनुदान दिया गया।

(२) उक्त बस्ती में जिन भवनों का निर्माण हुआ है उसकी प्रत्येक की बाहर से लम्बाई १५' चौड़ाई १०' व ऊंचाई ९' ३" की है जो पर्याप्त है।

पुष्कर में गाडोलिया लुहारों की बस्ती

२७५. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा पुष्कर में गाडोलिया लुहारों की बस्ती का निर्माण कराया है? यदि हां, तो कब और कितने रुपयों में?

(२) इस बस्ती में कितने मकान हैं, और उनमें कितने परिवार रहते हैं?

(३) क्या यह सच है कि इस बस्ती में अधिकतर अधूरे मकान पड़े हैं? यदि हां, तो क्यों व कब से?

उत्तर

(१) पुष्कर के गाडोलिया लुहारों के ११ परिवारों को सन् १९५७-५८ में ३५०) रु० प्रति परिवार के हिसाब से इस विभाग द्वारा मकान सहायता दी गई थी, परन्तु उक्त राशि में उक्त मकान सम्पूर्ण न होने के कारण ५८-५९ में ४००) रु० प्रति परिवार अतिरिक्त मकान सहायता विभाग की ओर से देनी पड़ी। इस प्रकार ११ परिवारों को ८२५०) रु० की राशि सहायता के तौर पर दी गई।

(२) उक्त बस्ती में ११ भवनों का निर्माण हुआ। उन सब मकानों में गाड़िया लोहार निवास कर रहे है।

(श्री समाज कल्याण मंत्री)

(३) उक्त बस्ती में कोई भी मकान अधूरा नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समिति निवाई के क्षेत्र में बिजली

५१. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पंचायत समिति निवाई के क्षेत्र में कृषि कार्य के लिये कितनी पंचायतों द्वारा बिजली की मांग की गई थी और उनमें से कितनी पंचायतों को बिजली दी गई है? बाकी को कब तक देने का विचार है ?

उत्तर

(क) १४ पंचायतों ने।

(ख) ६ को।

(ग) यथेष्ट धन-राशि मिली तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में।

चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़क-निर्माण का प्रावधान

५२. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राज्य सरकार ने सड़क निर्माण हेतु चौथी योजना के लक्ष्य निर्धारित कर लिये हैं ? अगर हां, तो उक्त तथ्यों की पूर्ति हेतु कितना प्रावधान रखा जा रहा है ?

(२) बीकानेर जिले में चौथी योजना काल में कौन कौन सी सड़कें बनाने का प्रावधान है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) चतुर्थ योजना के प्रस्ताव पूर्ण नहीं हुए हैं।

पलोदड़ा-सराड़ा सड़क

५३. श्री देवीलाल (सराड़ा–सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील सराड़ा में पलोदड़ा से सराड़ा जाने वाली सड़क कुल कितने मील लम्बी है ?

(२) क्या यह सड़क तीसरी पंचवर्षीय योजना में रखी हुई थी ? यदि हां, तो इसके निर्माण के लिये कुल कितनी रकम खर्च करने का अनुमानित आंकड़ा रखा था ?

(३) क्या पलोदड़ा सराड़ा सड़क को सराड़ा तहसील हैड क्वार्टर तक डामर की बनाने का प्रावधान रखा है ?

उत्तर

(१) १३ मील लम्बी सड़क है।

(२) जी हां, तृतीय योजनानुसार ६४,०००)रु० व्यय करने का अनुमान था।

(३) डामर कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

Page No. 40

गिरवा क्षेत्र में सड़क का निर्माण

५४. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या सार्वजनिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार गिरवा क्षेत्र में कैलाशपुरी से रामा और रामा से जिन्डोली सड़क निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

(२) क्या यह सही है कि इस समय वहां यह कार्य प्रारम्भ करने से वहां के लोगों को अकाल के समय में मजदूरी भी मिल सकेगी ?

उत्तर

(१) कैलाशपुरी से नागदा के एक मील के भाग को छोड़ कर कैलाशपुरी से रामा तथा रामा से जिन्डोली रोड का कार्य तृतीय योजना में स्वीकृत नहीं है।

(२) जी हां। किन्तु यह कार्य अकाल राहत कार्यों में भी स्वीकृत नहीं है।

खादी सहकारी समितियों को ऋण

५५. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड व खादी कमीशन द्वारा राजस्थान में कितनी सहकारी समितियों को ऋण व सहायता दी जाती है ? उनमें बोर्ड की कितनी व कमीशन की कितनी धनराशि बकाया है ?

उत्तर

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा दिनांक ३१-३-६५ तक १०५३ सहकारी समितियों को ऋण व सहायता दी गई है। इन सरकारी समितियों को ऋण के रु० ७०,१०,८०२.८० पैसे दिये गये हैं।

उक्त ऋण की रकम में से दिनांक ३१-५-६५ तक ४१,८८,०५०.७८ पैसे किश्तों के ड्यू हुये हैं जिनमें से ३१-५-६५ तक २७,९०,५२४.५७ पैसे वसूल हो गये हैं। शेष रुपये १३,९७,५२६.२१ पैसे बकाया है।

बोर्ड को उपलब्ध जानकारी के अनुसार कमीशन द्वारा १६ सहकारी- समितियों को ३१-३-६४ तक, १२,१५,८४३) रुपये ऋण दिया गया है और दिनांक ३१-३-६५ तक उनमें ११,६८,४०२.१२ पैसा बकाया है।

(१२.२२ म.प.)

आय-व्ययक १९६६-६७ पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री मानधातासिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय, बजट जो सदन में पेश हुआ है उसके संबंध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। हर सरकार को कर लगाने का अधिकार है क्योंकि कोई सरकार बिना कर के चल नहीं सकती। जितनी भी सरकार फेसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं बगैर कर के नहीं कर सकती। लेकिन इस संबंध में मैं आपका ध्यान मनुस्मृति की ओर आकर्षित करूंगा। उसके अन्दर लिखा हुआ है कि राजा कर लगावे वह इस प्रकार लगावें जिस प्रकार भ्रमर पुष्प का रस पीता है। भ्रमर पुष्प का रस इस प्रकार पीता है कि उससे पुष्प वैसा का वैसा रहता है।

(श्री मानधाता सिंह)

कुम्हलाता नहीं है। वह पुष्प का रसास्वादन कर लेता है और पुष्प वैसा का वैसा रहता है कुम्हलाता नहीं है। लेकिन कांग्रेस सरकार इस प्रकार कर लगाती है कि इस पुष्प का बिल्कुल मर्दन कर दिया जाता है, कुम्हला जाता है, सूख जाता है। जनतारूपी पुष्प जो है करों के भार से इतनी दब गई है कि आजकल उसके लिये खड़ा होना मुश्किल हो गया है। तरह तरह के नये नये कर लगाये जाते हैं बल्कि जीवनोपयोगी वस्तुओं को भी कर से खाली नहीं छोड़ा जाता है। अभी हाल ही में डालडा पर कर लगा दिया,........

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): डालडा पर नहीं लगाया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): घी पर लगाया है, तेल पर लगाया है।

श्री मानधातासिंह: घी का मतलब भी आज कल सब डालडा से समझते हैं। घी, तेल, कपड़ा आदि जितनी जीवनोपयोगी वस्तुएं हैं, उन पर करों का भार कम होना चाहिये। पशु कर नया लगाया गया है जो एग्रीकल्चरिस्ट्स को इफेक्ट करता है। एग्रीकल्चरिस्ट जो देश की बैक बोन हैं, उन पर जहां तक हो सके करों का भार कम होना चाहिये। पहले ही उन पर लैंड रेवेन्यू सेसेज इतने बढ़ गये हैं कि उनसे एग्रीकल्चरिस्ट्स पर कर भार पहले की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ गया है। इसके अलावा पशु कर तो उनकी पीठ तोड़ने वाला हो गया। इसी तरह नोन-सीरियल क्रोप्स पर भी कर लगाया गया है। इस सम्बन्ध में अधिक निवेदन नहीं करूंगा। मैंने शुरू में ही निवेदन किया था कि सरकार को ध्यान रखना चाहिये कि कर इस प्रकार लगावें कि उससे जनता का शोषण न हो और सरकार का काम भी चल जाय।

दूसरी तरफ करों से जो धन सरकार एकत्रित करती है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। यदि सदुपयोग हो तो ऐतराज नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल जितना धन करों के रूप में सरकार एकत्रित करती है उसको कई बार पार्टी के काम में लाया जाता है। अभी का ज्वलन्त उदाहरण कांग्रेस अधिवेशन का हमारे सामने है। यह इतने बड़े स्केल पर था कि जिस तरह से गवर्नमेंट मशीनरी काम कर रही थी कि कोई नहीं समझता था कि यह सरकारी फंक्शन है या पार्टी का। कई लोग मुगालते में थे कि यह सरकारी फंक्शन है.....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): आपको तो मुगालता नहीं था?

श्री मानधातासिंह: स्टेडियम की जमीन स्पोर्ट्स कौंसिल को स्पेसीफिक पर्पज के लिये दी गई थी, इस कंडीशन पर कि स्टेडियम बनाया जायगा लेकिन इसका उपयोग पार्टी के कार्य के लिये, कांग्रेस अधिवेशन के लिये किया गया, यह सरकार ने ब्रीच ऑफ कांट्रैक्ट किया। जमीन दी गई थी पर्टिकुलर पर्पज के लिये, स्टेडियम के लिये दी गई थी न कि कांग्रेस अधिवेशन के लिये। फोर्थ प्लान में स्टेडियम तैयार होने वाला था लेकिन केवल कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था, इसलिये इसको शीघ्र तैयार किया गया और जो काम जल्दी में किया जाता है, उसमें ज्यादा खर्चा

(श्री मानधाता सिंह)

होता है, जो काम ५ लाख में तैयार हो सकता था वह १० लाख में हुआ है। सीमेन्ट जो लोगों को मुश्किल से उपलब्ध होती है, यहां पर बहुत अधिक तादाद में काम में लाई गई। टिन्स भी बहुत अधिक तादाद में काम में लिये गये। स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कोर्पोरेशन द्वारा ये टिन्स दिये गये। क्या दूसरी पार्टीज को भी इसी तरह से टिन्स दिये जा सकते हैं ? कदापि नहीं। लेकिन कांग्रेस अधिवेशन के लिये दिये गये। इसी प्रकार संयू पी. डब्लु. डी. ने और इरिगेशन विभाग ने हजारों की तादाद में खरीदे ताकि वहां काम आ सकें। खाने का इन्तजाम मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के द्वारा था। लेकिन जहां तक मुझे मालूम पड़ा, कन्ट्रोल आर्डर की तहत कोई परमिशन नहीं ली गई। जब रेस्ट्रिक्शन है कि इतने से ज्यादा आदमी बगैर परमीशन के एक जगह नहीं खा सकते तो कांग्रेस अधिवेशन के लिये इस प्रकार की परमीशन क्यों नहीं ली गई। सरकार कानून बनाती है और वही खुद उसकी अवहेलना करती है। एक तरफ जब बहुत से लोग भूखे मर रहे हैं, खाद्यान्न की कमी है, वहां कांग्रेस के मेम्बर्स पुलाव उड़ा रहे थे, तरह तरह के पकवान उड़ा रहे थे और इस तरह से वेस्टफुल एक्सपेन्डिचर हो रहा था।

तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे यहां पर बिजली पानी की बहुत कमी है। जब कि इन्डस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल पर्पजेज के लिये बिजली को कट किया जा रहा है वैसी हालत में दूसरी तरफ कांग्रेस अधिवेशन में बिजली की कमी नहीं थी बल्कि दिन में मून लाइट्स दिखाई दे रही थीं। जब एग्रीकल्चरिस्ट्स को बिजली पानी नहीं दिये जा रहे हैं और एक पार्टी को प्रचार के लिये दी जाती है यह कहां तक उचित है। गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स भी वहां पर बहुत तादाद में काम कर रहे थे, जब कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को पार्टी का काम नहीं करना चाहिये। हर तरह के गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स वहां पर मौजूद थे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स थे, मिनिस्टर्स के पी० एज० थे। मिनिस्टर्स के पी० एज० दफ्तर में काम नहीं करके वहां गवर्नमेंट होस्टल में मैंने देखा है कांग्रेस के कमरे में काम कर रहे थे। सेशन में दूसरे लोग भी बहुत बड़ी तादाद में काम कर रहे थे। डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स के मुलाजिम भी वहां पर कार्य कर रहे थे, पार्टी को पब्लिसिटी दी जा रही थी। पुलिस का भी वही हाल था। हजारों की तादाद में पुलिस वाले वहां पर लगे हुए थे। खाली सिक्यूरिटी के लिये ही पुलिस लगाई जाती तो कोई बात नहीं थी लेकिन एस० पीज०, डी० आई० एस. पीज. सब इन्सपेक्टर्स वगैरा को बाहर से बुलाया गया था और उनके टी० ए० डी० ए० का खर्चा हजारों व लाखों रुपयों तक पहुँचेगा। मेरी अर्ज यह है कि क्या यह खर्चा बिल्कुल अॉफिशियल था ? एक तरफ तो फेमिन कण्डीशन्स है और दूसरी तरफ एक पार्टी के लिये इतना खर्च कर रहे हैं! जो रुपया कर के रूप में उपलब्ध होता है उसको इस तरह से खर्च करना मुनासिब नहीं है।

जो प्रदर्शनी वहां लगाई गई थी, उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि एक डिफेन्स पैवेलियन भी उसमें था। मैं निवेदन करूंगा कि क्या दूसरी पार्टियों के जो फंक्शन होते हैं, क्या उनमें भी इस प्रकार की फैसेलिटी दी जाती है, क्या उनमें भी इस प्रकार का

[redacted]

(श्री मानधाता सिंह)

डिफेन्स पेविलियन लगाया जाता है, या कोई प्रदर्शनी लगाने के लिए फैसेलिटीज दी जाती हैं ? जो इस प्रकार की फैसेलिटी कांग्रेस अधिवेशन के लिए दी गई । क्या वह अन्य पार्टियों के फंक्शन में भी दी जाती हैं ? इसके साथ ही में निवेदन करूंगा कि जयपुर में जो स्टेडियम है, वह आपने कांग्रेस अधिवेशन के लिए दे दिया । यदि हमारी पार्टी का कोई अधिवेशन होता है या जनसंघ का अधिवेशन होता है तो क्या यह उसके लिए दिया जा सकेगा ? क्या गवर्नमेंट उसमें भी इस प्रकार से बिजली देगी ? क्या गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट सर्वेंट्स को उसमें नियुक्त करेगी ? और क्या उसमें भी इस प्रकार की प्रदर्शनी लगायेगी ? मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इस बारे में सोच भी नहीं सकती है । मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि डिफरेन्स बिटविन पार्टी एण्ड गवर्नमेंट यह सरकार समझे और इस डिफरेन्स को हमेशा गवर्नमेंट को मद्देनज़र रखना चाहिए । पुराने जमाने में फ्रांस में एक किंग लुई था, वह कहा करता था I am the State मेरा ख्याल है कि इस सरकार के द्वारा Congress is the State कहना मुनासिब नहीं होगा ।

एक और अर्ज मैं कर दूं जो सोशियल वेलफेअर बोर्ड राजस्थान के अन्दर है, उसका करीब दस साल से कोई ऑडिट नहीं हुआ था । इन दस सालों का इस सोशियल वेलफेअर बोर्ड का ऑडिट एक साथ, जब पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने इस सम्बन्ध में ऐतराज उठाया, उस वक्त कराया गया । यह जो दस साल का ऑडिट एक साथ करवाया इसका क्या कारण था जब कि हर डिपार्टमेंट का हर साल ऑडिट होता है ? मैं जानना चाहता हूं कि इस सोशियल वेलफेअर बोर्ड का दस साल तक ऑडिट क्यों नहीं हुआ ? मतलब इस का दस साल का ऑडिट १९६५ में किया गया और जब उस बोर्ड के बारे में राजस्थान सरकार यह निश्चित नहीं कर सकी कि सरकार का उस पर कितना नियंत्रण है । यह एक ताज्जुब की बात है....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : यह ऑडिट १९६३ में हो गया ।

श्री मानधातासिंह : १९६५ में, जहां तक मेरी जानकारी है ।

श्री बालकृष्ण कौल : ऐतराज पहले का है ?

श्री मानधाता सिंह : मेरा ऐतराज यह है कि हर साल ऑडिट होना चाहिए । मतलब यह है कि १९५५ से लेकर १९६५ तक का एक साथ हुआ और वह भी जब लोगों ने एतराज किया कि क्यों नहीं हो रहा है तब हुआ । दूसरे सरकार यह तय नहीं कर सकी कि उसका नियंत्रण इस सोशियल वेलफेअर बोर्ड पर कितना है, यह बड़े ताज्जुब की बात है । जब कि सरकार इस सोशियल वेलफेअर बोर्ड को रन कर रही है तो वह यह नहीं जान सकी कि उसका कितना कंट्रोल इस पर रहेगा । उसमें कुछ पैसा तो सेन्ट्रल से आता है और कुछ इस सरकार के द्वारा दिया जाता है । आखिरकार जब सरकार धन लगाती है, तो वह चाहे सेन्टर का धन हो या इस सरकार का हो— उस पर सरकार का नियंत्रण होना आवश्यक है । इसका कारण क्या है कि इस सरकार का कंट्रोल नहीं रहा ? वह कारण यह है कि उसके अध्यक्ष जो हैं, उसकी अध्यक्षा जो हैं वह एक बहुत बड़े मंत्री की पत्नी हैं....

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : बहुत बड़े मंत्री कौन हैं ?

श्री मानधाता सिंह : आप सब जानते हैं, जो सबसे बड़े मंत्री हैं, वह मुख्य मंत्री ही कहलाते हैं। तो इस कारण से इस सरकार की हिम्मत नहीं हो सकी कि उस पर यह अपना कोई नियंत्रण कर सकें। मैं फिर अर्ज करूंगा कि एक मेक्सिम (maxim) इंग्लैंड में थी, "The King can do no wrong" वही यहां भी एप्लाई करता है........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : कहां है किंग ?

श्री मानधाता सिंह : C. M. can do no wrong. मुख्य मंत्री और किंग में कोई अन्तर नहीं रहा। यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री छत्रसिंह !

श्री छत्रसिंह (आहोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् फाईनेन्स मिनिस्टर साहब ने बजट भाषण में किसानों के साथ में सहानुभूति बताने का प्रदर्शन किया, जिसके द्वारा आप यह बताना चाहते थे कि आप किसानों के साथ बहुत ज्यादा सहानुभूति रखने वाले हैं। लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि आपकी सहानुभूति केवल शब्दों में थी एक्शन में नहीं थी। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है काश्तकारों को अपने उत्पादन का वाजब मूल्य नहीं मिल पाता है। राजस्थान में न तो किसानों को इन्सेन्टिव मिलता है और न ही उनको रेम्यूरेनटिव प्राइसेज मिलती हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि लोग बिल्कुल हताश हो गये हैं, क्योंकि उनको प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। मैं अपनी इस बात को एक उदाहरण देकर साबित करूंगा। जो चना है, वह जिस समय बोया गया उस वक्त चने का भाव ८० रुपये प्रति क्विन्टल था। लेकिन जिस समय चना कट कर आया तो पचपन रुपये प्रति क्विन्टल के भाव से इस सरकार ने लेना स्वीकार किया। इस तरह से काश्तकारों को काफी नुकसान हुआ, चालीस पर्सेन्ट का नफा तो उसी वक्त चला गया और उसके बाद भी पचपन के भाव से कोई लेने वाला तैयार नहीं हुआ। मैंने अपने क्षेत्र में लोगों से कहा कि चना बाजार में भेज दीजिए तो उन्होंने कहा—हमारे पास कोई इन्तजाम नहीं है, और यह मना कर दिया है कि चना आयेगा नहीं। ऐसी हालत में हम कहां जायं। तो इस प्रकार चने के अन्दर किसानों को काफी नुकसान हुआ।

जिस समय यहां पर कांग्रेस का सेशन हो रहा था तो मैं भी देखने के लिए गया था। मुझे खुशी हुई जब एस. के. पाटिल ने फूड रिजोल्यूशन को सपोर्ट करते हुए कहा "What belonged to Ceasar was given to Ceasar" यह सुन कर मुझे खुशी हुई लेकिन जब मैंने एक्शन देखा कि चने के भाव में स्टेपमदर्ली ट्रीटमेंट कल्टीवेटर्स के साथ में किया गया है तो मुझे लगा कि "What belonged to Ceasar has not been given to Ceasar."

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Has been given to Congress.

श्री छत्रसिंह : Yes, I think so. मैं कृषि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह काश्तकार फेमिली से आते हैं और उनको

(श्री छत्रसिंह)

हमारा दुःख-दर्द मालूम है। वह इन फाइनेन्स मिनिस्टर साहब के साथ में काश्मीर की हवा नहीं खायें, वह किसानों के दुःख दर्द को समझें और काश्तकारों को मदद देने की कोशिश करें ताकि उनको मदद मिले और देश के प्रौडक्शन में बढ़ावा हो।

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यहां पर बहुत बातें लम्बी चौड़ी और बढ़ा कर पब्लिक एन्टरप्राइज के लिए की गई। यहां पर पब्लिक एन्टरप्राइज के मिनिस्टर नहीं हैं। उनको मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बात तो ऐसी करते हैं, जैसे उनका यह डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरह से रन करता है और उनके इस डिपार्टमेंट में कोई गड़बड़ नहीं होती है। लेकिन मैं राजस्थान स्टेट रोडवेज का एक उदाहरण निवेदन करूंगा जिससे मालूम होगा कि किस तरह से टायर्स की खरीद करके बड़े बड़े ऑफिसर गोलमाल करते हैं। राजस्थान स्टेट रोडवेज़ को कुछ टायर्स खरीदने थे। उन्होंने फैसला किया कि सब टायर्स एक साथ खरीद लिए जायें क्योंकि खबर थी कि १ मार्च से रेट्स बढ़ जायेंगी। इसलिए टायर्स एक साथ खरीदने के लिए क्वोटेशन मांगे गये और दूसरी स्टेट्स से महाराष्ट्र रोडवेज़ और गुजरात रोडवेज़ से यह पूछा गया कि कौन से टायर्स सबसे अच्छे हैं। उन्होंने लिखा कि सीट टायर्स सबसे खराब हैं। इसके अलावा डनलप, फायर स्टोन और गुड ईअर अच्छे टायर्स हैं, इसके अलावा ताज्जुब की बात यह है कि सीट टायर की जो कीमत दिल्ली में है; वहां वह चालिस रुपये कम में मिलता है। मुझे हैरानी यह जान कर हुई कि रोडवेज के जो चेअरमैन साहब है कि उन्होंने अच्छे टायर्स के होते हुए भी सिर्फ सीट टायर्स के लिए बल्क ऑर्डर पेश किया। मैं नहीं समझ सका कि सीट टायर्स खरीदने का मकसद क्या था जब कि वह निम्न श्रेणी का था और जब कि दूसरी रोडवेज़ ने यह कह दिया था कि यह टायर सबसे निकम्मा है; जब आपके टेक्निकल एडवाइजर्स ने नोट भेजा था कि सीट टायर कम्पेरिटिवली दूसरे टायर्स से निम्न श्रेणी का है, तब भी बल्क ऑर्डर सीट टायर्स के लिए पेश किया गया और यह दलील दी गई कि चूंकि एक साथ टायर्स खरीदने थे, इसलिए सीट टायर्स खरीद रहे हैं। लेकिन मैं आपको निवेदन करूं कि २८ तारीख को ऑर्डर दिया तब १० टायर मिले और उसके बारह दिन के बाद बाकी के मिले। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह घटिया टायर्स खरीद कर रोडवेज़ के धन का दुरुपयोग किया गया है। मैं समझता हूं कि मिनिस्टर साहब, I will call him a showboy, वे यहां होते तो इन बातों की और ध्यान देते और हमें कन्विन्स करते और बताते कि इन चीजों में क्या राज था ?

श्री अध्यक्ष : श्री गंगासिंह !

श्री गंगासिंह (जायल) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री ने अगली साल का बजट पेश किया, उसमें उन्होंने यह कहा है कि इस असेम्बली का यह आखिरी बजट है। जब उन्होंने कहा कि असेम्बली का आखिरी बजट है तो हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि इस असेम्बली की पहली साल से यह जो पांचवां बजट पेश हुआ है उसके दरम्यान जो राज्य सरकार ने हर साल के अन्दर बजट पास कराया है उसमें कुछ उन्नति करके उनका जो मेक्सिम (maxim) है सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, उसको अचीव करने में वह कहां तक पहुँची है।

Page No. 46

(श्री गंगासिंह)

अध्यक्ष महोदय, १९६२ में जब हम एसेम्बली में आये थे, उस समय हमारा यह पहला बजट था और आज यह हमारा पांचवां बजट है। इस बजट के अवसर पर अगर मैं पिछले सारे बजटों का सिंहावलोकन करूं तो मैं यह देखता हूं कि जो पहला बजट हमारे सामने पेश हुआ उसके बाद से आज तक राजस्थान की आर्थिक स्थिति में कोई फर्क किसी प्रकार का नहीं आया है। आज हम देखते हैं की राजस्थान की आर्थिक स्थिति ३ पूंजी पर निर्धारित है।

(१) एडवान्सेज, जो आपको मिलते हैं,

(२) लोन्स देते हैं और तीसरा है

(३) ग्रान्ट्स-इन-एड।

अगर आप इन तीनों चीजों को इस मौजूदा बजट से निकाल दें, तो हम इस बजट को केआोस की नजर में लेंगे। मैं यह कहूंगा कि कोई भी राज्य हो उसकी आर्थिक परिस्थितियें मजबूत बनेंगी, तभी वह स्वावलम्बी हो सकता है और इसके लिए हमें अपनी स्वयं की, खुद की इन्कम को बढ़ाना चाहिए। और दूसरों से लोन्स, ग्रान्ट्स-इन-एड आदि के आधार पर अपना बजट निर्धारित रखती हैं वे सरकारें कभी स्वावलंबी नहीं बन सकतीं और मजबूत नहीं कहलातीं। ऐसी हालत में मैं आपको यह निवेदन करूंगा कि अगर आपको अपने यहां राज्य की इन्कम को बढ़ाना है तो आपको नोन टैक्सएबल रेवेन्यू की तरफ ध्यान देना होगा। आज तक राज्य सरकार जो अपने डेवल्पमेंट के संबन्ध में कार्यवाही कर रही है वे या तो टैक्सों से आने वाली आमदनी से या ऊपर मैंने पहले तीन प्रकार की आमदनियों के जरिये बताये हैं, उस पर यह सारा का सारा ढांचा जमा हुआ है।

मैं यह निवेदन करूंगा कि आपका और हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि जब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है तो हम नोन टैक्सेज की तरफ ध्यान दें और उससे राज्य का खजाना जो खाली है भरा जा सकता है और केवल ग्रान्ट इन एड और लोन्स आदि पर ही हम राज्य को चलाना चाहें तो हमें ऐसे राज्य को नहीं चलाना चाहिए।

जो बजट पेश हुआ है उसमें आपने इसको एक बेलेन्स्ड बजट की तारीफ में दिया है। यदि इस बजट को पूरी तरह से स्टडी किया जावे तो यह एक ऐसा बजट है जो बहुत बड़े घाटे का बजट है। आपने जो इसमें इन्कम और एक्सपेन्डीचर्स बताये हैं उनके आधार पर उनको आधार मानकर अगर उनकी संतुलित स्टडी की जावे तो यह बड़े भारी घाटे का बजट पेश हुआ है। यह सिर्फ आंकड़ों के आधार पर है, आप इस बजट को या तो सरप्लस की तारीफ में ले आवेंगे तो इससे यह संतुलित बजट नहीं हो सकता। आखिर में आपको यह देखना होगा कि जो इन्कम ला रहे है और जो एक्सपेन्डीचर करते उसका एक दूसरे पर असर हो तब हम उसको बेलेन्स्ड बजट की तारीफ में ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बजट में जो पेश हुआ है उसमें राजस्व में १ करोड़ ९३ लाख का घाटा और पूंजी खाते में १ करोड़ १४ लाख का घाटा इस तरह से दोनों मिलाकर ३.७ करोड़ का घाटा बताया गया है इसी तरह से इस घाटे की पूर्ति के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। इस ३.७ करोड़ का खर्चा बजट में है। आपने जो एस्टीमेट लगाया है

Page No. 47

(श्री गंगासिंह)

कि यह खर्चा इस प्रकार के एस्टीमेट से पूरा हो जावेगा। मगर मैं यह कहूंगा कि यह पूरा हो नहीं सकता। आपने यह एस्टीमेट लगाया कि १ करोड़ रुपया तो आप किफायत के तौर पर पूरा करलेंगे। मैं कहूंगा कि आप आखिर में कितना पैसा किफायत से पूरा कर लेंगे। आप किफायत को देखें। किफायत आपने पहले भी काफी की है। अगर आप बेलेन्स बजट को लेकर चलते हैं, तो मैं आपको कह सकता हूं कि ये आपके एक करोड़ रुपये आ नहीं सकते। अगर आप अपने बजट को बेलेन्स बजट नहीं मानें और इन्कम और एक्सपेन्डीचर कम बता कर यह बताना चाहते हैं कि यह पूरा हो जाएगा तो इसको मैं मानने को तैयार नहीं हूं। इसके अलावा १.१० करोड़ राजस्थान सेल्स टैक्स के आधार पर है। मगर उस पर अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि न मालूम क्या परिस्थितियें बनें। इस तरह मिला कर २७ लाख और मोटर विहिकल्स में टैक्सेज में जो परिवर्तन किया गया है उसके कारण ४७ लाख और बिक्री कर में जो चोरियां हो रही हैं उनको रोकने के लिए जो कदम उठाये हैं, उनमे ३० लाख और फसल के टैक्सों पर से १० लाख इस तरह से आपने अपने घाटे की पूर्ति बतालाई है।

अध्यक्ष महोदय, अगर इस सारे बजट का सिंहावलोकन करें और ठीक तरह से देखें तो मेरे ख्याल से यह एस्टीमेट घाटे को पूरा करने की बात कह रहे हैं वह कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिये मैं यह कहूंगा कि या तो आपका बजट पेश हुआ है वह गलत है, इसमें कहीं लीकेज है, उसके कारण आपको फायदा हो सकता है। अन्यथा आपने जो प्रोपोजल्स बनाये हैं। उस तरह से आप अपने घाटे को पूरा कर लेंगे, यह मुमकिन नहीं है।

इसके अलावा एक कर्जा जो ३३३ करोड़ का पेश किया गया है। अगर कोई भी इस बजट को इस समय देखे, कोई भी प्राग्त इसको देखे तो इसको देख कर यही महसूस करेगा कि यह दिवालियों का बजट है। करोड़ों रुपयों का यहां पर घाटा चल रहा है। इसलिये वहां के आदमियों के लिये सही तरीके से खर्च नहीं किया जा सकता। एज्यूकेशन पर आप ज्यादा इन्कम नहीं दे सकते। जबकि चारों तरफ से घाटे का बजट दिखाई दे रहा है उस समय वित्त मंत्रीजी ने हाउस के सामने साबित किया कि आज से इसमें घाटा न समझिए। यह घाटा नहीं है। यह मुनाफे का बजट है। उन्होंने इस घाटे को इस तरह से समझाया कि २४८ करोड़ का तो माल राजस्थान सरकार के पास है और १०७ करोड़ राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और स्टेट रोडवेज आदि निगमों के पास में है। ऐसी स्थिति में हमें दुख प्रकट करने की बात नहीं है। हमारे पर ३३३ करोड़ का कर्जा है तो भी हम नफे में हैं। अगर आप इस प्रॉपर्टी की जांच फरमावें तो आपको मालूम होगा कि जहां पर आपके ये पैसे इन्वेस्टमेंट किये हुए हैं, वहां से रिटर्न आने की उम्मीद नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि रिटर्न ही नहीं आएगी बल्कि उनकी स्थिति और भी डिटरियोरेट हो रही है। ऐसी हालत में मैं नहीं कह सकता कि यह ३५५ करोड़ की प्रॉपर्टी मौजूद है और ३३३ करोड़ का कर्जा देना है। ऐसी स्थिति में हम नफे में चल रहे हैं।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान में लोगों की हालत यह है, यहां पर

Page No. 48

(श्री गंगासिंह)

पर-कैपिटा इन्कम बहुत कम है और उन पर टैक्सेस बहुत ज्यादा लगाये हुए हैं। काश्तकार पर लैन्ड रेवेन्यू बहुत ज्यादा चल रहा है तो ऐसी हालत में मैं नहीं कह सकता कि यह सारा बजट किस तरह से राहत लोगों को पहुंचा सकता है। इसलिये मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि आपके टैक्सेज इस हद तक बढ़ चुके हैं कि अब जनता इन टैक्सों के भार को संभाल नहीं सकती है। मैं कहूंगा कि आपने जो टैक्सेज पहले से लगा रखें हैं, उनको सही तौर से वसूल करने की व्यवस्था कर लें तो आपको किसी प्रकार के नये टैक्सेज लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अरबन एरिया में जो जमीन है, उसको देखें और मनी लेंडिंग बिल है उसकी आमदनी को देखें तो आपको मालूम होगा कि जो एस्टीमेट आपने आमदनी का लगाया है, उससे चौथाई इनकम आपको नहीं मिलती है। आपने इसका कारण यह बताया कि आपने इसके लिए अभी तक रूल्स नहीं बनाये हैं। आखिर हम एसेम्बिली में बिल पास करते हैं तो हमको चाहिए कि हम उसके रूल्स भी जल्दी से जल्दी बनाएं। मार्च में बिल पास हुआ और अक्टूबर में आपके रूल्स नहीं बने। मैं यह कहूंगा कि यह सारी कार्यवाही सरकार की कमजोरी से है या उस पर निगाह नहीं रखते हैं इस कारण से हुई है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को बजट की अहमियत को देखते हुए काम करना चाहिये, जिससे सारा फाइनेन्स इस स्टेट का खतम नहीं होकर, धीरे-धीरे बढ़ता चला जावे।

अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि यदि इस स्टेट को फायनेन्शियली साउन्ड बनाना है, अगर इसकी आर्थिक स्थिति को अच्छा करना है तो आपको इसकी नॉनटैक्स रेवेन्यू की ओर ध्यान देना होगा नहीं तो इस स्टेट की आर्थिक स्थिति कभी अच्छी नहीं हो सकती। नॉनटैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए आपके पास बहुत अच्छी-अच्छी खानें हैं, बड़े-बड़े फॉरेस्ट्स हैं और इन सब के अलावा आपके पास बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इलाहबाद में आपकी स्टेट की प्रॉपर्टी है, बनारस में प्रॉपर्टी है, आगरा में स्टेट की प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज से जैसे एक आदमी अपनी इन्डिविज्युअल प्रॉपर्टीज से पैसा कमाता है, उनकी तरक्की करके अपनी आमदनी को बढ़ाता है, उसी प्रकार आप भी इन प्रॉपर्टीज को बढ़ावा देकर, इनमें इस प्रकार की तरक्की करके स्टेट की आमदनी को बढ़ाइये। आगरा, इलाहबाद, बनारस में आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वे बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, और बहुत ही अच्छी साइट्स पर वे प्रॉपर्टीज हैं, उन पर दुकानें बनायें, और काम करें जिनसे कि राजस्थान स्टेट की लाखों रुपयों की आमदनी हो सके। परन्तु देखा जाय तो दूसरे प्रान्तों में जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, उनकी तरफ आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया है और इस कारण लाखों रुपयों की आमदनी हमारी स्टेट को इनसे हो सकती थी, वह अभी तक नहीं हुई है। हमारे पास जो फीगर्स आये हैं हमारे पास जो सूचनाएं आई हैं, उनके आधार पर तो मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान के साथ धोखा किया है। जहां लाखों की इनकम इन प्रॉपर्टीज से हो सकती थी, मामूली पैसों में उस प्रॉपर्टी को बेच दिया असेम्बली में यह सवाल नहीं लाया गया, केबिनेट तक में यह सवाल नहीं लाया गया

(श्री गंगासिंह)

और एक मिनिस्टर ने ही बाला-बाला, उस प्रॉपर्टी को बेच दिया। हाईकोर्ट में आपके दावे गये थे, बिना कारण ही उन दावों को हाई-कोर्ट से वापिस ले लिया, लाखों रुपया स्टेट का हाई कोर्ट में खर्च हुआ और लाखों रुपयों की इन्कम इन प्रॉपर्टीज़ से हो सकती थी, वह इन्कम नहीं कर के कौड़ियों के मोल उन प्रॉपर्टीज़ को बेच कर आपने स्टेट एक्स्चेकर को बहुत नीचे गिराया है।

इसके साथ ही साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ ऐसे मुद्दों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिन मुद्दों पर बार-बार दलीलें होती हैं, उन मुद्दों को राजस्थान सरकार सही तौर पर टेकल नहीं कर सकी है। उन मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा है फेमीन का। इस प्रान्त का बहुत बड़ा भाग ऐसा है जहां ज्यादातर फेमीन पड़ते हैं। दूसरे-तीसरे साल तो उन भागों में फेमीन पड़ ही जाते हैं। जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर आदि ऐसे डिस्ट्रीक्ट्स हैं जिनमें दूसरे-तीसरे साल फेमीन पड़ जाते हैं और इनकी ओर राजस्थान सरकार का ध्यान आज से ही नहीं १९५२ की असेम्बली से, जब कि मैं भी इस असेम्बली का मेम्बर था, तभी से लगातार केवल अपोजिशन के मेम्बर्स की तरफ से ही नहीं, अपितु, उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों की तरफ से भी राजस्थान सरकार का ध्यान निरन्तर आकर्षित किया जाता रहा है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। पर सरकार ने जिस तरह से इस ओर ध्यान देना चाहिये था नहीं दिया है। दैव दुर्विपाक से कभी कोई ऐसी घटना हो सकती है पर १९५२ से १९६६ तक १४ साल के अन्दर फेमीन के बारे में राजस्थान सरकार ने कुछ नहीं किया है। वैसा भी राजस्थान का कम खर्च नहीं हुआ है, फेमीन फंड जिसमें ४० लाख से बढ़ते-बढ़ते ९० लाख दे रहे हैं परन्तु किस तरह से ऐसा कार्य किया जाय जिससे फेमीन हो तो एक ही दम एक साल में स्टेट एक्स्चेकर पर ज्यादा भार नहीं पड़े, इस बारे में आज तक राज्य सरकार की ओर से नहीं सोचा गया है। जैसे चारे का प्रश्न है, अनाज का प्रश्न है और और प्रश्न आते हैं तो इनका स्टोरेज अगर काफी तादाद में जमाने में ही कर लिया जाय तो चारे की कमी नहीं रहती है। अकाल पड़ गया तो उसी समय सारे का सारा चारा खरीदें, सारे का सारा अनाज खरीदें, सारे के सारे और काम करें तो इससे स्टेट एक्स्चेकर पर बड़ा भार पड़ता है। तो मेरा निवेदन है कि राजस्थान के लिये यह एक परमानेन्ट समस्या है, इसको परमानेन्टली हल करने के लिए कोई न कोई परमानेन्ट कदम उठाइये, हालांकि इसमें सक्सेसफुल हों या नहीं हों, यह आपकी कार्यक्षमता और कार्यतत्परता पर निर्भर करता है, पर यह कदम उठाना राजस्थान के हित के लिये बहुत ही जरूरी है।

जहां तक एग्रीकल्चर का सम्बन्ध है, हमारा यह राज्य भी कृषि-प्रधान राज्य है इसलिये हमारे इस प्रान्त में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना बहुत ही जरूरी है। इस समय इस सम्बन्ध में मैं विशेष अर्ज न करके राजस्थान केनाल की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। राजस्थान केनाल बन रही है, हमें खुशी है, हमें इससे बहुत कुछ फायदा होगा पर स्कीम के माफिक जिस द्रुतगति से राजस्थान केनाल तैयार होनी चाहिए, नहीं

(श्री गंगासिंह)

हो रही है। जो फाइनेन्सेज उसमें लगा रहे हैं उनमें आप इकोनामिकली नहीं चल रहे हैं। एक साल में जो कार्य करना है उसमें १० साल लगा देते हैं, तो इन्ट्रेस्ट का बहुत नुकसान होता है और रिर्टन्स भी जो हमें जल्दी मिलने चाहिए वे नहीं मिल पाते हैं, इससे स्टेट की आर्थिक स्थिति को बड़ा नुकसान पहुंचता है। अब यह राजस्थान केनाल आप सेंटर को दे रहे हैं तो सेन्टर से अनुरोध करें कि इसे जल्दी से जल्दी पूर्ण करे और इसमें जो राजस्थान का १५ करोड़ रुपया खर्च हो चुका है ....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : १५ करोड़ नहीं ३५ करोड़ खर्च हो चुका है।

श्री गंगासिंह : हां, ३५ करोड़ रुपया खर्च हुआ है, उसका एडजस्टमेंट सेन्टर से अवश्य करेंगे। वह मनी आपको देंगे, इस बारे में जरूर बातचीत करेंगे।

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान केनाल में जो मशीनरी वगैरह लगाई है, उसके कारण राजस्थान सरकार की असावधानी से राजस्थान को लाखों रुपयों का घाटा हुआ है। बुलडोजर, ट्रैक्टर्स वगैरह खरीदे हैं वे ७ लाख की कीमत के हैं. वे खराब होने के कारण बेकार पड़े हैं, हमारे कुछ काम नहीं आ रहे हैं। खराबी का कारण यह है कि इनके स्पेअर पार्ट्स नहीं मिलते हैं। जो मशीनें आपने खरीदी है उस समय आपने यह देखने की सावधानी नहीं बरती कि वे मशीनें पहाड़ी इलाकों के लिए उपयोगी हो सकती हैं। आपको यह देखना चाहिये था कि आपका प्रान्त एक रेतीला प्रान्त है, उसमें ये मशीनें कैसे उपयोगी हो सकती हैं ? आपकी इस असावधानी के कारण ७ लाख की मशीनरी ७ साल से बेकार पड़ी हैं। उस पर बिना मतलब के आपने कितना इन्ट्रेस्ट दे दिया। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह स्टेट एक्सचेकर पर बहुत ज्यादा तादाद में वजन डालने वाली घटनाएं हैं उनके सम्बन्ध में सरकार को जागरूक रहना चाहिए, जिससे कि स्टेट एक्सचेकर पर व्यर्थ का वजन नहीं पड़े और जो मशीनरी हम लें, उसका सदुपयोग कर सकें।

अब मैं देवस्थान की प्रॉपर्टी के सम्बन्ध में जो दुखद कार्यवाही की गई है, उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जोधपुर स्टेट की गोरख टीला नामकी प्रापर्टी देवस्थान की थी, वह २० लाख की प्रॉपर्टी थी, उस समय २० लाख की कीमत की थी, इस समय के भावों से तो वह ४० लाख की प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को आपने गोरख सम्प्रदाय को मुफ्त में दे दिया। किस तरह काम होगा, किस तरह रेगुलेशन होगा, यह कुछ नहीं देखा। एक तरफ तो आप कहते हैं कि स्टेट के पास जो प्रॉपर्टी है या जो प्रॉपर्टी आवेगी, उसको अच्छी तरह मेन्टेन करेंगे, उसको भावनावश बर्बाद नहीं करेंगे, उसका अच्छा उपयोग करेंगे, और दूसरी तरफ ४० लाख की कीमत की प्रॉपर्टी इस तरह मुफ्त में दे देते हैं।

(१ म. प.)

उस प्रापर्टी का सम्बन्ध किसी धार्मिक चीज से नहीं है, वह तो ऐसी प्रापर्टी है जिस पर गोरखनाथ के चेले चांदी हो सकते हैं। इसको इम्प्रूव करके इसमें

Page No. 51

(श्री गंगासिंह)

काम करें। वैसी परिस्थिति में मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह से इस प्रॉपर्टी को मुफ्त में दे दिया। यह बनारस में है। ऐसी प्रापर्टीज इलाहबाद के अन्दर देखी जाय तो इलाहाबाद का इम्पार्टेंट पोरशन आपकी प्रोपर्टी थी, जहां पर अगर आप दुकानें बनाते और बेचते तो करोड़ों रुपये की आमदनी थी, जैसे एक आदमी करता तो नेट आमदनी उसका माहवार हजारों रुपये की थी। उस प्रॉपर्टी को आपने बेकार कर दिया। कहीं यू० पी० के मंत्रियों की इन्फलूएंस हो गई, पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए उससे इन्फ्लुएंस हुए, आपने उसको बुरी तरह से बेकार कर दिया। अगर उसका ध्यान रखते तो लाखों रुपये जो आप टैक्सेज के रूप में वसूल करते हैं जनता से वे नहीं लेने पड़ते।

जो खाली प्लाट्स हैं तो जो आमदनी होनी चाहिए थी वह बहुत गिरी। जेल फैक्टरीज के सम्बन्ध में निवेदन है कि काफी समय तक यह आमदनी का सोर्स था। दो साल पहले इसके अन्दर लाखों रुपये का फायदा हो रहा था। मैं देख रहा हूं कि इस समय जेल फैक्टरीज में जो आमदनी हो रही है, मिसमेनेजमेंट ही इसका कारण है। बजट एस्टीमेट्स जो आप कर रहे हैं, उससे धीरे धीरे आमदनी कम हो रही है।

इसके अलावा एक्सपेरीमेंटल फार्मिंग की तरफ ध्यान दिलाता हूं कि उससे नुकसान होने की गुंजाइश नहीं, वहां पर पानी मौजूद है, सब कुछ है फिर भी आपका बजट जो पेश हुआ है, पिछले बजटों से लगातार एक लाख, डेढ़ लाख की आमदनी कम हो रही है। इसका कारण सिवा मिसमेनेजमेंट के और कोई नहीं हो सकता। पी० ए० सी० ने भी जो रिपोर्ट दी है उन्होंने भी इसको मिसमेनेजमेंट की संज्ञा देकर सरकार का इस सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित कराया है।

माइन्स हैं जो फाइनेन्सेज के बैकबोन हो सकती हैं। १९५२ से इन माइन्स पर सरकार कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। जिस किसी का फायदा करना हो उसका किया जाता है और माइन्स की लूट होती है। जो खान ५० हजार के अन्दर भी कई ले सकते हैं तो वह पांच हजार में चली जाती है अगर आप इसकी ओर ध्यान देते तो आपको काफी इन्कम हो सकती है। पलाना कोल माइन्स को तरफ मैं खासतौर से आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। उसमें काफी लाभ हो सकता है। परन्तु दुःख की बात है कि पिछले साल इसके अन्दर करीब ९ लाख रुपये का घाटा हुआ। इसके साथ साथ सरकार की तरफ से यह भी सवाल चल रहा है कि इन माइन्स को ओपन किया जाय या नहीं। इसके लिए टेक्निशियन्स और एक्सपर्ट्स की ओपीनियन मांगी जा रही है। परन्तु अजीब बात है कि वह अभी तक पेंडिंग है। अगर वह ओपन हो जाती है तो केवल खान से ही सम्बन्ध नहीं है, दूसरी फैक्टरीज से सम्पर्क होकर इससे लाखों रुपये का फायदा हो सकता है।

इसके अलावा दौसा के पास टाकिरी नाम का एक स्थान है वहां पर सरकार ने तय किया कि पट्टियों की खान चलाई जाय उसके लिए एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट थी कि सरकार द्वारा न चलाकर लीज पर दी जाय। पर सरकार ने कहा नहीं हम लीज पर नहीं देंगे क्योंकि १५ साल में बहुत

Page No. 52

(श्री गंगासिंह)

आमदनी होगी लेकिन लाखों रुपये खर्च करने के बाद सरकार ने एकदम इसको खतम कर दिया। लीजं के अन्दर जो आमदनी होने वाली थी वह भी गई, इन्वेस्टमेंट गया और वहां से कुछ आमदनी नहीं हो रही है।

वनों के सम्बन्ध में निवेदन करना है कि उससे चाहिए कि इन्कम को बढ़ाया जाय, इससे आमदनी हो सकती है। लगातार हिन्दुस्तान के अन्दर लकड़ी की कमी की गुंजाइश है और हमारे यहां यह काफी तादाद में मिल सकती है। इससे टिंबर मिल सकता है। अगर वनों को सुरक्षित किया जाय तो लाखों रुपये की आमदनी बजट पर अपना असर डाल सकती है।

सेल आफ लैंड की ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। यहां पर सेल ऑफ लैंड की तरफ बिल्कुल तवज्जह नहीं दी गई यहां तक कि मुफ्त के अन्दर जमीन दी गई। सरकार ने पैसा लगाया है, नहरी इलाके में उसके अन्दर जमीन से इन्कम होगी। इसके साथ में आमदनी सरकार की हो सकती है।

अब जो बजट पेश हुआ है उसके अन्दर आपने लिखा है सेल बराबर नहीं की, ऐसी गल्तियां इसमें नहीं होनी चाहिए।

इसके साथ बजट भाषण के अन्दर पाकिस्तान की ओर ध्यान अकर्षित किया था कि पाकिस्तान के हमले के कारण भी इस बजट पर असर पड़ा। यह जरूरी था कि पाकिस्तान के हमले के विरुद्ध हम अपना सहयोग देते। इस सहयोग का इस बजट पर असर पड़ा। परन्तु दुःख की बात यह कि अब भी जिस समय ताशकंद घोषणा के अन्तर्गत जब सेनाएं पीछे हटी हैं, हमने ११ मार्च को देखा एक पाकिस्तान का ब्रिगेड जंगीला गांव में, अहमद तालाब, गडरा सिटी इन गांवों के अन्दर ३८ मीलों का एरिया लगता है। वे ब्रिगेड के आदमी अपने अपने बोर्डस् पर हैं उन आदमियों को चेलेंज देते हैं कि हम थोड़े ही दिनों में फिर आने वाले हैं। खैर, यह सवाल नहीं है; लेकिन उनका एक ब्रिगेड इस बोर्डर पर लगा दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पाकिस्तान की नीति क्या हो सकती है और समझौते को कहां तक मानेंगे या नहीं, पर राजस्थान सरकार का यह पुनीत कर्तव्य हो जाता है कि यह जागरूक रहे और ब्रिगेड वगैरह इस बोर्डर एरिया पर जो करीब ३८ मील का है उसकी ओर पूर्णतया सतर्क रहें।

इसके अलावा उमरकोट में भी उन्होंने अपनी सेना ३२ मील के अन्दर ताशकंद घोषणा के बाद में लगाई है। तो इन घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। हालांकि इनका बजट से सम्बन्ध नहीं है, आपकी जो आर० एस० सी० बोर्डर पर लगी हुई है उनको सतर्क रहना चाहिए।

अंत में यह जो बजट पेश हुआ है उसको मैं घाटे का बजट कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज उपाध्यक्ष।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : माननीय अध्यक्षजी ....

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करलें।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय !

श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने १९६६-६७ के बजट पर वाद-विवाद चल रहा है। बजट के विषय में मैं अर्ज करूं कि इस बजट को क्या संज्ञा दी जाय, इस पर सोचना है। क्या यह समाजवादी बजट है, क्या यह पूंजीवादी बजट या लालफीताशाही का बजट है ? किस हैसियत का है ? विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा इस बजट पर टीका-टिप्पणी सुनी तो तो मुझे ताज्जुब हुआ। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, देश स्वतंत्र होने के बाद वहां किस प्रकार सड़कें बनी हैं, किस प्रकार शिक्षा का देहात में प्रबन्ध हुआ है, किस प्रकार लाखों किसानों को भूमि दी गई है, किस प्रकार चिकित्सा-व्यवस्था हुई है, ये सारी की सारी बातें जब हम पहले स्वतंत्र नहीं हुए थे और उस समय जो कुछ व्यवस्था थी उसको देखें और स्वतंत्र होने के बाद जो आज व्यवस्था हुई है उसको देखते हैं तो काफी हेर फेर नजर आती है, काफी प्रगतिशीलता आई है।

यह सही है कि हमारा देश समाजवाद की ओर बढ़ा है, किन्तु कुछ लालफीताशाही की वजह से पूंजीपतियों की जेब में भी बहुत कुछ पैसा दे चुके हैं। बजट से हमारे देश के चरित्र पर काफी असर पड़ता है। एक भूखा आदमी अर्से तक भूखा रहे और उसके पश्चात् उसको खाने को दिया जाय, खाने के लिये चिंतातुर हो, बराबर उसकी मांग बढ़ती रहेगी, यही हाल यहां हुआ है। हमारा देश बहुत अर्से तक गुलाम रहा। जब हमारा देश आजाद हुआ तो गांवों में चिकित्सा की व्यवस्था हुई शिक्षा की व्यवस्था हुई। यातायात की व्यवस्था हुई। पहले कोई भी आदमी अपने अधिकार को जोर से बोलकर शासक के सामने नहीं कह सकता था, मानवता सिसकती थी, वे ही आज कहते हैं कि यह दिवालिया बजट है, निकम्मी सरकार है, यह कुछ नहीं कर सकती है ! मुझे यह सुन कर सख्त अफसोस होता है। यह जरूर है कि जो हमारी आय के साधन हैं उनको जुटाने का प्रयत्न किया है, लेकिन हमारी कुछ असावधानी कहा जाय, हमारी मशीनरी है वह जागरूक नहीं है, जितनी आय के साधन बनाये उनकी पूरी आमदनी पर्याप्त मात्रा में हमारे खजानों में नहीं आती, यह अवश्य है। उदाहरण के लिए अर्ज करूं कि बहुतसी बसों का टैक्स बस मालिकों की जेब में पड़ा हुआ है, जनता से टैक्स वसूल कर लिया जाता है और सरकार उनसे पूरा नहीं ले पाती है। यह कानूनी अड़चन है ऐसा बताया जाता है।

१८ वर्ष पहले की दास्तान अर्ज करूं। बहुत से हमारे देहात के लोग बोहरा के अधीन रह कर कर्जदार होते थे लेकिन बोहरा उनका कर्जदार है। बोहरा के पास उनकी धरोहर है। बोहरा की धरोहर उनके पास नहीं है। हमारा किसान आर्थिक रूप से आगे बढ़ा है। खेती-बाड़ी में तरक्की हुई है शिक्षा में भी तरक्की हुई है। जिन गांवों में दस-दस, बीस-बीस घर हैं वहां पर भी प्राइमरी स्कूल खुले हैं। स्वतन्त्रता के पहले दस हजार की आबादी में भी प्राइमरी स्कूल नहीं था; आज वहां बिजली पहुंच रही है, सड़कें बनी हैं। यह सब करने पर इसको समाजवादी सरकार नहीं कहा जायगा तो क्या कहा जायगा ? हमारी कुछ असावधानी के कारण या लालफीताशाही के कारण पूंजपतियों की जेब में हमारी आय का बहुत हिस्सा जा रहा है, उसको देखना चाहिये।

टैक्स का जहां तक सवाल है, लाखों रुपया नॉन-टैक्सबल रेवेन्यू के भी आ सकते

(श्री चतुर्भुज उपाध्याय)

हैं लेकिन सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही है। उदाहरण के लिये निवेदन करूं, सिंचाई के क्षेत्र में कमान्डिंग एरिया है, बिला नाम पड़ा हुआ है काश्तकारों को उसको दिया जाय तो उत्पादन बढ़ सकता है और काफी प्रिमीयम सरकार के खजाने में आ सकता है। लेकिन सरकार को बार-बार रिक्वेस्ट करने पर भी गम्भीरी प्रोजेक्ट का और सोनिमारा प्रोजेक्ट का प्रिमीयम अभी तक तय नहीं हुआ है और इसी प्रकार से दूसरी जगहों के भी नहीं हुए होंगे। तो सरकार से निवेदन करूंगा कि उनके प्रीमियम तय करके लाखों रुपये की आमदनी सरकार में लायी जाय।

वन सम्बन्धी भी निवेदन करूं कि हमारे देहाती क्षेत्र में पहाड़ी इलाका है, सड़े वगैरा के लिये सौ सौ बीघे के प्लाट दिये जाते हैं इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में लाखों रुपयों के प्लाट दे देते हैं। यदि सड़े वगैरा के लिये जिससे खेतों की रक्षा की जा सके, ठीक प्रकार से व्यवस्थित तरीके से नियम बना कर दें तो लाखों रुपयों की बचत हो सकती है। लेकिन सरकार ने एक ही ढर्रा पकड़ रखा है कि देना है।

खानों के सिलसिले में अर्ज करूं कि हर प्रकार की खानें हमारे यहां हैं। जैसे तांबा, लोहा। खास कर हमारे यहां पत्थर की खानें हैं। काला संगमरमर का बढ़िया पत्थर हमारे यहां निकलता है। उसका ठीक प्रकार से विकास किया जाय तो सरकार को उससे काफी इनकम आ सकती है और फॉरेन भी वह पत्थर भेजा जा सकता है।

इसी प्रकार व्यय के लिये अर्ज करूं कि व्यय के साधनों पर बहुत कुछ देखभाल हमारी नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत सी जगह अननेसेसरी ऑफिसेज खुले हुए हैं। काम रुपये में एक आना भर है और पन्द्रह आना काम नहीं है और बैठे रहते हैं। कितने कागज निकालते हैं, कितना काम करते हैं या नहीं करते हैं, इसका सरकार को मूल्यांकन करना चाहिये। बहुत सी जगह देखते हैं कि आठ घंटा ऑफिस का टाइम है, दो घंटे अटेन्ड करके चले जाते हैं, हजारों किसान उनके दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, साधारण काम के खातिर भी पेशियां दूसरी देदी जाती हैं। सरकार को देखना चाहिये कि कहां कहां सुचारु रूप से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, कहां कहां पर कितने अर्से से कागज पड़े हुए हैं। सरकार को इस ओर पूरी तौर पर ध्यान देना चाहिये।

१९६२-६३ में, एक विधायक के नाते मैंने अपना कर्त्तव्य समझा कि सरकार को नुकसान हो रहा है, एक केस सरकार के पास भेजा कि अवैधानिक तौर पर जंगल की कटाई से सरकार को एक लाख रुपये का नुकसान हुआ। मैंने सरकार को मौके पर जाकर बताया। ताज्जुब फरमायेंगे, अध्यक्ष महोदय, उस रेन्जर को सस्पेन्ड कर दिया, कुछ दिन बाद उसको बहाल कर दिया, दो व्यापारियों को बीस-बीस हजार के नोटिस दे दिये और कुछ दिनों के बाद उनको माल दे दिया गया और अब तक वह केस सरकार के विचाराधीन है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०): किसी मंत्री के रिश्तेदार होंगे?

श्री चतुर्भुज उपाध्याय: किसी मन्त्री के रिश्तेदार नहीं हैं। केवल हमारी असावधानी है।

(श्री चतुर्भुज उपाध्याय)

ये ऐसे मामले हैं। एक बीज-खाद का मामला अर्ज करूं। एक बोहरा कुछ काश्तकारों को लेकर कोआॅपरेटिव बना लेता है। सौ मन बीज, अच्छा बीज जाता है १९५७, में कोआॅपरेटिव बनती है। उस बीज को वह बाजार में बेच देता है किसान से अंगूठे ले लिये जाते हैं। वह बोहरा सारा बीज खा जाता है। सरकार के बार बार मांगने पर भी नहीं देता है। मैंने सरकार से निवेदन किया कि गबन है, पी० डी० आर० में वसूली करो। भ्रष्टाचार निरोधक महकमे को भी लिखा और उसने माना कि वास्तव में उसने गबन किया है, लेकिन उस कार्यवाही को पुलिस विभाग चित्तौड़गढ़ ने दबा रखा है।

इस तरह से आप भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देते हैं तो इससे दूसरे आदमी नकल करते हैं। दूसरे यह सोचते हैं कि अपन भी क्यों न इस प्रकार का कार्य करो, कुछ होता जाता नहीं। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इस बारे में सरकार जागरूक होकर ठोस कदम उठाये।

मिसाल आपको अर्ज करूं। एक ब्राह्मण का लड़का अपने पांच साथियों के साथ बाहर गया। ब्राह्मण के लड़के के हाथ से एक गधा मर गया। घर आकर उसके साथियों ने कहा, पंडितजी एक गधा मार दिया गया है तो पंडितजी ने अपने पोथी-पत्रे निकाल कर देखा; यह तो बड़ा भारी पाप किया है, इसके लिये हरद्वार जाना पड़ेगा, फलां फलां प्रायश्चित करना पड़ेगा। लेकिन जब लड़कों ने कहा वह गधा तो आपके संतोष ने मारा है। तो पंडितजी बोले पांच सात लड़के एक संतोष गधा मारने का नहीं है दोष। सरकार को चाहिये कि ऐसा नहीं करे जो भी दोषी हो उसको सजा दे ताकि विरोधियों की जुबान को ताला लग सके जो लोग यह कहते हैं कि यह तो दिवालिया सरकार है, करोड़ों रुपयों का कर्जा कर रहे हैं। कहां से चुकायेंगे ?

अभी तो आप लोग प्राथमिक स्कूल के बच्चे हो, आपको पता नहीं राजनीति क्या होती है। आपने राजनीति नहीं सीखी है, राजनीति में और जनतंत्र में टैक्स भी लगते हैं, जनतंत्र में प्रगति भी होती है, यह आप निश्चित तौर पर मान कर चलें। आप हमारे मुकाबले साठ वर्ष बाद आ सकेंगे अभी तो आप इसमें केवल बच्चे हो।........

श्री श्रवणलाल : आप तो जरूर नये गधे हो।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, अकाल के बारे में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किये। जो अकाल-ग्रस्त एरिया है उस जगह को सर्वे की जाय। मैं सही अर्ज कर रहा हूं, चित्तौड़ जिले के कुछ गांव ऐसे हैं जहां अकाल है, लेकिन उसको अकाल-ग्रस्त एरिया नहीं माना। by the way उन दिनों मैं वहां नहीं था। मुझे मालूम हुआ कि उस इलाके में केवल पांच परसेंट भी रबी की फसल नहीं हुई, वन फोर्थ खरीफ की फसल नहीं, पीने के पानी की मुश्किल है। मैंने अकाल मंत्री महोदय से अर्ज किया, जिला कलेक्टर को लिखा, लेकिन अभी तक वहां राहत का सवाल नहीं आया। मेरा अर्ज करना यह है कि समय चूक गया। कुए में पानी नहीं है, वहां के लिये पीने के पानी की व्यवस्था हो; इसके लिये वहां आप कम्प्रेसर भेजें, तकाबी आदि

(श्री चतुर्भुज उपाध्याय)

की सहायता दें ताकि वहां के लोगों को अकाल से राहत मिल सके।

इसके साथ साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि चित्तौड़ की सड़कें हैं उनमें कई गड्ढे पड़े हुए हैं लेकिन उनकी मरम्मत का कोई इन्तजाम नहीं। आप यदि नई सड़कें नहीं बनाते हैं तो कोई बात नहीं' लेकिन जो सड़कें मौजूद हैं उनकी तो आप मरम्मत करवाते जाइये ताकि वे ज्यादा खराब न होने पायें। इसके साथ-साथ इन सड़कों के बीच में जो किसानों की जमीन आई है उनके मुआवजे के लिए प्रार्थना करते मुझे काफी अर्सा हो गया, मुआवजा तो देना उनको दूर रहा उनसे रेवेन्यू हासिल लिया जाता है। जमीन का मुआवजा नहीं, लगान जारी है। इस तरह से सड़कों में आई हुई जमीन का, सिंचाई के इलाके में आई हुई जमीन का मुआवजा दिया जाना चाहिये।

सिंचाई के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं; जहां एक ओर पानी की कमी है, दूसरी बेड्स पर नदी बारह महीने बहती है। आसपास कूओं में उसका सेजा नहीं रहने के कारण नदी का पानी बेकार जाता है। चित्तौड़ से लगाकर त्रिवेणी तक पानी इसका खाली बहता रहता है। इसके दोनों किनारों पर हजारों एकड़ जमीन बिखरी पड़ी है। उत्पादन की दृष्टि से, किसानों को रोजी-रोटी देने की दृष्टि से लिफ्ट इरिगेशन द्वारा इस पानी को काम में लिया जा सकता है, जमीन को आबाद कराया जाय और उस पानी का उपयोग किया जाय।

चित्तौड़ के पास सादी का तालाब एक पहाड़ी इलाका है। इसके चारों ओर पहाड़ का परकोटा आया हुआ है। उस परकोटे पर खेती वाड़ी करते हैं। जनतंत्र होने के बाद वहां स्कूल खुले हैं, लेकिन आवागमन के साधनों की कमी है। मन डेढ़ मन बोझा लेकर पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है इसलिए सरकार को कुछ आवागमन के साधन जुटाने चाहिये। यह सरकार की मेहरबानी है कि दो माइल सड़क चौथी योजना में सरकार ने मंजूर की है; आशा है, इसे जरूर पूरी करायेंगे। मोटे रूप में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, वहां के लोग मानो कोहकाफ में रहते हों।

इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि हमें नोन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिये; वन-सम्पदा है, खनिज सम्पदा है—ये जो साधन हैं इनसे आय बढ़ाने के उपाय किये जाने चाहिये। मेरे यहां पर फोरेस्ट है। उसमें फोरेस्ट और सेटलमेंट में आपस में मिलान नहीं हो पाया है बहुत सी रेवेन्यू की भूमि फोरेस्ट में है तो बहुत सी फारेस्ट की भूमि रेवेन्यू में बताई गई है, इस तरह से काफी भूमि पर दोहरे महकमे का अधिकार चला आ रहा है। बहुत से कागजात मैंने जिलाधीश महोदय के सामने और तत्सम्बन्धित मंत्री महोदय के सामने भी रखे, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं हो पाया। कम से कम मेरा यह निवेदन है कि जो कुछ हम रिक्वेस्ट करें उसका समय पर जवाब तो मिल जाय, 'हां' या 'ना' कोई भी हो, ताकि हमें सन्तोष हो सके। पांच-पांच साल से गबन के मामले चल रहे हैं, खाद-बीज के मामले चल रहे हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पाना गलत बात है। इतना ही मैं अर्ज करके इस बजट का समर्थन करता हूं। गरीबों को आप ऊंचा

(श्री चतुर्भुज उपाध्याय)

उठायें। पूंजीपति की जेब में जो आपकी असावधानी से पैसा जा रहा है उसको रोका जाय और गरीबों को उनके शोषण से रोका जाय। इतना ही निवेदन करते हुए मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री प्रभुलाल 'सेन्टर' (खानपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिन माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं वे सदन में उपस्थित हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है।

अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि आज के विश्व में अमेरिका और रूस जैसे देश चन्द्रलोक की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, वहां हमारे राष्ट्र की आर्थिक हालत ऐसी है कि हम अभी साइकिल से ही चल रहे हैं। इसके साथ साथ मैं हमारे वरिष्ठ नेताओं से अर्ज करना चाहता हूं, यह अन्तिम अवसर है, इन्दिरा जैसी शक्ति और कामराज जैसे व्यक्ति संगठन और सरकार में लगे हुए हैं। ऐसे समय में अगर हम हमारी पॉलिसी में फेल होते हैं और यदि हमने अपने बजट पर पुनः विचार नहीं किया तो यह बजट हमारे लिये खतरनाक हो सकता है।

मैं, अध्यक्ष महोदय, बजट की इस पृष्ठ-भूमि में दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। पहला तो यह है कि अनुशासन पर ज्यादा से ज्यादा व्यय किया जाय, चाहे वह संगठन में हो, चाहे सरकार को चलाने में और चाहे स्कूलों में।

महिला जगत में भी हमें काफी सुधार लाना है, ताकि हमारी शक्ति मजबूत हो। महिलाओं का जिस प्रकार से विकास होना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है; पांच परसेन्ट भी नहीं हो पा रहा है।

तीसरा, जहां तक कृषि की पैदावार बढ़ाने का सवाल है हमारे वयोवृद्ध वरिष्ठ संगठन के नेताओं ने समय समय पर इस पर विचार किया है, इस बारे में कलेक्टरों को भी आदेश प्रदान किये गये हैं। लेकिन मैं यह विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि कृषि की पैदावार बढ़ाने पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस पर्पज पर करोड़ों और लाखों रुपयों की रकम बरबाद हो रही है।

इसके क्या कारण हो सकते हैं, यह आपके सोचने की बात है। मैं अपने क्षेत्र के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। इस समय सुखाड़ियाजी भी उपस्थित होते तो ज्यादा अच्छा होता।

निवेदन यह है कि मेरा क्षेत्र राजस्थान की राजनीति का सेन्टर रहा है। वहां सन् १९५२ से ही राजनैतिक संघर्ष रहा है और इसी कारण से नदियों के समूह वाले इस हिस्से में बनने वाला भीमसागर बांध तीस साल से विचाराधीन पड़ा है। पूर्व में परवन नदी, पश्चिम में काली सिन्ध नदी, और काली सिन्ध की मर्जर करने वाली पश्चिम में चम्बल नदी, पार्वती नदी पूर्व में जिस पर आपका भीमसागर बांध बनना है जो तीस साल से अभी तक विचाराधीन ही है।

इसके अलावा खाद्य विभाग की अकर्मण्यता का भी एक नमूना मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं। इन नदियों के जलाशयों

(श्री प्रभुलाल 'सेन्टर')

के लिए बार-बार निवेदन करने के बाद भी पम्पिंग सेट्स नहीं लगाये गये। यदि पम्पिंग सेट्स लग गये होते तो १५ हजार एकड़ की सिंचाई हो जाती। इस तरह पूरा-पूरा ध्यान कोटा डिवीजन की तरफ दिया जावे तो पूरे राजस्थान में अकाल पड़ जाने पर भी सारे राजस्थान का पेट कोटा डिवीजन अकेला भर सकता है। आपको अमेरिका से भी भीख मांगकर गेहूं लेने की जरूरत नहीं रहेगी, कम से कम राजस्थान को।

इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा हमारे सम्माननीय कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपके विभाग से जितने भी प्रेक्टिकल सर्वे, अंग्रेजी में जिसे आप कहते है, कोटा डिवीजन में करवाया जावे और उन सब नदियों के पानी का पूरा-पूरा उपयोग सिंचाई और बिजली के लिये किया जावे, इससे सारा राजस्थान खुशहाल हो सकेगा।

मेरी यह समझ में नहीं आता कि इतने अपार साधनों के होते हुए आप कोटा डिवीजन में पैदावार बढ़ाने की ओर ध्यान क्यों नहीं देते और अमेरिका के ऋण से, उसके दान से, और उनकी पॉलिसी से क्यों नहीं मुक्त होते ?

साथ ही एक-दो छोटी-मोटी समस्याएं और भी हैं। १५ साल से भीमसागर पर जो कुछ थोड़ी बहुत नहरें आपने खोदी है उनमें जिनके खेत आये वे (कृषक) आज एक तरफ तो अपनी पैदावार से महरूम हैं, पांच छः साल तक तो लगान भी आप उनसे लेते रहे, पर नहर में आई भूमि का मुआवजा उनको अभी तक नहीं मिल पा रहा है, साथ ही यह भी तय नहीं हो रहा है कि भीमसागर का होगा क्या ? तो एक तो यह मुआवजा कब तक आप दे देंगे इस बारे में आश्वासन देने की कृषि मन्त्रीजी कृपा करें।

असनावर के भविष्य का जहां तक सवाल है सारी परिस्थितियां आपको धीरे धीरे मालूम होती जा रही है। तो आप इस पर भी ध्यान देने की कृपा करें।

एक जगह आप १५) रु० बीघा का मुआवजा दे रहे हैं और दूसरी जगह १००) रु० बीघा का। १५) रु० जिसको आप दिला रहे थे उसने नहीं लिया, वह कोर्ट में गया और वहां से ७५) और ८०) रु० बीघा का मुआवजा मिला है। तो यह भेद-भाव क्यों बरता गया ? इसे मिटावेंगे या नहीं, इस पर आश्वासन दिलाने की कृपा करें।

साथ ही निवेदन कर दूं कि सेविंग सर्टीफिकेट जब चले थे तो लोगों ने समझा कि चम्बल डेम के टिकट हैं। लोगों ने इस उत्साह में इनको लिया भी था। लोगों के दिमाग में है कि आप इस एरिया को काफी डेवलप करेंगे और अन्न उत्पादन में यहां काफी प्रगति करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आज से २५ वर्ष पहले की बात है। मैं ऐसे गांव आलोदा में पैदा हुआ हूं जहां २५ आदिवासियों के घर उस समय थे। उस समय जैसी झोंपड़ी में मैं गुजारा करता था उससे आज भंगी—हरिजन के पास भी अच्छी है। इसमें शक नहीं कि इस माने में प्रगति हुई है। बरसात में हम उन दिनों एक आना भर ज्वार में

(श्री प्रभुलाल 'सैन्टर')
पुबाड़िया डालकर पेट भरते थे। इतना भर मिल जाता था तो ग्वाला नाच नाच कर काम करता था। आज उस गांव में हमारे लोग टैरीलीन भी पहनते हैं। इस अर्थ में विकास हुआ है। हम काफी आगे बढ़े हैं। पर हमें तेजी से आगे बढ़ना है। इन्दिराजी और कामराजजी जैसे बुद्धिमान लोगों को हमने सरकार एवं संगठन में रखा है, तो हमें सारे बजट का अवलोकन करना है और जनता के जीवन को और ऊपर उठाना है।

आज विरोधी पक्ष के लोग इस प्रगति को भुलाकर कई तरह की भावना गांवों के लोगों में भर देते हैं, इससे गांवों के लोगों का भविष्य अन्धकारमय है। वे नहीं समझते कि हमारे पर टैक्स क्यों लगते हैं, इसलिए वे उनकी बातें बहुत पसन्द करते हैं क्योंकि हमारा कृषि और आर्थिक क्षेत्र में विकास कम हुआ है।

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : वे जानते हैं कि असली शुद्ध घी में और वेजिटेबल में कितना अन्तर है।

श्री प्रभुलाल 'सेन्टर' : हमें हमारी इन नहरों से कितना फायदा कब तक मिलेगा, यह भी आप बताने की कृपा करें। हमारे व्यक्ति अनुशासनबद्ध हैं। हमने विरोधी पक्ष के लोगों को कुछ करने नहीं दिया है, किसी को पांव नहीं रखने दिया है और अगर जन संघ की छाया पड़ी भी है तो इसका क्या कहा जावे? यह तो कोटा के जागीरदारों का और राजाओं का और कार्यकर्ताओं की पॉलिसी की टक्कर है। राजा साहब झालावाड़ और महाराज कुमार साहब हमारे साथ हैं, जागीरदारों की पॉलिसी है वह इनके व कांग्रेस के विरुद्ध है। इस कारण जन संघ पैदा हुआ है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कोटा रियासत के समय के ९० प्रतिशत जागीरदार मेरे इलाके में रहते हैं। इसके बाद भी कांग्रेस में झालावाड़ राजा और महाराज कुमार कोटा हैं, तो हर तरह से उनका सहयोग कांग्रेस को मिल रहा है।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : उधर जाने के बाद भी महसूस करते हो क्या?

श्री प्रभुलाल 'सेन्टर' : इसलिए आप इस डिवीजन में कृषि पैदावार के लिए प्रयत्न करिये ताकि हमारा डिवीजन सही माने में राजस्थान की सेवा करने लायक हो सके, अन्न के क्षेत्र में पूरे राजस्थान को आत्म निर्भर बना सके, अन्नदाता कहलाने लायक हो सके।

शीघ्र सिंचाई की दृष्टि से पम्पिंग सैट्स दीजिये। बिजली और अच्छा बीज आप मुहैया करिये। आज कामराजजी जैसे नेता विश्व में कम होंगे। उनके तत्वावधान में आज कांग्रेस को आगे बढ़ना चाहिये, इन्दिराजी के तत्वावधान में महिला जगत को ज्यादा से ज्यादा बलवान बनाएं। अनुशासन में अधिक विश्वास पैदा हो और कृषि पैदावार को बढ़ाने का प्रयत्न करें।

फिर जैसा मैंने कहा गांवों में जो कर लगाये हैं, विरोधी पक्ष के लोगों के कहने से कतिपय गांवों में अविश्वास की भावना है कि सरकार उन पर कोई नाजायज बोझ लाद रही है इसलिए आप इस तरह के करों में

(श्री प्रभुलाल 'सेन्टर')

संशोधन करके अन्य अप्रत्यक्ष कर ज्यादा लगा दीजिये, पर इन करों में संशोधन करिये। यही मुझे कृषि मन्त्रीजी और वित्त मन्त्रीजी से निवेदन करना है।

श्री बीसरसिंह बाबेल (बेंगू) : अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट है मैं तो इसे दिवालिया बजट ही कहूंगा। सरकार ने जो फीगर्स इसमें बताये हैं उनमें बहुत बड़ा अन्तर है। ६३ में ८१ करोड़ ३७ लाख का अन्दाज लगाया था और आगे आकर संशोधित बजट में उसे ९७ करोड़ ८४ लाख कर दिया; १६ करोड़ ४७ लाख का फर्क निकाल दिया। तो इस तरह के बजट को कैसे अच्छा बजट माना जावे, अच्छे अनुमान माने जावें। थोड़ा बहुत अन्तर तो स्वाभाविक हो सकता है। अब जो बजट ९६ करोड़ ५६ लाख का है इसमें उनको कोई कर लगाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये थी, क्योंकि यह पिछले साल से कम का बजट है। पर खर्चा बढ़ाकर उसको मीट आउट करने के लिये बुरी तरह से अत्याचार करके कर लगाना चाहते हैं। सरकार की आमदनी बहुत बढ़ी है, अगर सरकार अपना खर्चा बढ़ाने के बजाय थोड़ा घटा देती और नहीं भी घटाती तो भी काफी बचत होती। पर खर्चा अनाप-शनाप बढ़ा दिया है और फिर कहती है कि हमारा बजट घाटे का है।

अध्यक्ष महोदय, इसमें जो १॥ करोड़ रुपया अकाल सहायता के लिए बताया गया है वह कहां खर्च किया गया? किन गरीबों की किस तरह से सहायता की गई, इसका एक नमूना मैं सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में भी दो पंचायतों में अकाल सहायता के रूप में ५० हजार रुपया सड़क बनाने के लिए मन्जूर किया गया। वहां मजदूरों को, आदमी को १.१२ पैसा रोज, औरतों को ०.८७ पैसा और बच्चों को इससे भी कम दिया गया। जब तक मजदूरी नहीं बांटी तब तक तो काम किया, पर जब इतना कम पैसा उनको दिया गया तो सब लोग भाग गये। क्या इतनी कम मजदूरी में किसी का अच्छी तरह पेट भर सकता है? जबकि उसके पास ही राणा प्रताप सागर डेम पर २॥), २।) और २) रु० रोज की रेट थी। क्या यही अकाल सहायता आप दे रहे हैं, क्या अकाल की सहायता की आड़ में इन गरीब लोगों का आप शोषण करना चाहते हैं?

क्या आप उनके साथ यह रियायत कर रहे हैं? तो आप बताने की कृपा करें कि आपकी रेट्स क्या हैं, ताकि मुझे भी तसल्ली हो, और वे घर पर बैठे हैं और आपकी सड़कों का काम बन्द है। मेरा कहना यह है कि ५६ लाख रुपये का प्रावधान सशस्त्र सेना के लिए रखा जायगा। उसके लिए भारत सरकार से पैसा मिलेगा और इसमें फिर इस रकम का इन्दराज किया गया तो क्या हमारी सरकार को भारत सरकार ने यह रकम देने से इन्कार कर दिया जिसकी वजह से इसमें यह इन्दराज हुई? या आपने मांग नहीं की या उन्होंने दी नहीं? इसके बारे में भी आप स्पष्टीकरण करें।

आप १३ करोड़ रुपया बैंक से ले चुके हैं और ४ करोड़ १० लाख रुपया आपको इसी साल चुकाना है। यही नहीं, भारत सरकार का कुल कर्जा आपके ऊपर ३१३ करोड़ रुपये

(श्री बीसरसिंह बावेल)

का है उसमें १७ करोड़ आपको इसी साल चुकाना है, वह कहां से आप चुकायेंगे ? क्या इसके लिए आप फिर से कर्जा लेंगे, यह भी आप बतायें । आप बताने की कृपा करें कि आपका सही तरीका क्या है; आप वसूली करते नहीं हैं, आप घोटाले का रुपया वसूल नहीं करते । जैसा कि कल एक माननीय सदस्य ने बताया था, जो माननीय सदस्य दूर से आते हैं उन्होंने कहा था, कि यदि आप वसूली करें तो आपका काम चल सकता है । लेकिन आप उस पर विचार नहीं करते हैं । आपने जब ६४ का चुनाव था तो अकाल की हालत में कितना रुपया खर्च किया और आज भी माननीय सदस्य यहां नहीं हैं, आप बतायेंगे कि उनके यहां कितना रुपया खर्च हुआ है । आप अपने मकसद को पूरा करने के लिए इस तरह के काम करते हैं, आप इस पर विचार करें और आप जब बजट बनाते हैं, उसके अन्दर एस्टीमेट्स ठीक से नहीं बनाते हैं । १५-१६ करोड़ का संशोधन में फर्क है तो यह क्यों होता है, इसको भी समझाने की कृपा करें । ६७ करोड़ का बजट होता है और वैसे आता है ८१ करोड़ यह क्या है ? यह हम समझना चाहते हैं ।

मेरे क्षेत्र में बिजली के लिए २ लाख ६० हजार रुपया बेंगू को देने के लिए था और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बजट के बावजूद भी तृतीय पंचवर्षीय योजना में, साठ हजार की आबादी होते हुए भी वहां बिजली नहीं दी गई और वह रुपया दूसरी जगह खर्च कर दिया गया । इसी तरह से आपने १५ लाख टन अधिक अन्न उत्पादन करने का लक्ष्य बनाया था, लेकिन उसके बावजूद ११ लाख ३४ हजार टन ही रह गया । आपने वर्षा के लिए कहा, मैं मानता हूं कि वर्षा नहीं हुई, लेकिन आपने बताया कि किटाणुनाशक दवाई नहीं मिली । तो आप उसको उपलब्ध नहीं करा सके । आप गरीबों को जमीन नहीं देते । आप ऐसे लोगों को जमीन अलॉट करते हैं जिनके पास पहले से जमीनें मौजूद हैं या फिर आप ऐसे लोगों को जमीन अलॉट करते है जिनके पास खेती करने के साधन नहीं हैं और न वे खेती कर सकते हैं । हमारे यहां एक विकास अधिकारी श्री पुरुषोत्तमलालजी हैं, उन्होंने अपने बाप के नाम जमीन ले ली, वहां के प्रधान मुन्नलालजी है उन्होंने अपने नाम से ले ली, इसी तरह से एक वकील श्री रामधन है उन्होंने अपने लड़के के नाम से जमीन ले ली, एक देवकरणजी वैद्य हैं उनको आपने जमीन दे दी । अगर आप ऐसा नहीं करें तो दुष्काल नहीं पड़े और वास्तव में जिनको जमीन दी जानी चाहिए उन्हीं को दें तो आपकी यह सारी अन्न की समस्या हल हो जाये । तो आपसे प्रार्थना है कि आप इस पर विचार करें ।

आपकी पुलिस का इन्तजाम अच्छा नहीं है । आप लाखों रुपया इस बजट में पुलिस विभाग के लिए रखते हैं । आज कत्ल हो रहे हैं, दिन-दहाड़े डकैतियां हो रही हैं, १॥ लाख की नकबजनी हुई है करेला की, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हुआ । आप इस बारे में विचार करें । आपका वन विभाग है जिसके आगे हजारों आदमी उसके दफ्तर के सामने खड़े रहते हैं । आप पंचायती राज वहां देखें कि किसान कहां खड़ा है, गरीबों की क्या हालत हो रही है ? न्याय इतना मंहगा हो गया है कि जिसकी हद नहीं । बेंगू का एरिया १०२ मील का है और वहां पर ४ हजार के करीब मुकदमें होते थे । तो बजाय बेंगू में तहसील

(श्री चौसरसिंह बावेल)

रखने के आपने चित्तौड़गढ़ में रखी है। तो यह क्या न्याय है कि तीन-तीन दिन पेशियों के लिए आना पड़ता है और इस पर आप विचार करें। यह ६० हजार की आबादी का कस्बा है। आपने अस्पताल चित्तौड़गढ़ में बनाया। राज्यपाल महोदय ने उसका उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि यहां कई बड़े बड़े एक्सपर्ट रहेंगे, लेकिन वहां कोई नहीं रहता। आपने प्रतापगढ़ हैडक्वार्टर रखा और अस्पताल बना दिया चित्तौड़गढ़ में। आपकी नीति साफ होनी चाहिए जिससे जनता की भलाई हो। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं और अभी एक माननीय सदस्य ने कहा, कि यह दिवालिया बजट नहीं है लेकिन आप देखते हैं कि कितने गड़-बड़ घोटाले है। आप सामान खरीदते हैं; आपने ३५५ करोड़ की सम्पत्ति बताई है, लेकिन कर्जा भी तो ३३३ करोड़ का है। आप उस सम्पत्ति को बेचने जाओ तो लेने वाला कोई नहीं है। अब मैं लम्बी चौड़ी बात अर्ज नहीं करना चाहता हूं। कृपया आप तो इस बजट को एक पोथा ही समझें। जो टैक्स आप लगा रहे हैं उन्हें आप वापिस लें। यह बड़ा अन्याय है। आप घी पर टैक्स लगा रहे हैं, हर काश्तकार के ऊपर उसका हमला हो रहा है। आपने जनता से यह वादा किया था कि भूमि पर राज प्रजा का होगा और जंगलात पर किसान का होगा, सस्ता अनाज होगा, न्याय सस्ता मिलेगा, आपकी वे सब बातें कहां गई? आप कुर्सी पर बैठने के बाद जनता को भूल गए। मैं एक मिनट के लिए एक कहानी कह देता हूं गाने के रूप में:

'जंगलात की सीमा में·········'

(अध्यक्ष)

श्री अध्यक्ष : यह चुनाव के गीत अभी तैयार कर लिए क्या ?

श्री चौसरसिंह बावेल : तो मैंने तो आपसे कहा, यह सही बात है। अध्यक्ष महोदय, सन् २२ में एक आंदोलन हुआ बेंगू में। वहां किसानों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया और उस आन्दोलन में सरकार का मुकाबला करके दो आदमी, रूपाजी और कृपाजी, मारे गए। महात्मा गांधी ने भी कहा कि बेंगू के किसानों को क्या समझाऊं। आज वे किसान मारे-मारे फिरते हैं, न जंगल के मिनिस्टर सुनते हैं और न कोई और सुनते हैं। बार बार आने की चिट्ठियों के लिए दो-दो दिन तक मारे मारे फिरते हैं जबकि इतने फोरेस्टर्स हैं; इतना अमला है तो वह घर पर क्यों नहीं देते हैं? यही अर्ज करना चाहता हूं कि आप इस बजट को देखें। ठेकेदारों के लिए तो काफी लकड़ी है, लेकिन उन गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। राणाप्रताप सागर के डूब में जितने भी लोग हैं उनकी जो जमीन ली गई उनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। वे सब लोग मारे मारे फिर रहे हैं, कई लोग हाई कोर्ट में गए हैं और वहां पर भी बहुत सारी बातें हुई हैं। चुनाव में इतनी गड़बड़ियां होती हैं, अध्यक्ष महोदय, कि सिविल जजों से फैसला हुआ, वहां से चुनाव रद्द होने के बाद भी चुनाव नहीं हुआ और जिन अफसरों ने गड़बड़ियां कीं, जिनके बारे में कोर्ट ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने बेईमानी की है, रिटर्निंग ऑफिसर ने गलती की है, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया।

(श्री चौसरसिंह बावेल)

यह बात मैंने प्रधान मंत्रीजी से भी, जब मैं एक डेपूटेशन में गया था १२ फरवरी को, तब कही थी। वे कोई कार्यवाही करें या न करें, लेकिन आपको तो इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वे इसमें विचार करें और चुनाव की जो पद्धति है उसको बिल्कुल शुद्ध करें। कांग्रेस पार्टी द्वारा इस प्रकार की चुनाव की व्यवस्था होनी चाहिए कि उनमें इस तरह की गड़बड़ियां न हों। आप न्याय प्रिय हैं। देश ने जिस भावना से आपको देश की बागडोर सम्भला रखी है आपको उसी भावना से काम करना चाहिए। इसमें आपका नाम होगा और जो कुछ भी अन्याय आपने किए हैं उनको भी जनता माफ कर देगी। अब तो चुनाव आ रहे हैं, आप इन पर कृपा कीजिए।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री जीवराजसिंह।

श्री जीवराजसिंह (गुढा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वक्त देशमें दो ही चीजों की आवश्यकता है। एक तो डिफेंस की और दूसरी अनाज की। अनाज के मामले में और डिफेंस के मामले में दोनों में ही झुंझुनूं जिला वैसे ही आगे है। लेकिन वहां पर सिंचाई के साधनों की कमी है जिसकी ओर मैं सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सिंचाई के मामले में हमारे जिले के बारे में मैंने पहले भी सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया था और सवाल भी पूछा था और मैंने अपनी स्पीच में भी, दो साल पहले, अर्ज किया था कि वहां पर जयपुर स्टेट के टाइम में भी कांकड़ा बांध की योजना थी वह योजना पहले भी पूरी नहीं हो सकी और इस सरकार में भी पूरी नहीं हो सकी है। इसके बाद शेखावाटी के इलाके हैं, उदयपुरवाटी और खेतड़ी के इलाके हैं, जहां दो-फसली एरिया है वहां पर छोटे छोटे बांधों के लिए सर्वे हुई थी, लेकिन उस सर्वे के होने के बाद वहां पर कोई काम नहीं हुआ। और जैसे उदयपुर, टोंक, मंडावा, कोटड़ी, सीकर और झुंझुनूं जिलों में भी बांधों के लिए सर्वे हुए थे और इसके अलावा गुढ़ा और कोटड़ी का सर्वे भी हुआ था, लेकिन वहां कार्य अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। इसलिए मैं कृषि मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जो सिंचाई के साधन हैं उनको वे उस एरिया में प्राथमिकता दें और अगर वहां के काश्तकारों को आप सिंचाई के साधन दें तो आज देश की जो अनाज की समस्या है वह ज्यादा से ज्यादा हल हो सकती है। इसी तरह से वहां पर जो बिजली का साधन है वह भी अभी दो साल से ही है। वहां पर कुए भी बहुत ज्यादा हैं और छोटे छोटे बांध बना दिए जावें तो कुओं का लेवल भी ऊंचा हो सकता है। बिजली तो गांवों में पहुंच गई है, लेकिन उसके लिए तकावी बहुत कम मिलती है, पंचायत समितियों से जो तकावी मिलती है वह तो नाम मात्र को ही होती है। इसलिए मैं सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान भी इस ओर दिलाता हूं कि बिजली के लिए भी कुछ फण्ड अलॉट किए जायं कि जिससे वहां पर सिंचाई के साधन बढ़ सकें; इससे ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ सकेगी।

दूसरा ध्यान मैं आपका इस ओर दिलाता हूं कि आप लोग जो एरियाज में दौरों पर जाते हैं और बड़े बड़े भाषण देते हैं। आप लोगों आपकी बातों में आ जाते हैं और भावुकता में

(श्री जीवराजसिंह)

आकर आप जो कुछ कहते हैं कर देते हैं। भावुकता में आकर उन्होंने स्कूलें बना दीं, औषधालय की बिल्डिंग बना दी, अस्पताल की बिल्डिंग बना दी; लेकिन उनकी ओर आपका ध्यान नहीं जाता है। आपको रिक्वेस्ट की जाती है तो भी आप ध्यान नहीं देते हैं। जैसा कि चिराणा में हाई स्कूल की बिल्डिंग बना दी, बड़गांव में लड़कियों की स्कूल की बिल्डिंग बना दी, उदयपुर में लड़कियों की स्कूल के लिए बिल्डिंग बना दी। स्पीकर साहब भी जब वहां पर दौरे पर आये थे तब उनसे भी निवेदन किया था। पचरंगी का मकान पड़ा है, बागोली में औषधालय भवन बना लिया है, इन्दुपुरा में औषधालय बना दिया है, लेकिन उस ओर आप कोई ध्यान नहीं देते हैं। लोगों ने आपकी बातों में आकर हजारों रुपये खर्च कर दिए लेकिन अब लोगों में निराशा की भावना फैल रही है। सरकार हमारे साथ न्याय नहीं करती है।

इसके साथ साथ वहां की जनता पर आपने जो टैक्स लगाये हैं तो इसके अलावा हमारे एरिया के अन्दर क्लोराइड की खानें हैं, चूने के पत्थर की खानें हैं जिससे सीमेण्ट की फैक्ट्री चल सकती है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो क्लोराइड का पत्थर है, चूने का पत्थर है और भी दूसरी तरह के खनिज है, अगर सरकार उनके कारखाने वहां लगाये तो लोगों को काफी काम मिलेगा और उससे आपको भी पैसा मिलेगा।

इसके अलावा मैं आपका ध्यान खुदकाश्त के बारे में दिलाना चाहता हूं। खुदकाश्त की भूमि बहुत से छोटे छोटे जागीरदारों को नहीं मिली है जिनके बारे में बहुत कुछ लिखा-पढ़ी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। दस-दस साल हो गए हैं जागीर रिज़म्प्शन हुए लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आप इस ओर ध्यान दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों को जमीनें मिल सकें और जो लोग रह गए हैं, जिनकी मियाद निकल गई हैं उनकी मियाद भी आपको बढ़ानी चाहिए, उनकी मियाद बढ़ाने की आप कृपा करें ताकि उन लोगों को भी जमीनें मिल सकें।

इसके साथ साथ मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जो आपने टैक्स लगाये हैं उन टैक्सों की एवज में जिन लोगों में टैक्स की रकम बकाया है अगर आप वह वसूल करेंगे तो आपको टैक्स नहीं लगाने पड़ेंगे। घी, तेल पर और मवेशियों पर जो आपने टैक्स लगाया है वह अगर नहीं लगायेंगे तो आपकी कृपा होगी और साथ साथ जो छोटे कर्मचारी हैं आप उनकी तनख्वाहें बढ़ायेंगे तो वे आपको आशीर्वाद देंगे। इसलिए मेरा तो यही निवेदन है कि या तो आप टैक्स लगायें ही नहीं और टैक्स लगाते हैं तो जो हमारी प्रोब्लम्स हैं, कृषि की प्रोब्लम्स हैं, सिंचाई की दिक्कतें हैं, उनको आप पूरा करें। बस इतना ही कह कर मैं अपना स्थान लेता हूं।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : अध्यक्ष महोदय, मैं तीन दिन से खड़ा हो रहा हूं, लेकिन मुझे मौका ही नहीं दिया जा रहा है........

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

Page No. 65

श्री मुक्तिलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं तीन दिन से खड़ा हो रहा हूं लेकिन एक बार भी टाइम नहीं दिया गया है। और लोग तीन-तीन बार बोल चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य पहले भी बोल चुके हैं। सदस्य अभी तक एक बार भी नहीं बोले हैं मैं उनको प्राथमिकता दे रहा हूं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं कहां बोला हूं ?

श्री अध्यक्ष : इस तरह की बहस न करें। जब आपका टाइम आएगा आपको कह दिया जाएगा।

श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा) : माननीय अध्यक्ष, हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट को यहां पर पेश किया है और उस बजट को हमने देखा है। इस बजट को देखने से मालूम हुआ कि तेरह करोड़ रुपयों का घाटा वित्त मंत्रीजी ने बताया है। हमारे वित्त मंत्रीजी बजट पेश करते हैं, सन् ६२ से बजट पेश करते आ रहे हैं और जब भी बजट पेश करते हैं तो बजट को घाटे का बजट रखते हैं। आज इस बजट को देखने से यह मालूम पड़ता है कि अगर इस बजट को घाटे में न लाकर सही तौर से इस बजट को पेश किया जाय और जो हमारे हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में जो बकाया, वसूलियां हैं, जो बकाया है, जो इसमें लेनी हैं, उसको सही तौर से वसूल किया जाय तो हमारा बजट कभी घाटे में नहीं जा सकता। हमारे वित्त मंत्री महोदय इस बजट को इस रूप में लाकर यह बताना चाहते हैं कि हमारे यहां अकाल पड़ा है और हमारी सीमा पर पाकिस्तान का आक्रमण हुआ है जिसकी वजह से बजट घाटे में चला गया है लेकिन यह बिल्कुल असत्य है।

अध्यक्ष महोदय, आज वित्त मंत्री महोदय, यह बात बताते हैं और उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा है राजस्थान की अर्थव्यवस्था बुनियादी तौर पर खेती पर निर्भर है। राजस्थान के गांव इसकी रीढ़ हैं और जैसा कि गांधीजी ने कहा था, अगर गांव मरता है तो देश मरता है। अध्यक्ष महोदय, आज किसानों की हिमायती सरकार किसानों के लिए इस तरह की बातें कहें और यह कहें कि हम उनको राहत दे रहे हैं, हम देश में समाजवाद ला रहे हैं, इस तरह की बातें करते हैं; लेकिन यहां काश्तकारों पर टैक्स लगाते हैं। जब चुनाव आते हैं तो यह कांग्रेस बैलों के नाम पर किसानों पर वोट लेकर जीत कर आ जाती है.........

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : चुनाव तो फिर आने वाले हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : जब चुनाव आते हैं तो कहते हैं कि हम आपके यहां सिंचाई के साधनों में वृद्धि करेंगे और आपको लगान में छूट देंगे, इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन आज अध्यक्ष महोदय, इन्होंने क्या किया है कि किसानों पर ही टैक्स लगाया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज देश में अनाज की समस्या है, लोगों को खाद्य नहीं मिल रहा है। मैं आपसे कहता हूं कि आप किसानों को सहूलियतें दीजिए, उनको सिंचाई के साधन दीजिए, लगान में छूट दीजिए और आप देखेंगे कि किसान अपने आप खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा देगा। आज किसानों के

(श्री लक्ष्मीचन्द)

सामने पानी पीने की समस्या है, किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर जब श्री दौलतरामजी सारण उप मंत्री आए थे तो उन्होंने कहा कि तुम चना बोओ, गेहूं बोओ, तुम्हारे लिए पानी की व्यवस्था करेंगे। आज वहां पर हजारों बीघा खेत में चना पड़ा है, बीज खत्म हो रहा है लेकिन खेतों में पानी नहीं मिल रहा हैं।

(२. म. प.)

अगर वे यह नहीं फर्माते कि पानी आपको नहीं मिलेगा तो काश्तकार चना नहीं बोते। आज यह समस्या है, अध्यक्ष महोदय, कि जब उन्होंने चना बो दिया तो उनसे कहा जाता है कि पानी नहीं मिलेगा। पंचायत समिति ने उनको बीज दिया है, उसका भी कर्जा उनके ऊपर हो गया है और वह चना वैसे ही सूख रहा हैं। अध्यक्ष महोदय, वह बीज बेकार गया हैं और उलटे उन पर पंचायत समिति का बीज का कर्जा हो गया है।

आज कृषि मंत्रीजी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कि आप कहते हैं, कि फर्टीलाइज़र काफी तादाद में किसानों को दिया गया है, लेकिन मैं अर्ज करूं कि हमारे वहां ६५ की मई और जून में लाखों बोरी खाद आया, लेकिन उस खाद को समय पर किसानों में नहीं बांटा और आज भी वस वहां पर पड़ा हुआ है। वह खाद बरसात में भी वहीं पड़ा रहा और उस खाद को अब काश्तकारों में बांटना चाहते है तो आप बताइये कि उपज कैसे बढ़ सकती है? उसके लिए वहां के सरपंच ने और जनता ने शिकायत की है, लेकिन आज तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैंने बी० डी० ओ० साहब से कहा था कि यह खाद बरसात में भीग रही है, यहीं पड़ी हुई है, लेकिन उन्होने उसकी परवाह नहीं की। आज भी वह खाद वहां पर पड़ी हुई है और उसकी एन्क्वायरी नहीं हुई।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : कौन सी पंचायत समिति?

श्री लक्ष्मीचन्द : पंचायत समिति इटावा।

१०० बोरियां वहां पड़ी हुई हैं। जब कलेक्टर साहब अक्टूबर में गये थे तो उन्होंने कहा था कि मैं एन्क्वायरी कराऊंगा, लेकिन आज तक उसकी एन्क्वायरी नहीं हुई। उस ऑफिसर से, जिसकी गलती है, पांच हजार रुपये वसूल होने चाहिए। उन्होंने उन बोरियों को वहां खुले में रखवा दिया। न कोई गोदाम है। इससे काश्तकारों को फायदा नहीं मिल सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे गांव की एक समस्या मैं अर्ज करना चाहता हूं। वहां पर एक तालाब है आयना का। उस तालाब के ऊपर से नहर निकाली गई है, तो जो नाला उसमें पड़ता था वह बन्द हो गया, तो ३-४ साल से उस तालाब में पानी आना बन्द हो गया और वहां के लोगों को पीने का पानी व मवेशियों के लिए पानी नहीं मिल रहा है। नहर से पानी ले लेते थे, लेकिन इस साल तो उन्होंने कहा कि पानी नहीं। लाखों टन पानी बेकार गया। दो बार नहर टूट गई, लेकिन तालाब में पानी नहीं दे रहे हैं। उस तालाब में कमल होते हैं, सिंघाड़े होते हैं। वहां की दो हजार की जनता पूरे तौर से उस तालाब पर निर्भर करती है। पानी पीते हैं, और सारी

(श्री लक्ष्मीचन्द)

बातें उस तालाब पर निर्भर हैं, लेकिन आज उसमें पानी नहीं है और कीड़े उसमें बुलबुला रहे है। वहां की ग्राम पंचायत के लोग विकास अधिकारी और एस० ई० एन० से मिले, लेकिन आज वहां की जनता को पीने का पानी भी मुहय्या नहीं हो रहा है।

मैं यह कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि उसकी वजह क्या है ? वहां पर जो ओवरसियर हैं वे लोगों को तंग करते हैं। उनकी शिकायत मैंने भी दो दफा यहां पुट अप कर दी है, लेकिन वह प्रश्न नहीं आया है अभी। वह ओवरसियर ४-५ साल से वहां रह रहा है और अपनी मनमानी कर रहा है। किसी से क्या लेता है, किसी से पैसा खाता है और भ्रष्टाचार करता है। उसकी शिकायत काफी कर दी, लेकिन उसका ट्रान्सफर नहीं हो रहा है। हम एक्स० ई० एन० से मिले और अधिकारियों से मिले लेकिन कोई परवाह नहीं करता। उसने वहां पर मवेशी पाल रखे हैं, वे किसानों की फसलों को नुकसान करते हैं। ऐसा वहां पर अफसर है, वह भाग लेता है पार्टी पॉलिटिक्स में। उसको ४-५ साल वहां पर हो गये हैं लेकिन उसका ट्रान्सफर नहीं हो रहा है, उसकी शिकायत हो गई है तो भी।

वहां के काश्तकारों को तो पानी नहीं मिलता है लेकिन ओवरसियर ने २० बीघा सरकारी जमीन पर चने बो रखे हैं उनको पानी मिल जाता है। वह उस जमीन का हासिल भी नहीं देता है। उसकी एन्क्वायरी की जाये। वहां के सरपंच साहब ने कहा था, रेवेन्यू के पटवारी और सिंचाई के पटवारी को, कि इनकी फसल लिखी जाये, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। उसकी एन्क्वायरी की जाये और उनसे लगान वसूल किया जाय और उस ओवरसियर को सस्पेण्ड किया जाये जिसने कि सरकारी जमीन २० बीघा पर चने बो रखे हैं।

इसी तरह से गन्ने का मामला है, अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो सरकार चाहती है, कि काश्तकार गन्ना खूब पैदा करें। काश्तकारों ने बड़ी इच्छा के साथ गन्ना बोया। उन्होंने सरकार से बीज लिया, पंचायत समिति से बीज लिया, लेकिन गन्ने को पानी नहीं मिला और वह सूख गया। उसका गड़बड़ घोटाला हो गया। गन्ने के लिए बी० डी० ओ० ने खाद देने की परवाह नहीं की। उसकी सबसिडी ३४ हजार बनती है, वह सब हजम कर गया। उसकी आज तक एन्क्वायरी नहीं हुई। उसके लिए एक जांच कमेटी भी बिठाई गई और जांच कमेटी ने कहा कि रिपोर्ट दे दी, लेकिन वह नहीं दी, तो जांच किस पर करें। उसका ट्रान्सफर पहले शाहबाद पंचायत समिति में कर दिया गया था लेकिन उसकी एन्क्वायरी को दबाने के लिए फिर वहां पर उसी बी० डी० ओ० को लगा दिया गया, पंचायत समिति इटावा में। जो सदस्य बने हैं, एन्क्वायरी करने वाले, उन्होंने कहा कि लिस्ट दी जाये कि किस पर एन्क्वायरी करें, लेकिन वहां से सरपंच उसकी वजह से दब गये और ८ दिन में ही मीटिंग करके रिपोर्ट दे दी गई कि कोई गलती नहीं है, एन्क्वायरी कर ली गई। मैं पूछना चाहता हूं, कृषि मंत्रीजी, कि आप उस बी० डी० ओ० का ट्रान्सफर करें और उसकी एन्क्वायरी पूरी करायें, जिसमें कि ३४ हजार का गबन है। यह कहां का न्याय है। आज आप कहते हैं कि

(श्री लक्ष्मीचन्द)

काश्तकारों की तरक्की करेंगे। इसीलिए तो, अध्यक्ष महोदय, आज खाद्य की कमी है।

काश्तकारों पर आपने टैक्स पर टैक्स लगा दिये। आज उन पर से टैक्स क्यों नहीं हटाते हो ? लाखों रुपया काश्तकार पहले ही आपको दे रहा है। उस पर पहले से ही बहुत लगान है। आपने फिर घी पर टैक्स लगा दिया, तेल पर टैक्स लगा दिया। ये चीजें काश्तकारों के काम में आने वाली हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा, सड़कों के सम्बन्ध में। आज सरकार इस तरह का ढिंढोरा पिटाती है, कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं और शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स को सहूलियतें देना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इलाके की बात कहता हूं कि वहां पर १५ मील का एक टुकड़ा है वह स्टेट के जमाने से बचा है। आज १८ साल से वह वैसा ही पड़ा हुआ है। वहां पर एक एक फुट चूना हो जाता है और काश्तकारों को परेशानी हो जाती है। उसकी मन्जूरी हुए तीन साल हो गये लेकिन उसका प्रारम्भ नहीं हो रहा है। वहां पर रोड नहीं बन रही है। यह कहां का न्याय है ?

अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने यह भी जिक्र किया है कि हम पाकिस्तान से युद्ध में से गुजरे हैं और इस तरह की हमारी गति हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री लालबहादुरजी शास्त्री ने "जय जवान जय किसान" का नारा लगाया था। बात बिल्कुल सत्य है। आज के युग में दोनों की बड़ी आवश्यकता है। हमारे जवानों ने जिस साहस के साथ, जिस बहादुरी के साथ में पाकिस्तान का मुकाबला किया। पाकिस्तान को हताश किया, हम उन जवानों की यादगार को कभी नहीं भूल सकते। जिन्होंने अपने देश के खातिर अपने परिवार को छोड़ कर, जिस साहस के साथ, अपने प्राणों की परवाह नहीं करके, पाकिस्तान के साथ लड़कर विजय पाई आज हमारी सरकार, जिन जवानों की मौत हुई है उनके लिये कहना चाहती है कि हम उनके परिवारों को सहायता दे रहे हैं, लेकिन सरकार उनके लिये कुछ नहीं कर रही है। आज हमारे वीर जो स्वर्गवास पधारे, उनके पीछे उनकी पत्नियां और कुटुम्ब वाले विलाप कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि हमें जमीन मिले, लेकिन उनको जमीन नहीं मिल पाती है। हमारी तहसील में एक भगोला ग्राम है जिसमें एक जवान मरा, जिसका नाम विरजागगासिंह था, या क्या था पता नहीं लेकिन जब मैं दौरे पर गया था तब निर्माण मंत्रीजी भी वहां पर पधारे थे। उनके गांव वालों ने कहा कि हमारे जवान के नाम से एक माध्यमिक शाला इस गांव में खुलनी चाहिये, उनकी और कोई मांग नहीं थी, पंचायत समिति और जिला परिषद् की तरफ से भी यह मांग की गई, लेकिन वहां पर अब तक माध्यमिक शाला नहीं खुली। उसके परिवार वाले चाहते हैं कि उनको खेती मिलनी चाहिये, ताकि वे लोग अपना गुजर कर सकें। इसी तरह से एक निंबोला गांव है, वहां का भी एक जवान लड़ाई में हताहत हुआ था, वहां वालों की भी मांग है कि उनके नाम पर एक माध्यमिक शाला खुलनी चाहिये, जिला परिषद् और पंचायत ने भी उसके बारे में लिखा है लेकिन अब

(श्री लक्ष्मीचन्द)

तक नहीं खुली। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, कि इन दोनों वीरों के नाम से उनकी यादगार के लिये माध्यमिक शाला खोली जाये।

अध्यक्ष महोदय, पुलिस के बारे में भी कई लोगों ने कहा। आज हमारा इलाका मध्य प्रदेश से मिला हुआ है और आये दिन वहां पर डकेतियां होती हैं। थोड़े दिन पहले ही बानानी गांव में डकैती हुई। डाकू लोग आते हैं और आदमियों को उठा कर ले जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले पता नहीं लगा सकते। डाकू लोग बच्चों को उठा कर ले जाते है और रुपया देने पर छोड़ते हैं। अभी एक गांव रायथल में डकेती पड़ी थी। डकैतों का रास्ता घेर लिया गया था। यहां पर कलेक्टर, एस. पी., डी. वाई. एस. पी, आदि भी आ गये थे और १२ घन्टों तक डकैतों को घेर रखा लेकिन फिर भी पुलिस वाले कुछ नहीं कर सके और डकेत निकल गये, पुलिस डकेतों को नहीं पकड़ सकी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार को इन सारी बातों की तरफ ध्यान देना चाहिये। इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री अध्यक्ष : श्री खानपुरिया।

श्री माधोलाल खानपुरिया (अटरू) : अध्यक्ष महोदय, बजट के बारे में जो वाद-विवाद हो रहा है उसके बारे में मैं भी उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि यह बजट जो हमारे वित्त मंत्रीजी ने रखा है यह बिल्कुल सही और सच्चे माने में है क्योंकि हमारी सरकार को समाजवाद लाना है और समाजवाद कैसे आयेगा ? यह सब उसमें बताया है, और इसमें जो भी बातें रखी हैं वह सही है और इस बजट में जो बड़ी बड़ी योजना और बड़े काम जैसे बिजली है, नहरों के हैं, शिक्षा के हैं, विश्व विद्यालय के हैं, ऐसे बड़े बड़े काम अपने बताये हैं, वे बिना पैसे के चलेंगे नहीं। इसलिए बजट में जो आपने कर लगाये हैं वह लगाने चाहिए थे, नहीं तो पैसा कहां से आता। जो पैसा करों के द्वारा लिया गया उसके बजाय और कोई योजना बनाकर लानी चाहिये थी इसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है लेकिन मैं थोड़ा सा वित्त मंत्रीजी से अर्ज करूंगा कि आपने जितना बोझ लादा है वह काश्तकारों पर लादा है। फिर आपने मवेशियों पर बड़ा भारी टैक्स लगा दिया। बिना मवेशियों के काश्तकारों की काश्तकारी हो नहीं सकती इसलिए यह जो आपने ५ पर्सेन्ट कर मवेशियों पर लगाया वह नहीं लगाना चाहिये। इसके साथ-साथ जो आपने घी और तैल पर कर लगाया है वह भी बहुत ही ज्यादा है इसमें यह भी मालूम नहीं पड़ रहा है, कि यह कर किस पर पड़ेगा ? काश्तकारों पर पड़े तो इसको वापिस लेना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि वित्त मंत्रीजी ने कहा था कि राजस्थान पर प्रकृति का दो-चार साल से प्रकोप हो रहा है लेकिन हमारे कोटा, बून्दी और झालावाड़ पर कृषि मंत्रीजी का प्रकोप हो गया है (हीयर हीयर की आवाज) क्योंकि वहां की जनता ने अनाज पैदा किया है, वहां पर काफी मात्रा में अनाज है लेकिन वहां पर भाव निर्धारित कर दिये गये हैं। वहां पर जवार ४३) क्विन्टल बिकी है जबकि दूसरी पर जवार ४३) क्विन्टल बिकी है, जबकि दूसरी जगह ६०) क्विन्टल बिकती है, मक्का पर भी इसी प्रकार रोक लगा रखी है।

(श्री माधोलाल खानपुरिया)
कृषि मंत्रीजी से अर्ज करूंगा कि इन तीन जिलों ने क्या जुर्म किया है? जिसके कारण प्रकृति ने तो प्रकोप कम किया लेकिन आपने प्रकोप ज्यादा किया। कोटा, बून्दी और झालवाड़ा जिलों में इतना अनाज पड़ा है जो सड़ने लगा है और जब तक आप भाव निर्धारित करके लेने की व्यवस्था नहीं करेंगे तो दो-चार महीनों में और भी बिगड़ जायेगा।

दूसरे वहां हर सिंचाई के साधन बहुत कम हैं, वहां की भूमि उपजाऊ है इसलिए वहां पर बिजली का प्रबन्ध होना चाहिये ताकि कुओं से सिंचाई हो सके।

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रसिंह बर्फा।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा): अध्यक्ष महोदय, बजट अभिभाषण पर हो रहे वाद-विवाद के सम्बन्ध में हमारे वित्त मंत्रीजी के आंकड़े और भाषण के जंजाल को पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि आपने हास्यप्रद विषय में कृष्णलीला जिस तरह कही जाती है, वह लीला की है। उधर बालकृष्ण हैं और लीला के बजाय कौल करते हैं, तूफान की तरह हमेशा कार्य किया करते हैं। देखने में बड़े सुन्दर हैं लेकिन उनकी जो कलम चलती है वह हमेशा गांव वालों पर ही चलती है। यदि अध्यक्ष महोदय, ये तन से काले होते तो अति उज्जवल मनवाले होते इसमें दो राय नहीं है·······

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): मन से काले हैं।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा: आप कुछ भी अर्थ लगा लीजिये। मैं निवेदन कर रहा था, कि वित्त मंत्रीजी ने जितने बजट रखे, उनमें हमेशा घाटा ही बताते गये और घाटे की पूर्ति के लिए नये टैक्स इम्पोज करते गये और ये नये टैक्स हम गांव में रहने वालों पर ही लगाते रहे, डाइरेक्टली या इनडाइरेक्टली, व्यक्तिगत रूप से इसका उत्तर किसानों और मजदूरों पर ही अधिक पड़ता है। घाटा पूरा करने के लिये आंकड़ों का जाल जंजाल रख देते हैं। गत वर्ष उन्होंने जो टैक्स लगाया उसमें मैं निवेदन करूं यदि गलत नहीं कह रहा हूं तो साढ़े तीन करोड़ या ४ करोड़ की बकाया है। टैक्स की रकम समझ लीजिये या और समझिये इतनी रकम बकाया है और सरकार जागरूक नहीं है, उसको वसूल करने के लिये तथा वसूल करने में शिथिलता बरतते हुए नित्य नये कर नया रूप देकर जनता पर तोड़-मरोड़ करके लगा देते हैं।

मैं इसके खिलाफ नहीं। टैक्स लगाइये। टैक्स लगाइये–क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि टैक्स के बिना विकास नहीं होगा। मगर उस टैक्स का या दूसरी रकम का अगर आप सदुपयोग नहीं करते हैं तो आपका टैक्स लगाने का जो मकसद है वह पूरा नहीं होता है।

मैं, अध्यक्ष महोदय, गांवों की और आपकी मार्फत वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं। मुझे इस बात की जानकारी है कि बड़े बड़े ठेकेदारों में, या दूसरे पूंजीपतियों में, दुकानदारों में और व्यापारी वर्ग में टैक्सों की रकम बकाया है, लेकिन इसके अलावा किसानों में भी काफी अकाल के कारण बकाया है। उसके लिये आपने उन्हें क्या रिलीफ दिया है? सिवाय इसके कि फेमिन में आपने उनको रिलीफ दिया है, वह यह कि वसूली को सस्पेन्ड कर दिया है। वह बहुत कम मात्रा में रिलीफ है, इसलिए उस बकाया

(श्री चन्द्रसिंह बर्फा)

की वसूली का माफ कर देने का रिलीफ देने का जो प्रश्न है इस रिलीफ को न देने में वित्त मंत्रीजी अड़े रहे हैं। आपको मालूम है कि हरिराम धारू के प्रश्न के उत्तर के बाद में बड़ी संजीदगी से उन्होंने कहा था कि पिछड़ी जाति को यदि आप फायदा पहुँचाना चाहते है, तो उनको आप बिना ब्याज पैसा दीजिये, ताकि वह अपने को सम्भाल सकें। उस वक्त उन्होंने खुद ने आपत्ति की और कहा, कि हम बिना ब्याज के पैसा नहीं दे पायेंगे।

आप कहते हैं, बड़ी सफाई के साथ कि इरिगेशन के सोर्सेज़ बढ़ा रहे हैं, नहरें बढ़ा रहे हैं। वहां भी आपने एक करोड़ का घाटा अपने भाषण में बताया कि इतना घाटा प्रति वर्ष होता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप प्रथमबार इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इसके बाद में भी आपको आगे करना होगा और उसके बाद भी जब तक आपकी योजना पूर्ण नहीं हो जाये तब तक आपको घाटा ही घाटा रहेगा। मेरा निवेदन है कि आप उसको घाटा नहीं समझें बल्कि आने वाले वर्षों में वह आपके लिए, आपकी सरकार के लिए और देश के लिए एक लाभप्रद चीज होगी। इसलिए आप उसे घाटा नहीं मानें।

बहुत सफाई के साथ आपने कहा कि हमने रिजर्व बैंक आदि से कर्ज लेकर सारा काम चलाया है। अध्यक्ष महोदय, यदि आप कर्ज लेते आये हैं तो कर्ज लेना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन कर्ज होता है, जो ऋण होता है यह दुधारी तलवार की तरह होता है। यदि इसे सतर्कता से बरता जाये, तो वह उपयोगी साबित होगा और यदि उसे उद्दण्डता के साथ बरता जाये, या लापरवाही के साथ बरता जाये, तो वह विनाश का कारण बन जायेगा। इसलिए मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, वित्त मंत्री महोदय! आप जो इन टैक्सों के लगाने पर या दूसरे मसलों पर जितना ध्यान देते हैं उतना अपना ध्यान इस ओर लगायें कि पहले के जो आपके करों का बकाया है, उसकी वसूली किस तरह की जाये, तो आप लोगों को अधिक राहत दे पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, हमेशा अनुपूरक अनुदान की मांग वित्त मंत्री महोदय पेश करते हैं। मैं निवेदन करूंगा, कि शिक्षा विभाग में इतनी लापरवाही हो रही है कि छः-छः वर्षों से अध्यापकों के फिक्सेशन नहीं हुए हैं और यह कहते जा रहे हैं कि हमारा घाटे का बजट है इसमें फिक्सेशन के कारण इतने पैसे की और आवश्यकता होगी। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें क्यों ढिलाई बरती गई है? क्यों नहीं उन कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाये जिन्होंने इसमें ढिलाई की है? आज, अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रेक्टिकल रूप में सदन के सामने एक उदाहरण पेश करूंगा, जिसको जानकर आपको ताज्जुब होगा। एक वैद्य हैं, उनका पांच साल का फिक्सेशन का मामला है, उस फिक्सेशन के १५१ रुपये लेने के लिए उनको १८७ रुपये खर्च करने पड़े हैं, लेकिन अभी तक उन्हें पैसा नहीं मिला है। इस प्रकार की ढिलाई क्यों बरती जा रही है? मेरे कहने का मतलब यह है कि वित्त मंत्री महोदय और सम्बन्धित मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में ध्यान दें।

अब रहा सिंचाई के ऊपर टैक्स का सवाल। लगाइये आपने जो यह बतलाया कि एक

(श्री चन्द्रसिंह बर्फा)

करोड़ का घाटा होता है उसके लिए तो मैंने निवेदन कर दिया कि दो वर्ष में, या पांच वर्ष में, या दस वर्ष में आपका यह घाटा पूरा होने का नहीं हैं। परन्तु यह घाटा नहीं है, वित्त मंत्री महोदय ! आप इसे घाटा मानते हैं, मैं तो कहूंगा कि इसमें वित्त मंत्री महोदय भूल कर रहे हैं। यह घाटा नहीं है, बल्कि आमदनी का बहुत बड़ा जरिया है, जिसके द्वारा बहुत बड़ा जरिया देश की प्रगति के लिए, देश को रोशन और चमन बनाने के लिए साधन बनाए जा रहे हैं। जिसको आप घाटा समझते हैं उसको मैं दूसरी तरह से देखता हूं। आप कृपया इसको घाटा न मानें।

अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के सम्बन्ध में, मैं निवेदन करूंगा, आज से साठ वर्ष, सत्तर वर्ष, और अस्सी वर्ष के पहले के बांध बने हुए हैं, लेकिन आपने सब जगह पर रेट एक कर दी है सिंचाई की, जब कि जो पुराने बांध हैं उन पर सरकार को खर्च नहीं करना पड़ता है। उनकी न तो कोई देख रेख होती और न उनमें कैनाल बनाई जा रही हैं फिर भी वही रेवेन्यू और वही वाटर रेट, वहां अधिक वसूली की जा रही है और उसी रेट के हिसाब से, जो सरकार ने एक नियम बना दिया है, ऐसे एरिया के अन्तर्गत पैसा चार्ज करते जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, और माननीय सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि और कोई खर्चा नहीं करके, वहां पर यदि एक ओवरसियर पहले था, तो अब पांच ओवरसियर लगा दिये होंगे, लेकिन उसकी कोई वाटर की कैपेसिटी बढ़ती नहीं है, वह इतने वर्ष पुराने बांध हैं; तो फिर वहां पर ओवरसियर इन्जीनियर और दूसरा अधिक स्टाफ लगाने की क्या आवश्यकता है ? आप किसान को वह सहूलियत दीजिये, जो उन्हें मिल सकती है।

दूसरी बात यह है कि हमारे क्षेत्र में, जैसा अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं जसवन्त सागर से पानी मिलता है। मैं निवेदन करूंगा,

(२.२५ म.प.)

(राव श्री नारायणसिंह, मसूदा, उपाध्यक्ष पदासीन)

कृषि मंत्री ने इसके लिये यह नियम लगा दिया है कि सिंचाई का एक एकड़ का पांच रुपया लेंगे। लीजिये, कोई बात नहीं। लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि उस बांध की ऐसी स्थिति है कि एक या दो गांव जो उसके नजदीक हैं उनको तो श्री वाटरिंग या फोर वाटरिंग मिल जाते हैं, लेकिन और गांवों को एक-एक वाटरिंग देकर बाद में इरीगेशन बन्द कर देंगे, उस समय क्या होगा ? तो इसमें यह बात है कि एक तो वह बांध पुराना है और पुराना होने के कारण जो नहरी जमीन है या कल्टीवेबल एरिया जितना है वह इरीगेट होता नहीं है। नहरी एरिया के लिए मैं सिंचाई मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि इस इलाके में या तो आज या कभी जब आपको सहूलियत हो पांच महिने में, सात महिने में सर्वे करा कर कृपया यह जानकारी तो लें, कि इन बांधों के नीचे जितना नहरी एरिया है और उस नहरी एरिया से जितनी सिंचाई होनी चाहिए, उसमें से बचा हुआ एरिया कितना रह जाता है। और उस बचे हुए नहरी एरिया का टैक्स किसानों को कितना देना पड़ रहा है, जो फालतू बोझा है। आप क्लासिफिकेशन कराने की वहां कृपा कीजिये ताकि उन लोगों को कुछ राहत मिल सके।

(श्री चन्द्रसिंह बर्फा)

सरकारी स्टाफ के वेतन बढ़ाने के सम्बन्ध में कुछ कहने के बजाय वित्त मंत्री महोदय ने बड़ी सफाई के साथ कहा कन्ज्यूमर स्टोर खोलेंगे। लेकिन उसका इन्तजाम कौन करेगा ? कौन साहब ! और कोई ईमानदार आदमी नहीं, जो व्यवस्था कर सके। आज बहुत से कन्ज्यूमर स्टोर चल रहे हैं, उनमें हम देखते आये हैं, आज से नहीं १९४९ से देखते आये हैं कि ये कामयाब कम होते हैं क्योंकि न तो इनके पास पूंजी का साधन है और न यह साधन कर पाते हैं। एक बात और है, जब वहां सामान मिलेगा तो फिर तो हर नागरिक का, शहर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज है कि वह स्टोर पर जाये और सामान खरीदे। वित्त मंत्री बतायेंगे कि क्या आप कोई प्रतिबन्ध लगायेंगे कि हम फलां आदमी को नहीं देंगे फलां आदमी को नहीं देंगे। इस पर आप स्वयं सोच सकते हैं। हम सोचते थे, और राज्य सरकार के कर्मचारी भी आशा करते थे, कि जब बजट आयेगा तो उन्हें कुछ मिलेगा, क्योंकि कभी मिनिस्टर की तनख्वाह बढ़ा देते हैं कभी एम. एल. ए. की बढ़ा देते हैं और कभी सैक्रेटरीज की बढ़ा देते हैं, तो मुझे बताइये कि एक चपरासी जिसके ऊपर भी आपके बराबर लाइबिलिटीज हैं, यदि आपके पांच बच्चे हैं तो उसके भी होंगे, कोई आपने प्रतिबन्ध नहीं लगाया है कि उसके दो ही होंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ज्यादा होंगे।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : हो सकता है लेकिन उनके ऊपर भी उतनी ही लाइबिलिटीज हैं जितनी आप पर हैं। इसलिए आप इस पर पुनः विचार करें और लो-क्लास के जितने कर्मचारी हैं उनके वेतन में बढ़ोतरी करें और यदि आप दूसरों के लिए न करें तो कम से कम फोर्थ क्लास सर्वेन्ट की तनख्वाह तो सेन्टर के बराबर करके रहें, तब तो आपको मान सकते हैं। नहीं तो गांव में रेल्वे के आदमी भी रहते हैं और पोस्ट मास्टर भी रहता है और वहां आपके कर्मचारी भी रहते हैं—वहां उनकी और इनकी तनख्वाह में कितना अन्तर है। कोई गांव में कन्ज्यूमर्स स्टोर होगा, तो यह आप कह देंगे कि रेल्वे कर्मचारी को मना कर देंगे या अपने कर्मचारियों को देंगे। इसलिए आप इस पर विचार करें। मेरा निवेदन है कि ये जो आदमी हैं इनको एक तरफ तो आप भर पेट रोटी नहीं दें और फिर काम चाहें चौबीस घन्टे और उसके बार में भी तनख्वाह नहीं बढ़ावें, तो यह कहां का न्याय है, साहब। आप जरा उनकी हालत को देखिये। आज दुनिया के मजदूर आठ घन्टे काम करते हैं, और आप उनसे २४ घण्टे काम लेते हैं, फिर भी उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी नहीं करते। आप टैक्सेज लगायेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आप किसी राय को मानने वाले नहीं। लेकिन जहां तक उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने किसानों पर सरचार्ज लगाया, वह एमर्जेन्सी के समय, यह कहते हुए कि एमर्जेन्सी है, इसलिए यह सरचार्ज लगाया जाता है, लगाया। आपने यह एमर्जेन्सी का नारा लगाकर ... किसानों पर सरचार्ज लगाया। अब कहां है एमर्जेन्सी ? अब तो एमर्जेन्सी नहीं रही है। आप जब बजट पर बहस करने के लिए हाउस में आते हैं, तो आपको कहना पड़ता है। मगर मैं यह कहूंगा कि जो कुछ टैक्सेज आपने

(श्री चन्द्रसिंह वर्मा)

इम्पोज किये हैं, और करते जा रहे है उनका कितना प्रतिशत सही रूप में वसूली के रूप में आपको प्राप्त होता है। आप इस पर कृपया गोर करें।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि आप कहते है कि नहीं छोड़ेगे, हम किसी को भी। मवेशी क्यों किसान पालते। अरे कौल साहब डूब मरिये, गांवों में लोग कहते हैं, कि सांड, बैल हमारे मा-बाप हैं और आप उन पर भी टैक्सेज लगाते है। हमारे यहां गांव वाले यह कहते हैं कि यह हमारे अगले जन्म के बाप और भाई हैं और हमारे पास रहते हैं, उन पर भी आप प्रतिबन्ध लगाते हैं। आप इसको तो निपटारा कीजिये।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह चुनाव जीत कर आने के लिए बढ़ाया है।

श्री चन्द्रसिंह वर्मा : आपका एक नारा समाजवादी समाज का और समाजवादी समाज को फली भूत करने वाला जिसको हमारे वित्त मंत्री, सुनते हैं या नहीं कौल साहब आप कहते हैं धन और धरती बंट कर रहेगी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने धरती पर तो सीलिंग लगा दिया। धन का क्या होगा। तिजोरियों में रखा हुवा धन आप से हरगिज नहीं निकलेगा। कम-से-कम आप वह धन जो तिजोरियों में है, उसको तो निकलवाइये। अगर यह आप नहीं कर सकते तो कम-से-कम उन आदमियों के पास चार-चार और ६-६ बंगले हैं, उन पर आपने टैक्सेज लगाने का क्यों नहीं विचार किया। आप यह विचार करलें कि जिनके पास १५ हजार तक की बिल्डिंग है उनको माफ करेंगे और इससे ऊपर कीमत की जो भी बिल्डिंग होगी, उन पर टैक्स लगावेंगे। आप उन पर टैक्सेज क्यों नहीं लगाते ?

आपने डालडा पर टैक्स लगाया। ठीक है लगाइये, आपने ही इस डालडे को अपनाया और पनपाया। इस पर जितना टैक्स लगादें, लगावे, बहुत बढ़िया काम होगा। आप क्या खाते है, काश्मीर से अंगूर और केसर भी ले आवें, मगर हमारे गरीबों के पास क्या रखा है। हमारे यहां पर घी ही है और उस पर भी आपने टैक्स लगा दिया है। यह टैक्स आपने किसानों पर लगा कर किसानों पर ज्यादा बर्डन टैक्सों का कर दिया है।

आपने किसानों के बच्चों को एक लम्बरदारी की तनख्वाह मिलती थी वह भी आपने लम्बरदारी समाप्त कर दी। मैं आप से कहना चाहता हूं कि उससे आपको कितनी मदद मिलती थी, वे २०-२० हजार का मुतालबा वसूल करते थे और अब आपको कितनी परेशानी हो रही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उपाध्यक्ष महोदय, उप-राजस्व मंत्री ने यह कहा भी था कि यथा संभव बड़े-बड़े कस्बों में भी नहीं। आप बतावें कि आपका पटवारी कहां-कहां इसके लिये फिरेगा। आप गांव वालों से व उन लोगों से बेगार लेते हैं और उनको फूटी कोड़ी नहीं देते हैं। आपको एक भी मिसाल नहीं मिलेगी कि फलां चौधरी रकम गबन कर के चला गया। आपको यह कहने का मौका नहीं मिलेगा, मगर खैर, इसके बारे में आगे क्या होने वाला है, यह तो सब आपको बाद में मालूम होगा।

इसलिये कौल साहब, आप इस पर पुनः विचार करिये, घबराइये नहीं, सामने बैठने वाले लोग क्या कहेंगे इनकी चिन्ता न करें। मान लीजिये ये सब एक ही हैं आप घबराइये

(श्री चन्द्रसिंह बर्मा)

नहीं:--"यह सत्य है, हैं आप हममें और हम हैं आप में; जल में भरी ज्यों भाप है वह भी भरा है भाप में।" जनता आपकी है और आप जनता के नुमाइन्दे हैं। ८० पर्सेण्ट जनता के हित में आप जरूर देखिये और जो पहले की बकाया वसूली है उनको आप वसूल कीजिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन में अभी जो तकरीरें हुई हैं मैं खास तौर से उन माननीय सदस्यों को, माननीय महानुभावों को जिन्होंने दौराने तकरीर कुछ ऐसी बातें रखी, जिसकी वजह से हमें यह मौका मिला, कि सदन के सामने कुछ मुद्दे रख कर जो कहीं भी गलती या गलत फहमी या कोई भी गलत आंकड़े रख दिये गये हैं उनको ठीक कर सकें।

योजना को लेकर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर माननीय सदस्यों ने दो-तीन मुद्दे रखे हैं। एक तो यह कि योजना के अन्दर जो तीसरी पंच वर्षीय योजना खत्म होने जा रही है उस योजना में राज्य सरकार ने जो कोई भी फिसकल टारजेट मुकर्रर किये थे, उनमें उन्होंने पूर्ति नहीं की। यह भी कहा गया कि कहीं पर फिसकल टारजेट पूरे कर लिये, मगर फिजिकल टारजेट पूरे नहीं हुए। यह भी कहा गया, कि हमारे यहां राजस्थान के लोगों की माली हालत ठीक नहीं है और यहां पर-केपिटा इन्कम में बढ़ोतरी नहीं कर पाये। यह भी कहा गया कि जो कुछ हम आंकड़े देते हैं वे आंकड़े एक माया-जाल है। ये सब बातें मुख्तलिफ माननीय सदस्यों ने कहीं। इस संबंध में मैं नम्रता-पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, कि तीसरी पंच साला योजना जो खत्म होने जा रही है, उस वक्त इस सदन ने योजना का और उसके विकास के लिये जो प्रारूप बनाया था, उसको बदल कर जो कुछ मुकर्रर किया था, उसको करीब-करीब हमने पूरा किया है। फिसकल टारजेट और फिजिकल टारजेट के संबंध में भी। यह ठीक है कि कहीं किसी जगह ज्यादा खर्चा हो गया हो और वो भी कई कारणों से करना पड़ा हो और ज्यादा रुपया खर्च हो गया हो और उसकी वजह से दूसरी जगह के लिये जो सीलिंग मुकर्रर था, वहां पर कम खर्च हुआ हो, ऐसा हो सकता है। मगर इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि देश में ज्यादा से ज्यादा धन उपलब्ध किया जावे और इसलिये ज्यादा धन-राशि इस कार्य के लिये दी जावे और ज्यादा कुए बनाये जावें, जिससे किसान लोगों की माली हालत और दूसरे लोगों की माली हालत ठीक हो सके, इस बात को ध्यान में रखा है, और इसको ध्यान में रखते हुए हमने उनको सुविधायें दी हैं, वह चालू रखी जावे और जो चीज समाज को जरूरत हो उसको भी ध्यान में रखते हुए तीसरी पंच-वर्षीय योजना को पूरा किया है और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का अभी प्रारूप नहीं बन पाया है। लेकिन चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का पहला साल जिसका प्रारूप ३६.६६ करोड़ का है, जिस पर प्रकाश डाला गया है, हमने और सदन ने यह कहा था, कुल प्लॉन सीलिंग २०८.९७ का मुकर्रर किया था, जिसको हम कोर ऑफ दी प्लॉन कहते हैं और उसके मुकाबले २०९.६४ का खर्चा हम तीसरी पंच साला योजना पूरी होने होने कर पायेंगे। जो एडवान्स एक्विजन में धन राशि मिली और जो गैस टरबाइन में पैसा मिला था, वह इसमें अंकित नहीं किया है। तो ऊपरी तौर से जो

(श्री मथुरादास माथुर)
सीलिंग, कोर ग्रॉफ दी प्लॉन मुकरर किया था, वह पूरा किया है।

अब मैं उन सेक्टर्स में, जिनमें फिसकल फाल्स हुए हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूं। खास तौर से कहा गया कि इरिगेशन और मिनरल डेवेलपमेंट में जो धनराशि मुकर्रर की थी, वह पूरी नहीं कर पाये। इरिगेशन के लिये ९७.७ का कोर में रखा था वहां ७२ करोड़ ही खर्च कर पाये। मिनरल डेवेलपमेंट में ३.५ करोड़ का प्रावधान किया गया था वहां १.६५ लाख रुपया ही खर्च हुआ, यह बात कही गई, इसको मैं स्वीकार करता हूं, पर साथ ही नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह; खर्चा सिंचाई में कम हुआ, उसमें माइनर इरिगेशन में जो हमारे फिजिकल और फिसकल टार्गेट्स थे उससे ज्यादा खर्च किया है, छोटे कुएं खुदवाये हैं, लघु सिंचाई पर ज्यादा खर्च किया है। राजस्थान कैनाल में ३८ करोड़ का प्रावधान रखा था, वहां २९ करोड़ ही खर्च कर पाये, इस वजह से इरिगेशन सेक्टर में ओवर ऑल ९७.७ रखा था, वह ७२ करोड़ ही खर्च हुए, उसकी कुछ वजह थी। वहां का टेरेन और राजस्थान कैनाल की एक प्रोयेरिटी बन रही थी, वह भी एक बड़ा मुद्दा था, कि राजस्थान कैनाल में हम कम खर्च कर पाये।

मिनरल डेवलपमेंट के अन्दर कम खर्च नजर आता है; उसकी वजह यह है कि २७५ लाख रुपये का प्रावधान, एक कारपोरेशन, माइनिंग कारपोरेशन बनाने का फैसला किया, केलिसयम फ्लोराइट, पलाना वगैरह को एक्सप्लॉइट करने के लिये, मेन्युफैक्चर करने के लिये, २७५ लाख का प्रावधान किया गया था, पर केलिसयम फ्लोराइट आदि की रिपोर्ट हमारे पास पूरी नहीं पहुंच पाई, इसलिये यह कार्य नहीं कर पाये और उस सिलसिले में २७५ लाख रुपया खर्च करना था, वह नहीं कर पाये। माइनिंग डवलपमेंट में ३५ लाख खर्च कर पाये।

तो दो बड़ी बातें सदन में कही गई थीं कि हमने इरिगेशन और माइनिंग डेवेलपमेंट के लिये कम खर्च किया है, जो कि बड़े इम्पोर्टेन्ट फैक्टर्स हैं; इस सम्बन्ध में मैंने आपसे निवेदन किया, कि इसमें जो राशि रखी गई थी, उसको हमने खर्च किया है। राजस्थान कैनाल में जितना हमारा सीलिंग था उतना खर्च नहीं कर पाये, उसकी वजह मैंने आपके सामने रखी; कि माइनर इरिगेशन में ज्यादा खर्च किया है। माइनर इरिगेशन के फिजिकल टार्गेट्स के बारे में मैं बाद में निवेदन करूंगा। इधर रुपया कम खर्च हुआ, पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, माइनर इरिगेशन; एनिमल हस्बेन्डरी, एज्यूकेशन, मोडरन मेडिशन्स में जो सीलिंग मुर्करर की थी उससे ज्यादा खर्च हुआ है क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा तवज्जोह देनी थी, और उससे माइनर इरिगेशन जुड़ा हुआ था इसलिए माइनर इरिगेशन पर ज्यादा खर्च किया। तो इस तरह कुल मिला कर तीसरी पंचसाला योजना में जो फिजिकल टार्गेटस मुकर्रर किये थे, उसके अन्दर पूरा खर्च किया, फिजिकल टार्गेट्स अचीव किये हैं।

एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में १५ लाख टन का पोटेन्शियल क्रियेट करने का हमारा फैसला था। वहां हम ११.३४ का ही कर पाये। इसकी वजह यह है कि कुछ तो इरिगेशन सेक्टर, राजस्थान कैनाल और मेजर

Page No. 77

(श्री मथुरादास माथुर)
मिडियम इरिगेशन पर पूरा खर्च नहीं हो पाया इसलिए जो एकरेज आफ लैंड उनके कमाण्ड में आने वाली थी, वह नहीं आ पाई। उसके अलावा जो काम पूरे हो गये, पर तीन साल से सूखा पड़ता रहा, इसलिए इरिगेशन के जो कुए बने उनमें पानी नहीं आया इसलिए भी जिन एरियाज को वे कुए कमाण्ड करते थे, उनमें हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन घट गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन घटने की एक और दूसरी बड़ी वजह थी, वह थी, फर्टीलाईजर की कमी। फर्टीलाइजर उपलब्ध करना राजस्थान सरकार की ताकत के बाहर की बात थी, क्योंकि यह फोरेन से आता है, फोरेन एक्सचेन्ज की कमी की वजह से बाहर से नहीं आ पाया, इस वजह से फर्टीलाइजर में कमी आई, गोया कि धनराशि काफी खर्च हो गई।

इसी तरह पावर और रोड्स के बारे में जिक्र किया गया कि रोड्स का जो टार्गेट था, वह पूरा नहीं कर पाये और जो एडीशनल क्रियेट करना था, वह भी नहीं कर पाये। जो जनरेशन करने का काम है, वह राजस्थान सरकार नहीं करती, राजस्थान सरकार से अलग दूसरी एजेंसी है, वह जनरेशन करती है; उसके ऊपर कन्ट्रौल जितना होना चाहिये, उतना नहीं हो पाता। भाखरा प्रोजेक्ट का जनरेटर आज तक अमल में आ जाना चाहिये था, पर वह ६७ में अमल में आयेगा, थर्मल पावर में भी कमी रही, राणा प्रतापसागर स्कीम अब तक पूरी हो जानी चाहिये थी, पर वह ६८ में शुरू होगी। तो कुछ कमी है, हम पूरा करना चाहते हैं। पर नोन-अवेलेबिलिटी, मेटिरियल की कमी, फोरेन एक्स्चेन्ज की कमी की वजह से कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है, इसलिये जो चाहते थे, वह पूरा नहीं कर सके पर पावर सैक्टर में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एडिशनल केपेसिटी जनरेट नहीं कर पाये पर गावों में बिजली देने का काम हमने जो हमारा टार्गेट था, उससे चौगुना काम कर डाला है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और बोर्ड ने बडी हिम्मत से काम किया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : पहले साल में इलेक्ट्रिसिटी के लिये कितना पैसा खर्च किया और अगले साल में कितना करेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : प्लान में जितना रखा है वह बताता हूं। पावर के अन्दर १२.१६ वह हमने रखा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : पहले के कम्पेरिजन में कम रखा है क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : पूरा कम्पेरिजन बताता हूं कौनसे साल से पूछना चाहते हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: पिछले साल कम हुआ जो सिंचाई के लिये जरूरी है, पहले साल कितना था, ६४-६५ में, ६५-६६ में और ६६-६७ में क्या है।

श्री मथुरादास माथुर : इस साल का तो बताया, कि जो प्रावधान रखा गया है १२ करोड़ का रखा गया। इसमें पहले ११.६ करोड़ का रखा गया था। मैं मानता हूं इस बात को कि हमारे पावर मंत्री महोदय ज्यादा धनराशि मांगते है, कुओं पर बिजली लगाने के लिये यह जरूरी है पर केपेसिटी आफ जनरेशन और राज्य के रिसोर्सेज का खयाल रखना पड़ता है।

(श्री मथुरादास माथुर)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि रोड सेक्टर में भी माननीय सदस्यों ने कहा कि हमने २,४५१ मील लम्बी सड़कें बनाने का टार्गेट रखा था पर १,१५० मील ही बना पाये। इसकी वजह एक ही है कि जो रिसोर्सेज हमको रोड्स के लिये देने चाहिये थे, वे उपलब्ध नहीं हो पाये। इसकी वजह से इस सेक्टर में कमी आई। मैं आपसे जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, सोशल एजुकेशन हैल्थ जिनमें हमने ज्यादा खर्चा किया उसके लिए पहले कह चुका हूं। फिजीकल टार्गेट्स भी प्रचीव किए हैं, वह नेशनल टारगेट्स से मेल नहीं खाते हैं, जैसे प्राइमरी एजुकेशन का कुछ पर्सेन्टेज प्रचीव करना था, वह नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास धन की कमी थी। इसलिए प्लान को रिवाइज करके कोर आफ दी प्लान बनाया था। इसलिए माननीय सदस्य जो भ्रम देने की कोशिश करते हैं ताकि तीसरी योजना में हमने कुछ नहीं किया, यह सही नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : मिनरल डेवलपमेंट के बारे में बताइए।

श्री मथुरादास माथुर : मैं कह चुका हूं, आप बाद में मुझ से फिगर्स ले लें। इससे जाहिर है कि तीसरी योजना में जो कुछ फिजीकल टारगेट्स कोर आफ दी प्लान में किए थे, उनको पूरा करने की कोशिश की है। एक दो सेक्टर्स में जो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना था, प्रायरीटीज को देखते हुए, वह किया, वरना सदन की इच्छा से हमने काम किया है।

हमारे सदन में यह भी सवाल चलता है कि हमारी पर-कैपिटा इन्कम के बारे में, हमने तीसरी योजना के अन्दर जो टार्गेट्स रखे थे, वे पूरे नहीं किए। तीसरी योजना में पर-कैपिटा इन्कम के टारगेट का फिगर कि हमारी ग्रामदनी यहां तक पहुँच जायेगी यह कहीं नहीं हमने लिखा था। फिर भी हम बराबर कोशिश करते हैं कि जो प्रास्पेक्टिव प्लानिंग के आधार पर आखिर जाकर हम लोगों की पर-कैपिटा इन्कम बढ़े और जो यह भ्रम हो कि राजस्थान की हिन्दुस्तान के मुकाबले में इकॉनोमी कम रही यह गलत है। राजस्थान योजना में ४८ प्रतिशत हमारा जो स्टेट इन्कम का हिस्सा है, वह एग्रीकल्चरल सेक्टर है और उसके अन्दर अकाल होने की वजह से कमी हुई है और फूड प्रोडक्शन में कमी हुई है, जिससे स्टेट इन्कम में रिफ्लेक्शन हुआ है। फिर भी दूसरे मुद्दों में काफी ग्रामदनी पैदा करके बैलेंस करने की कोशिश की है। मेरे पास तीसरी योजना के पहले चार सालों के फिगर्स हैं। पांचवे साल के आंकड़े अभी जून में इकट्ठे हो जायेंगे। मगर चार की फिगर्स जो टैब्यूलेट हो चुकी हैं उनके आधार पर यहां पर राजस्थान में इन्कम १७.२९ परसेण्ट बढ़ी है, बावजूद इसके कि अकाल पड़ा है, यह १९५४–५५ के प्राइसेज पर है। उधर इत्तफाक से भारत के अन्दर नेशनल इन्कम चार वर्षों मे १७.२९ परसेन्ट ही बढ़ी है, इसलिए कोई नहीं कह सकता कि हम पीछे हैं। मगर हमारी पर-कैपिटा इन्कम जो बढ़ी है, वह ६.६४ परसेन्ट है, बनिस्बत हिन्दुस्तान के जिसमें ७.२ परसेन्ट बढ़ी है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : फुडग्रेन्स का क्या भाव था १९५४–५५ में ?

श्री मथुरादास माथुर : जो भाव यहां था वही था। पर-कैपिटा इन्कम फूडग्रेन्स के

(श्री मथुरादास माथुर)
भावों से नहीं आंकी जायेगी हमने १९५४-५५ को बेस ईयर मान लिया है, कम्पेयर कर रहा हूं, स्टेट और नेशनल इन्कम को।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : पर-कैपिटा राजस्थान में कितनी है ?

श्री मथुरादास माथुर : पर-कैपिटा इन्कम की फिगर्स से सदन में कभी-कभी कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि हमारी पर कैपिटा इन्कम का हिन्दुस्तान की पर-कैपिटा इन्कम से मुकाबला करते है। हिन्दुस्तान की पर-कैपिटा इन्कम का बेस १९४८-४९ और १९४९-५० है तब राजस्थान नही बना था, इसलिए वह फिगर्स उपलब्ध नही हो सकती। हमारा बेस दूसरा है, उस बेस के आधार पर हमारा मुकावला नहीं हो सकता, फिर भी माननीय सदस्यों की तसल्ली के लिए करेंट प्राइसेज से मुकाबला करूंगा। १९५४-५५ के मुकाबले मैं बताऊं, लेकिन अखबारों में जो पढ़ लेते है और कहते हैं तो गलत फहमी हो जाती है, यह जो मुद्दा है पर-कैपिटा इन्कम का नहीं है। पर-कैपिटा प्लान पीरियड के ४ सालों को छोड़कर एवरेज निकालना पड़ेगा। हमारा १९६२-६३ में पर-कैपिटा इन्कम एकदम शूट अप हो गया और १९६३-६४ में नीचे आ गया, क्योंकि अकाल आ गया। अगर एक साल के अन्दर अकाल पड़ता है और पर कैपिटा इन्कम गिर जाती हैं और हम कहें कि गरीबी आ गई और बरबाद हो गए तो भ्रम में पड़ जायेंगे और जब अकाल नहीं आता है और पर-कैपिटा इन्कम शूट अप हो जाती है तो इसका मतलब यह नही है कि प्रोस्पेरिटी बहुत बढ़ गई है। चार साल में राजस्थान में ६.४ प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है और हिन्दुस्तान में पर-कैपिटा इन्कम ७.२ प्रतिशत बढ़ी हैं। मगर टोटल इन्कम में बढ़ोतरी दोनों की करीब करीब एक जैसे परसेन्टेज की है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान में पर-कैपिटा इन्कम कितना है ?

श्री मथुरादास माथुर : पर-कैपिटा इन्कम में मैं आपको एब्जालिटवली और इन्टेन्सिवली सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। बुरी है तो बुरी है, अच्छी है तो अच्छी है, आंकड़ा अपने आप बोलेगा। यह बात मैंने इसलिए कही कि स्टेट इन्कम के फिगर्स का रिफ्लेक्शन हमारे यहां के लोगों की इकोनोमिक कन्डीशन्स पर सही नहीं आएगा। इस लिए मैंने, जो बढ़ोतरी हुई है, उसका परसेन्टेज बताया। राजस्थान और हिन्दुस्तान की एवरेज पर-कैपिटा इन्कम का मुकाबला किया हैं। राजस्थान की पर-कैपिटा इन्कम १९६४-६५ के अन्दर मौजूद है। अगर करेंट प्राइसेज पूछते हैं तो १९६४-६५ की ३८२ है। और १९५३-५४ में २५७ है।

श्री दुर्गालाल बड़दार: ये एग्रीगेट हैं ?

श्री मथुरादास माथुर: पर कैपिटा इन्कम की कह रहा हूं। एक आदमी की औसत आमदनी १९५४-५५ में २५७ थी और करेंट प्राइसेज के बेसिस पर ३८२ बनिस्बत आल इन्डिया की, जो फिगर्स हैं, उनमें करेंट प्राइसेज १९६४-६५ आल इन्डिया का फिगर अवेलेबल नही है। १९६३-६४ का उनका ३७.७ है और १९४८-४९ के प्राइसेज पर

Page No. 80

(श्री मथुरादास माथुर)
उनका पर-कैपिटा इन्कम का फिगर २९९.८ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कभी करेंट प्राइसेज बोलते हैं, कभी पुरानी बोलते हैं। आप बताइए कि १९६०-६१ के प्राइसेज के बेसिस पर जो राजस्थान में अवेलेबल हैं और आल इन्डिया के भी अवेलेबल हैं, १९६०-६१ में पर-कैपिटा इन्कम राजस्थान की कितनी है और हिन्दुस्तान की कितनी है।

श्री मथुरादास माथुर : इसके लिए बेस फिक्स्ड होता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : १९५४-५५ को बेस मानकर बताइए।

श्री मथुरादास माथुर : करेंट प्राइज राजस्थान का १९६४-६५ का आंकड़ा २५७, १९६३-६४ का २३९, १९६१-६२ का २५२, १९६०-६१ का २४१।

(३ म. प.)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दोनों को एक्जामिन करने पर आप यह बताइये कि राजस्थान की पर-केपिटा इन्कम कितनी है और आल इण्डिया की पर-केपिटा इन्कम कितनी है?

श्री मथुरादास माथुर : उन्होंने ४८-४९ का बेस इयर माना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो ६०-६१ का ही बता दीजिये कि पर-केपिटा इन्कम कितनी थी? उनकी प्राइसेज ६०-६१ की मानिये।

श्री मथुरादास माथुर : इसका केलकुलेशन ६०-६१ पर करना पड़ेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो किया होगा। १९६०-६१ में पर केपिटा इन्कम राजस्थान में कितनी आती है और आल इन्डिया में कितनी?

श्री मथुरादास माथुर : राजस्थान के फिगर्स हैं ३८१....।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल—: ६०.६१ के।

श्री मथुरादास माथुर : वह हमारे पास अवेलेबल नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आप गलत कह रहे हैं और इसलिये गलत कह रहे हैं इसके आधार पर "At the end of the Third Plan, the per capita income at all-India level (1960-61) prices) is likely to be 385. It is estimated that at the end of the Third Plan the per capita income in Rajasthan would be only 355 (at 1960-61 prices). The relative beckwardness of the State can well be judged from this comparison."

श्री मथुरादास माथुर : यह आप कौनसी किताब पढ़ रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेमोरेन्डम राजस्थान सरकार ने फाइनेंस कमीशन को सब्मिट किया है उसमें लिखा है कि ६०-६१ की प्राइसेज पर-केपिटा इन्कम है ३५५ और आल इण्डिया की है ३८५ और आपकी राजस्थान सरकार यह कहती है "The relative backwardness of the State can well be judged from this comparison" या तो आप गलत पिक्चर सेन्ट्रल गवर्नमेंट को देते हैं या हाउस को गुमराह करते हैं और वास्तविक स्थिति जो राजस्थान

Page No. 81

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की है, मैं समझता हूं, राजस्थान प्रान्त सबसे पिछड़ा हुआ प्रान्त है ऑल इन्डिया बेसिस पर and you are playing a fraud on this Assembly and on the people of Rajasthan by given false figures. This is your own document, a document which you have submitted to the Central Government just to extort money otherwise.

श्री मथुरादास माथुर : जोर से बोलने से प्राइसेज बढ़ेंगी नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बढ़े या नहीं, हाउस को मुगालता देने में माहिर हो गये हैं। यह आपका एक ट्रेन्ड हो गया है। आपने कहा कि ६०-६१ की प्राइसेज नहीं है, बेस नहीं है, केलकुलेशन भी नहीं है। नहीं हैं तो, फाइनेन्स कमीशन को कैसे दिया?

श्री मथुरादास माथुर : उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। सुनिये; हमारे पास जो बेस है उसको आंकड़े देकर बताया। करेन्ट प्राइसेज पर हमारा ३८२ का फीगर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसको आप तोते की तरह क्यों रटते हो बार बार, उसको हमने सुन लिया।

श्री मथुरादास माथुर : करेन्ट प्राइसेज का फीगर ऑल इन्डिया बेसिस पर ३८२ और राजस्थान का २५७, ६४-६५ का जो मेरे पास अवेलेबल है, ५४-५५ के बेस पर। करेन्ट प्राइसेज पर राजस्थान का ६३-६४ का ३३७ और ऑल इन्डिया का ६३-६४ का ३७०.७; ६२-६३ अवेलेबल नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह गलत है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप यह बता दीजिये कि ६०-६१ की प्राइसेज पर, पर-केपिटा इन्कम केलकुलेट की गयी वह करेक्ट है या गलत है?

(विराम)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गलत है। आपने यह कहा है कि ६०-६१ की प्राइसेज के हमारे पास केलकुलेशन नहीं हैं। केलकुलेट ही नहीं है। यह आपने हाउस के अन्दर गलत बात कही है कि ६०-६१ का केस नहीं है और केलकुलेट नहीं की है।

श्री मथुरादास माथुर : ६०-६१ की प्राइसेज हैं उसको करेन्ट प्राइसेज कहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आज के दिन उसको करेन्ट प्राइसेज नहीं कह सकते। ६५-६६ में जो करेन्ट प्राइसेज हैं उनको आप ६०-६१ की प्राइसेज को करेन्ट प्राइसेज नहीं कह सकते। कैसे कहते हैं?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यदि आप उसको करेन्ट प्राइसेज कहते हैं, तो जो आपने आंकड़ा बताया वह गलत हो गया।

श्री मथुरादास माथुर : यह इसलिये कहा....

श्री भैरोंसिंह : बैटर यह है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, कि यहां पर इस प्रकार आंकड़ों की जगलरी खड़ी कर के अपनी तरफ से हमेशा सदन को मुगालता दिया जाता रहा है और इस प्रकार हाउस को कॉन्फिडेन्स में लेने की चेष्टा की जाती रही है। इस हाउस के अन्दर इस प्रकार जो मुगालिज़ियाजों ने आज तक जो

(श्री भैरोंसिंह)
आंकड़े दिये हैं, उन सबका एक चार्ट बना लिया जाये, तो यह पता चलेगा कि झूंठ बोलने का आप दोनों ने ठेका ले रखा है। इस हाउस को मुगालता दिया जाता रहा है और इस हाउस के फ्लोर पर झूंठे आंकड़े देकर झूंठ बोला जाता रहा है।

श्री मथुरादास माथुर : गलतफहमी का ठेका आपने ले रखा है।

श्री भैरोंसिंह : हमने नहीं ले रखा है।

श्री मथुरादास माथुर : आपने जो फीगर्स कहे हैं किताबों में छपे हैं। पूरे प्लान पीरियड की पर-केपिटा इन्कम दी है, उनसे आप मुकाबला कर लीजिये। सवाल इतना रह जाता है, पर-केपिटा इन्कम का बेस करेन्ट प्राइसेज पर माना है, इन्डिया ने बेस माना है ४८-४६ और हमने माना है १६५४-५५, उनका डिफरेन्ट है और हमारा डिफरेन्ट है, प्राइसेज बढ़ती घटती जाती हैं, फ्लक्चुएट होती जाती हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १६६०-६१ के हिसाब से ३५५ पर-केपिटा इन्कम राजस्थान की और ऑल इन्डिया की बतायी आपने ३८५, वह सही है या नहीं, यह बता दीजिये ?

श्री मथुरादास माथुर : यह जो फाइनेन्स कमीशन के मेमोरेन्डम में दिये गये फीगर्स पढ़े हैं, मुमकिन है ६०-६१ की प्राइसेज को देख कर किसी पर्पज के लिये केलकुलेट कराये गये हों।

श्री भैरोंसिंह : यह मुश्किल हो जाता है, उपाध्यक्ष महोदय !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि फाइनेन्स कमीशन ने किसी पर्पज से दिये होंगे।

श्री मथुरादास माथुर : आज की करेन्ट प्राइसेज पर आते हो और आंकड़े आते हों तो देने पड़ते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किसी मकसद के लिए आंकड़े तैयार कराने पड़ते हैं यह आपने कहा। आप मेहरबानी करके यह बता दीजिये कि ६०-६१ की प्राइसेज पर राजस्थान की पर-केपिटा इन्कम ३५५ है या नहीं और ऑल इन्डिया की ३८५ है या नहीं, यदि है, तो है कह दीजिये और नहीं है, तो नहीं कह दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : मैं फीगर्स दे रहा हूं वह ५४-५५ की प्राइसेज के बेस पर दे रहा हूं और यह करेन्ट प्राइसेज पर देते हैं। करेन्ट प्राइसेज फ्लक्चुएट होती रहती हैं उसको छोड़ दीजिये। ५४-५५ को बेस लेकर प्लान के फर्स्ट ईयर, सेकिण्ड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का मैं बता सकता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेन्ट में १६६०-६१ के आंकड़े नहीं हैं क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : मेरे पास हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : योजना मंत्रीजी उपाध्यक्ष महोदय, फाइनेन्स कमीशन के मेमोरेन्डम में ६०-६१ के बेस को कहते हैं और यहां पर ५४-५५ के बेस को कहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, योजना मन्त्रीजी हाउस में झूंठ बोल रहे हैं। आज सुबह मेरा ही प्रश्न था। उस क्वेश्चन के जवाब में आप कहते हैं, योजना मंत्रीजी·······

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : ५४-५५ पर है, ठीक है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह सब गलत है।

क्वेश्चन मेरा आज सुबह हाउस में यह था। "तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में राज्य में प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी आंकी गई थी और कितनी उपलब्धि का अनुमान है।" उसके उत्तर में आपने बताया है।

"तृतीय पंच वर्षीय योजना के निर्माण के समय राज्य में प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े इस योजना काल के अन्त तक के लिये आंके नहीं गये थे। चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भिक ज्ञापन को तैयार करते समय उपलब्ध सामग्री के अनुसार जो प्रोजेक्शन किये गये थे, उनके अनुसार इस वर्ष में प्रति व्यक्ति आय १९६०-६१ की कीमतों पर ३५५ रु० हो जाने की आशा थी। सन् १९६५-६६ में प्रति व्यक्ति आय के अनुमान अभी तैयार नहीं हुए है।"

आपका कहना है कि फाइनेन्स कमीशन को जो फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट द्वारा ज्ञापन दिया गया वह किसी मकसद से तैयार करके दिया गया। हम यह जानना चाहते हैं, ६०-६१ का आपका बेस क्या है ?

श्री मथुरादास माथुर : बेस ईयर हमारा ५४-५५ है, जितने भी आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं, वे ५४-५५ को बेस ईयर मानकर किये हैं। अगर हमें ६०-६१ के फीगर केलकुलेट करने होते हैं, तो हमारा एक फार्मूला है, उस आधार पर उसको केलकुलेट करते है। आप इसका कम्पेरिजन ६१-६२ का बेस ईयर मान कर मत करिये, ५४-५५ का बेस ईयर है। ६१-६२ का जो फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने दिया है, वह कनवर्शन करने का फार्मूला है, उसी के आधार पर करके उसमें बताया गया है।

राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय ५४-५५ के प्राइसेज के आधार पर ६४-६५ की २५७ है। १९६०-६१ की प्रति व्यक्ति आय २५१ है और १९६१-६२ की प्रति व्यक्ति आय २५२ है। यह फीगर्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसका मकसद है कि इससे अन्दाज यह हो जायेगा, कहीं किसी साल में पर-कैपीटा इन्कम घटी है, तो वह फेमिन ईयर होने की वजह से घटी है। टोटल मिलाकर हमारी पर-केपीटा इन्कम गिर रही हो, यह बात नहीं है। जहां एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन कम हुआ है, तो उसको दूसरे सेक्टर से फीड करने की कोशिश की गई है। १९६४-६५ की आय प्रति व्यक्ति मैंने बतायी है, वह २५७ है।

श्री भैरोंसिंह : आपने जो यह १९६४-६५ के फीगर्स दिये हैं, क्या उसमें ६१ के सेन्सस के फीगर्स लिये हैं, या पोपुलेशन की ग्रोथ को बताते हुए बताये हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : इसका जो बेस है वह ६१ के सेन्सस के आधार पर है। इसमें ऐसा होता है कि जो पापुलेशन में ८ परसेन्ट इन्क्रीज होती है उसको ध्यान में रखते हुए केलकुलेट करते हैं।

(श्री नाथूराम मिर्धा के बार-बार बैठे बोलते रहने पर)

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, दोनों मंत्रियों में से एक मंत्री को बोलने दिया जाये। नाथूरामजी जो बैठे बैठे बोलते रहते हैं, उससे मंत्री महोदय की बात हम सुन

(श्री भैरोंसिंह)
नहीं पाते। ये बार बार उनको डिस्टर्ब करते हैं। इनको बोलने का तरीका नहीं आता, इस तरह से बैठे बैठे बोलकर सदन का डेकोरम खराब करते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने आपको बताया ६१ का मैम्बर्स इसका बेस है। हर साल जो आबादी बढ़ती है, जिस ट्रेन्ड से बढ़ती जाती है, उसको केलकुलेट करते हैं, यह मैथोलोजी है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से जो पर-केपीटा इन्कम के बारे में बहस चली है, उसके बारे में मैंने आपको पर-केपीटा इन्कम के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इसके साथ-साथ जो पर-केपीटा इन्कम में इन्क्रीज हुआ है, स्टेट इन्कम की जो ग्रोथ हुई है वह भी परसेन्टेज इकोनोमिक प्रिंसिपल पर रिफलेक्शन करता है, वह मैंने आपके सामने रखा।

इसके साथ-साथ मैं आपके सामने यह भी निवेदन करना चाहता हूं, हमारे यहां रूरल इन्डेटेडनेस क्या है, इसके बारे में जो डिपार्टमेन्टल सर्वे हुई, उसके हिसाब से ६० प्रतिशत फेमिलीज़ रूरल इन्डेटेड हैं और उसमें एक फेमिली के ऊपर जो कर्जा है वह ६५० रु० है। मगर उसमें से ४० प्रतिशत कर्जा प्रोडक्टिव प्रोग्राम्स के लिए है। इससे यह अन्दाज बनता है यहां जो इनकी आर्थिक स्थिति को लेकर रूरल इन्डेटेडनेस की हवा पैदा की जाती है, उसकी सही स्थिति यह है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हवा केवल इतनी ही पैदा की जाती है कि रूरल इन्डेटेडनेस है।

श्री मथुरादास माथुर : मगर साथ ही यह भी आपको पता होना चाहिये इसमें ४० प्रतिशत प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम्स के लिए है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन आंकड़ों में कुछ डिस्काउंट भी काटना पड़ेगा ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने यह समझ कर पहले ही काट कर बताये हैं। यह मैंने फीगर्स दिये हैं, वे रिपोर्ट के आधार दिये हैं।

कल माननीय सदस्यों ने योजना की चर्चा करते हुए सदन के सामने यह रखा कि हमारी नोन-टैक्स रेवेन्यू स्टेट एन्टरप्राइज में लगायी है, उसके अन्दर जितना रिटर्न मिलना चाहिये वह नहीं आ पाता है। इस-लिए हमारी यह कोशिश होनी चाहिये और माननीय सदस्यों ने यह चाहा है कि इससे आय बढ़े, इसको सुचारु रूप से चलाया जाना चाहिये। इसके रिटर्न्स अच्छे आयें यह हम चाहते हैं और इसके साथ-साथ राष्ट्रीयकरण की जो भावना है, उसको उद्योगों के साथ हम लगायेंगे तो हम समाजवाद के लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे। जहां तक माननीय सदस्यों ने इस ओर सदन का ध्यान दिलाया, उसके लिये धन्यवाद देता हूं, उसके साथ ही मैं इस बारे में उनका पूरा सहयोग भी चाहता हूं। हमारी राज्य सरकार की नीति है, ज्यादा से ज्यादा स्टेट एन्टरप्राइजेज खोले जायें। लेकिन जब यह इरादा लेकर चलते हैं, वहां इन्वेस्टमेंट का सवाल आता है, इसके अभाव में हम जितने तेजी से चलना चाहते हैं उतना चल नहीं पाते।

हिन्दुस्तान में राजस्थान ही पहली स्टेट है जिसमें स्टेट एन्टरप्राइज एक जुदा डिपार्ट-मेंट है। इसके लिए कमिश्नर मुकर्रर किया है, इससे वह अनुभव हो सकता है इस बारे

Page No. 85

(श्री मथुरादास माथुर)
में स्टेट का क्या दृष्टिकोण है। यह हम भी मानकर चलते है कि केवल डिपार्टमेन्ट खोल देने से स्टेट एन्टरप्राइज नहीं बढ़ जायेंगे, लेकिन इससे हमारी जो इस ओर भावना है उसका आभास मिल जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानता हूं स्टेट एन्टरप्राइज के अन्दर जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा, करोड़ों रुपयों का इन्वेस्टमेन्ट होता है। मैं आपको बताऊं, हमारे पास स्टेट एन्टरप्राइज में ये हैं, गंगानगर शुगर मिल, रोडवेज, सोडियम सल्फेट, ग्लास फैक्ट्री, साल्ट और एक पलाना खान है। इसके अन्दर जो कुछ इन्वेस्टमेन्ट हुआ है डिबेन्चर और इक्वीटी शेयर्स हैं, वे सब मिलाकर करीब तीन साढ़े तीन करोड़ रुपये का हैं, इससे ज्यादा नहीं है। बहुत से इन्वेस्ट्मेन्ट्स का अभी इवेल्यूएशन मुकर्रर नहीं हुआ है।

गंगानगर शुगर मिल में	३३ लाख का
रोडवेज में	२ करोड़ का
सोडियम सल्फेट	४८ लाख का
ग्लास फैक्ट्री में	६१ लाख का
ऑर्डिनरी साल्ट	५ लाख का

इस प्रकार से हमारा रुपया इन एन्टरप्राइजेज में लगा हुआ है। जो करीब साढ़े तीन करोड़ के होता है।

इसके मुकाबले गंगानगर शुगर फैक्ट्री को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये हुए आठ-नौ साल हुए हैं, इन वर्षों के अन्दर गंगानगर शुगर फैक्ट्री ने ३१ लाख का प्रोफिट दिया है।

रोडवेज से ८२ लाख रुपये का प्रोफिट हुआ है।

सोडियम सल्फेट जो इसी साल से बनना शुरू हुआ है, उसने भी नेट प्रोफिट ३ लाख का दिया है; अपना खर्चा निकाल कर।

ग्लास फैक्ट्री को एक साल की रिपोर्ट आयी है यह घाटे में चल रही है।

साल्ट में भी ६ लाख से ८ लाख मिल जाता है।

मैं यह तसवीर इसलिए रख रहा हूं, स्टेट एन्टरप्राइज डिपार्टमेन्ट घाटे में नहीं चल रहा है। अगर घाटे में चलता है, तो इसे स्टेट एन्टरप्राइज नहीं कहा जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : इस साल का प्रोफिट बतलाइये।

श्री मथुरादास माथुर : तो मैं निवेदन कर रहा था........

श्री भैरोंसिंह : आप इस साल का बतलाइये प्रोफिट।

श्री मथुरादास माथुर : मैं इस साल पर भी आ जाऊंगा। कोई चीज आप से छिपाकर रखने की आदत नहीं है। पर यह फिजा बनाना कि करोड़ों रुपयों का इन्वेस्टमेन्ट कर दिया, पर उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है, घाटा खाया जा रहा है, यह सही नहीं है। जितना इन्वेस्टमेन्ट किया है, उसका अच्छा रिटर्न हमें मिल रहा है; हताश होने की जरूरत नहीं है। यह हो सकता है, किसी एक में एक साल घाटा हो जावे तो मैं एक एक स्टेट एन्टरप्राइज के बारे में निवेदन करूंगा।

सबसे पहले मैं सोडियम सल्फेट की बात निवेदन कर दूं। जो प्रोजेक्ट बनाया था

(श्री मथुरादास माथुर)

इसका टार्गेट बीस टन पर डे (per day) का था। किन्हीं टैक्निकल कठिनाइयों और क्लाइमेट की कठिनाइयों के कारण वह पूरा नहीं हो सका। साल भर हमारा वेस्ट हुआ। ३८ लाख का हमारा ब्याज का नुकसान हुआ। यह सही है। पर अब उसमें चेन्जेज करवाकर प्रोडक्शन को चालू कराया है। २१ सौ टन सोडियम सल्फेट अब तक पैदा हुआ है। ४०१ रुपया प्रति टन के हिसाब से हमने उसको सैल किया है। आज हमारा प्रति दिन का उत्पादन १५-सोलह टन आ रहा है। अधिक निकलेगा नहीं, क्योंकि जर्मनी की और हमारे यहां की क्लाइमेट में अन्तर है। रेफ्रीजरेशन में इसके कारण डिफेक्ट रहेगा। पर किसी दिन सत्तरह टन भी निकलता है, कुल मिलाकर १५–१६ टन का एवरेज है। इसमें भी भाखरा का पॉवर का ब्रेकेज कभी कभी हो जाता है, वोल्टेज लो हो जाता है. लाइन कभी चली जाती है रिपेयरिंग की वजह से, तो इसलिये हमें टर्बाइन का भी प्रबन्ध रखना पड़ता है। फिर भी हमारा किसी दिन प्रोडक्शन १८ टन तक भी चला जाता है। इन्हीजोनस जो है उसको भी हमने बेचा है। वह भी १५० टन बेकार मिला है, ऐसी स्थिति में सोडियम सल्फेट के इस प्लान्ट में ३८ लाख की लागत के बाद ८॥ लाख रुपया हमें मिल चुका है। इसमें से नेट ३॥ लाख का प्रोफिट हमें हो जावेगा। यह आपके सामने मैंने तस्वीर रक्खी है। आज बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज वाले आते हैं हमारे पास इस प्लान्ट को चालू देखकर और कहते हैं इसको एक्सपेण्ड करा लो, चालीस टन रोज की केपेसिटी करा लो, क्योंकि उनको इसमें फायदा नजर आता है।

श्री भैरोंसिंह : वेस्ट जर्मनी की फर्म के साथ आपका कोलेबोरेशन था और उसके एग्रीमेन्ट के अनुसार इसका इन्स्टालेशन उस फर्म ने यहां किया। इसमें एक साल वेस्ट गया। इस एक साल के वेस्ट जाने के कारण जो प्रोडक्शन का, ब्याज का लोस गया, उसे कौन भुगतेगा? क्या सरकार ने निर्णय किया है इस बारे में कोई कि वे लॉसेज कैसे मीट किये जावें?

श्री मथुरादास माथुर : जहां तक प्रोडक्शन में डिले हुई, उस साल का प्रोडक्शन नहीं मिला, यह नेगोशियेबल है। हमने नोटिस दे रखा है। हम कोरस्पोन्डेन्स में हैं। पर १५ टन रोज का प्रोडक्शन करने लायक उस प्लान्ट को बनाने में जो एडीशन और ऑल्टरेशन्स करने पड़े हैं या पड़ेंगे वह सब कम्पनी की कोस्ट पर हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : ऑल्टरेशन किया है, इस कारण डिफरेन्ट पार्ट्स लगभग ५० परसेन्ट पार्ट्स स्पेयर हो गये हैं या आउट ऑफ ऑर्डर हो गये हैं उनका लॉस कौन भुगतेगा?

श्री मथुरादास माथुर : ऐसे कोई पार्ट्स नहीं हैं। बारीक कैपलेरीज हो रहे हैं, टर्बाइन खराब हो गया है, तो उसको ठीक कर लिया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : रिमोडल किया गया है तो पार्ट्स जो पहले लगे थे, वे स्पेयर हुए हैं। मुझे जानकारी है, लिस्ट है मेरे पास।

श्री मथुरादास माथुर : यह तो रेफ्रीजरेशन, कूलिंग प्लान्ट है। ऐसा कोई रिमोडल होने जैसी बात नहीं है।

Page No. 87

श्री कृष्णकुमार गोयल : ५० परसेन्ट पार्ट्स स्पेयर हुए हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आपका मतलब क्या यह है कि कोई पुर्जो का एक जगह ढिगला हो गया है ? आप क्या यह कहते हैं कि कोई नली बदलनी है तो वे वापिस ले जावेंगे या उसमें कोई फोरिन एक्सचेन्ज का सवाल पैदा होता है। ऐसे पार्ट्स नहीं हैं जिनमें फोरिन एक्सचेन्ज इन्वॉल्व होते हों। उनकी कोई खास वेल्यू नहीं है। इस तरह की कोई नली टूट गई, गिर गई तो वे पड़ी हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि आपका कॉरस्पोन्डेन्स चल रहा है। तो क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि आपने कितना क्लेम अपना किया है ? प्रोडक्शन जिस तारीख से चालू होना चाहिये था, नहीं होने से सरकार को इतना लॉस हुआ और दूसरा इतना लॉस हुआ, क्या इस सारे लॉस को आपने उस पार्टी से क्लेम किया ? इस नाते कितना क्लेम आपने किया ?

श्री मथुरादास माथुर : रुपये आने पाई में क्लेम भेजने से आपका मतलब हो तो वह हमने नहीं भेजा है। पर यह खत हमने लिखा है कि यह जो हमारे लॉसेज हो रहे हैं और उसमें भी हमारे स्टाफ का खर्चा जो पड़ा है, उसके आप जवाबदार होंगे। आप इसे बीस टन प्रति दिन की कैपेसिटी पर लाकर रखें। इसमें जो खर्चा होगा, वह आप देंगे। लॉ डिपार्टमेंट से इस तरह की बात करके, उसकी राय लेकर हमने चिट्ठी जर्मनी को भेजी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ६१ से ६४ के बीच में प्रोफिट २० लाख का होता, आपने २० लाख क्यों नहीं क्लेम किया ?

श्री मथुरादास माथुर : यह भी इश्यू होगा। चूंकि रुपया हमने एडवान्स कर दिया था, कमीशन के मार्फत हमारी चिट्ठी जाती है, और चूंकि प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ था तो इसलिये हमने इसे प्रेस नहीं किया कि प्रोडक्शन तो पहले १८-२० टन का होने मिल जावे, अब प्रोडक्शन ठीक हो गया है तो हम क्लेम उठावेंगे।

श्री भैरोंसिंह : हमें आप यह बता दीजिये कि इस साल में इतना प्रोडक्शन होना चाहिये था वह नहीं हुआ, तो उससे होने वाले लॉस का आप क्लेम करने वाले हैं कि नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : हम तो क्लेम करेंगे केटेगोरकली। मिले यह तो बहुत अच्छा है।

श्री भैरोंसिंह : मिले यह तो बहुत अच्छा, इसमें क्या बात है ? मुझे खुश करने के लिये क्लेम करेंगे क्या ? आपने अभी तं नहीं किया ?

श्री मथुरादास माथुर : रुपया, आना, पाई में तं नहीं किया ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्यों नहीं किया ? कॉमर्शियल बेसिस पर कर सकते हैं, तो करना चाहिये था।

श्री मथुरादास माथुर : हमने पहले यह चाहा कि एक बार प्रोडक्शन किसी तरह चालू हो जावे। प्रोडक्शन पहले चालू हो जावे तो रुपया, आना, पाई में भी क्लेम रखेंगे। पर क्लेम हमारा है, यह हमने पहले लिख दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्लेम आपका टाइम बार हो जावेगा ।

श्री मथुरादास माथुर : नहीं होगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्यों नहीं होगा ? गर्दन हिला देने से काम थोड़े ही चलेगा ।

क्लेम आप पुट-अप नहीं करेंगे प्रोपर वे में तो वह वेवर हो जावेगा, खत्म हो जावेगा, खाली लेटर लिख देने से काम नहीं चलेगा ।

श्री मथुरादास माथुर : वेवर नहीं होगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हो जावेगा, कैसे नहीं होगा ।

श्री मथुरादास माथुर : वेवर तब होगा जब हम अपना क्लेम नहीं रखें । हमने क्लेम रख दिया, लॉसेज के लिये, एडीशन और ऑल्टरेशन के लिये, वे जिम्मेदार हैं । यह हमने लिख दिया E और तभी तो वहां से इन्जीनियर आये, दौड़कर और अब काम ठीक तरह से चलना शुरू हो गया है । अब अगला पोइन्ट उठाया जावेगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: वह कुछ नहीं; You should have put up your claim in business like manner, which you did not do.

श्री मथुरादास माथुर: हमने किया है ।

दूसरा सवाल है ग्लास फैक्ट्री का । इसमें ६।। लाख का इन्वेस्टमेन्ट है । इसमें एक फर्नेस लेकर प्रोडक्शन शुरू किया है । उसका इतिहास आप जानते हैं । यह पहले प्राइवेट एन्टरप्राइज था फिर स्टेट ने लिया । इस लिये इसके लॉसेज को कवर करना था ।

इसके अन्दर भी एक टैक्नीकल डाइरेक्टर, जिनका आपने सवाल पूछा था वे थे, उनको टैक्नीकल डाइरेक्टर बनाकर वह शेयर होल्डर बने इस कम्पनी के, क्योंकि उनके पास एक जीना फैक्ट्री ग्लास की है जर्मनी के अन्दर जो कि दुनियां मे इस तरह के सामान बनाने के लिए सबसे अधिक मशहूर है, इस कम्पनी के अन्दर उस फैक्ट्री का टैक्नीकल केलोबरेशन था और वह था श्री किशनजी अग्रवाल के साथ । वह टैक्नीकल केलोबरेशन का ही परिणाम था कि उनको टैक्नीकल डाइरेक्टर बना कर काम शुरू करा दिया । फर्नेस एक बन गयी और प्रोडक्शन थोड़ा बहुत शुरू हुआ । फिर मालूम पड़ा कि वह श्री किशनजी अग्रवाल जिनको टैक्नीकल डाइरेक्टर बनाकर वहां पर रखा हुआ था इसलिए कि उनके पास जीना फैक्ट्री का केलो-बरेशन था, वह न तो कोई टैक्नीकल आदमी है और जो कुछ उनके पास एग्रीमेन्ट था जीना ग्लास फैक्ट्री को हमने उसके लिए लिखा तो उन्होंने लिख दिया कि वह एग्रीमेन्ट हम उनके साथ निभाने के लिए तैयार नहीं हैं । तो इस पर उनको टैक्नीकल डाइरेक्टर के पद से हटाया गया । फिर चूंकि हमारी गवर्नमेंट के शेयर्स ज्यादा थे, तो हमारे जो विभाग के डाइरेक्टर हैं उन्होंने काम लेना शुरू किया । फिर इसके अलावा गलतफहमी है, कि हमने एक करोड़ रुपये के ऑर्डर दे दिये, तो मैं इस गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं कि हमने कोई एक करोड़ रुपये के ऑर्डर्स नहीं दिए हैं; मैं आपसे निवेदन करूं कि हमारा कोई एग्रीमेन्ट भी नहीं हुआ । उसका एग्रीमेंट था जीना ग्लास फैक्टरी से तो हमने फिर

(श्री मथुरादास माथुर)

जीना ग्लास फैक्टरी, जर्मनी को लिखा कि वह एग्रीमेंट जो कि टेक्नीकल कोलोबरेशन का है उसका क्या स्टेट गवर्नमेन्ट के साथ में वहां की जीना ग्लास फैक्टरी को और जर्मन गवर्नमेन्ट को लिखा कि हम तैयार हैं, तो मैं इत्तफाक से न्यूयार्क से बर्लिन जा रहा था, उस समय जर्मनी में रुका तो उसमें बातचीत की और वह उसके लिए एग्री हो गए। उसके बाद में उन्होंने उसके लिए एक ड्राफ्ट एग्रीमेन्ट भी भेजा और वह लॉ डिपार्टमेन्ट में एग्जामिन हो रहा था तो जीना ग्लास फैक्टरी का हमारे पास पत्र आया, कि वह टेक्नीकल कोलोबरेशन करने के लिए हमारे साथ तैयार नहीं है और वह मामला उन्होंने ब्रेक कर दिया और मामला वहीं ड्राप हो गया। फिर उनके एक मिस्टर फिशर आये थे। उनसे हमारी बातें हुई तो हमने उनसे कहा कि आखिर एक गवर्नमेन्ट के साथ एग्रीमेन्ट हो रहा था तो उसको ड्राप क्यों कर दिया, तो उन्होंने कहा कि कोई टेक्नीकल डिफिकल्टी आ गई होगी।

अब आपको यह सुनकर खुशी होगी कि हम वहां पर इस समय हाईटेक फैक्टरी में २३२ टाइप के लेबोरेट्री के एपरेटस बनाते हैं और वह ७० हजार के मूल्य के बनाते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि जब तक १॥ लाख रुपये के मूल्य के नहीं बनेंगे तब तक इसकी इकोनामिक कन्डीशन ठीक नहीं होगी, और तब तक लोस रहेगा। इसलिए एक भट्टी और लगाने का विचार किया है। उसके लिए फाइनेन्स को लिखा है और फाइनेन्स ने इसके लिए हां कर दिया है। एक भट्टी और लग जायेगी और फस्ट ईयर के अन्दर यह सब सरकमस्टान्सेज ऐसी थी कि यह सब हुआ। फिर यह कहा गया कि ऑडिट रिपोर्ट के अन्दर १२ हजार का सामान टूट गया क्योंकि कोई स्टोव वगैरह नहीं बन पाये थे तो मैं आपको बताऊं कि आज के दिन हम ऑल इन्डिया कम्पीटीशन के अन्दर जाते हैं और हमारा माल बहुत अच्छा बनने लगा है। पहले जो लेबर थी, उसको भी आरगेनाइज कर दिया है और दूसरी भट्टी बनने के बाद और अब तक ग्लास टेक्नोलाजिस्ट नहीं थे, वह भी अब आ गये हैं तो उसका अब प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल के अन्दर जब यह भट्टी तैयार हो जायेगी, तो हम नुकसान में नहीं होंगे.......

श्री भैरोंसिंह : इस समय टेक्नीकल डाइरेक्टर कौन है ?

श्री मथुरादास माथुर : अब रिक्रूट हुए हैं पब्लिक सर्विस कमिशन के मार्फत। नाम तो मुझे याद नहीं है। अभि दो-तीन महीने ही हुए हैं। मैं पूछ कर बता दूंगा। But he is a trained Glass Technologist.

श्री भैरोंसिंह : जिस प्रकार का मैनुफक्चरिंग आप कर रहे हैं उसके लिए क्वालीफाइड हैं क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : हां, वे बनारस से बी० ई० (ग्लास टेकनोलाजी) हैं और जो क्वालीफिकेशन प्रेस्क्राइब की थी, उसके अनुसार ही लिए गए हैं। हमारा माल तो बहुत सीधा है। हम तो बीकर्स, ब्युरेट्स, डेसीसेटर्स वगैरह जो मैट्रिक के लड़कों के लेबोरेट्री में काम आने वाली चीजें हैं, वह बनाते हैं, उसमें कोई दाग नहीं रह जाये, गैस वैक्यूम नहीं रह जाये; तो वे बहुत हाई टेक्नीकल आदमी हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने मूलतः तय किया था, कि हम थर्मामीटर और सीरेन्जेज़ बनायेंगे, लेकिन इनके बजाय आप दूसरी ही चीजें बना रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : लेबोरेट्री एपेरेटसेज़ बनायेंगे, फर्स्ट फेज में, और दूसरे फेज़ में थर्मामीटर और सिरेन्जेज़ भी बनायेंगे। तो फ़स्ट फेज़ तो शुरू कर दिया। अब जो हम जीना ग्लास फैक्ट्री जर्मनी से जो टेक्नीकल कोलोबरेशन कर रहे थे, वह थर्मामीटर, बैरोमीटर, सीरेन्जेज़ और कट ग्लासेज़ वगैरह के लिये कर रहे थे, क्योंकि यह चीजें बनाने के लिए मशीनें कोई इन्डिया में तो बनती नहीं हैं। तो ऐसी सूरत में सेकिण्ड फेज़ बाकी है। फर्स्ट फेज में भी एक भट्टी हम और बनायेंगे, जैसा कि अभी मैंने पहले कहा है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप कृपा करके यह भी बतायेंगे कि जो टेक्नीकल आदमी आपने एम्पलाय किया है, उसको प्रीवियस एक्सपीयरेन्स है या नहीं; इसको भी देखा है आपने ? क्या आप उसको १८०० रुपये महावार पे कर रहे हैं ? पहले ये महाशय जहां फिलिप्स में नौकर थे वहां उनको ६०० रुपये मिलते थे और किस कारण से एप्लीकेशन मंगाई थी, क्वालीफिकेशन प्रेस्क्राइब की थी या किस तरह से रिक्रूट किया ? एक आदमी को निकाल कर इसकी प्रीवियस स्टेज क्या थी प्राइवेट के अन्दर और उसके बाद में १६०० और २०० बंगले के १८०० रुपये उसको पे कर रहे हैं ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसका नाम क्या है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : नाम का तो मुझे मालूम नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर ठीक है, आपको भी मालूम नहीं और हमें भी मालूम नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : नाम शायद सुरजीतसिंह है।

श्री मथुरादास माथुर : हमारे डिपार्टमेंट के टेक्नीकल डाइरेक्टर पूरनसिंह हैं। और जो क्वालीफाइड टैक्नोलोजिस्ट हैं उनका नाम शायद छत्री है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : छत्री हो या खत्री; पर नाम क्या है वही तो मेटीरियल बात है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप बतायें कि उसको पे क्या मिल रही है ?

श्री भैरोंसिंह : आपको मालूम हो तो इनकी कोई क्वालीफिकेशन हो तो बता दें ?

श्री मथुरादास माथुर : यह बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स और टैक्नीकल एक्सपर्ट्स ने बैठक कर तय किया है। अब कौन आदमी किस क्वालिफिकेशन का है, यह तो आप प्रश्न पूछ लें, मैं जवाब दे दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको नाम मालूम है ?

श्री मथुरादास माथुर : मुझे तो मालूम नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप को यह तो मालूम नहीं है, लेकिन डाइरेक्टर्स के ऊपर देखभाल नहीं है कि जो कम्पनी ६ लाख का

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

नुकसान उठा रही है और पहले कई दफा आपके सामने यह बात कह दी और ६७ हजार का माल बनता है ३॥ लाख कर के, आपने दो बार उधार लिया है और उसके बाद में आप १८०० का आदमी रखते हैं जिसको कि ६०० रुपये मिलते थे, इसकी जांच नहीं करा सकते हैं ? आप कहते हैं कि डाइरेक्टर का काम है, नुकसान उठाते रहें और तनख्वाह देते रहें । हम एक भट्टी लगायेंगे तो नुकसान कम हो जायेगा। आप ३॥ लाख रुपया दो दफा हमसे मांग चुके हैं और शायद १ लाख रुपया और अभी अभी ले लिया है ।

श्री मथुरादास माथुर : लिया तो कुल ६॥ लाख है, उससे ज्यादा नहीं लिया है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपकी बैंक में ८ लाख की गारंटी है । जब घाटा निकलेगा तब मैं बताऊंगा ।

श्री मथुरादास माथुर : तो बैंक में गारन्टी होती है तो हमारा सामान भी तो पड़ा रहता है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सब मशीनों की डेप्रीसियेशन की वेल्यू भी तो बताइये।

श्री मथुरादास माथुर : वहां मशीनें लगी नहीं होती हैं कोई लम्बी चौड़ी । वह तो भट्टी होती है, इंटे गिर जाती तो भट्टी दूसरी लगानी पड़ती है । मैं खुद वहां जाकर आया हूं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उसकी रिपोर्ट दे दें कि कोई डेप्रिसियेशन है या एप्रिसियेशन हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : वह तो हाउस को अधिकार है लेने का मैं आपको बताऊं कि उनको तनख्वाह १४००) रु० मिलती है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अपोइन्टमेंट से पहले कितनी मिलती थी ?

श्री मथुरादास माथुर : वह तो मुझे इतना मालूम है कि उसे अब १४००) रु० मिलते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्वालीफिकेशन क्या है ?

श्री मथुरादास माथुर : बी० ई० इन ग्लास टेक्नोलाजी है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप पूरी क्वालीफिकेशन बताइये ।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने अभी बताया कि टैक्नीकल कोलेबोरेशन जर्मनी से करने के लिये मंत्री महोदय वहां बातचीत करने के लिए गए थे । मैं जानना चाहूंगा कि क्या टैक्नीकल कोलेबोरेशन करने के बारे में केबीनेट में राय ली थी कि माननीय सदस्य वहां जायें और बात करें । आपने कहा कि जीना फैक्टरी दुनियां में एक ही फैक्टरी है, लेकिन मैं जानकारी के लिये बताना चाहूंगा कि जीना से बढ़िया जेकोस्लोवाकिया की है । क्या आपने कभी कोशिश की कि उनसे बात करें या सिर्फ श्री किशन जी को राज़ी करने के लिए उनसे बात-चीत करने के लिए गये ?

श्री मथुरादास माथुर : न तो अग्रवाल टैक्निकल डाईरेक्टर हैं और न कोई कोलेबोरेशन हुआ है । खत्म हुआ किस्सा ।

श्री मोतीलाल चौधरी : इसके बाद क्या हुआ ?

श्री मथुरादास माथुर : हमने रुमानिया, जैकोस्लोवेकिया और हंगेरी से कॉंटेक्ट किया है और इन तीनों कंट्रीज़ के एम्बेसेडर्स और इनके ट्रेड एजेन्टस से भी बात की है, लेकिन अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

श्री मोतीलाल चौधरी : यह जो जीना कम्पनी से आपने बात करने का प्रस्ताव किया तो उसके लिए भी क्या टेक्नीकली यह निर्णय लिया गया था कि वर्ल्ड में बेस्ट ग्लास बनाने वाली यही कम्पनी है या और भी कोई इंडस्ट्री इसका काम करती है । आपने बीना कम्पनी को ही बेस्ट कैसे माना जब कि जापान इसके लिए बेस्ट है ।

श्री मथुरादास माथुर : डॉ० हिश, जो टेक्निकल एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के प्लानिंग कमीशन में आगे से हम उनकी सलाह से काम करेंगे । जीना कम्पनी से न तो कोई हमारा एग्रीमेंट हुआ है और न आगे ही कोई बात की जा रही है । पहले जीना कम्पनी सामने थी तो इसका ही नाम आगया अब को कौन कह सकता है कि दुनिया में इसके अलावा और कोई कम्पनी नहीं है । और भी कम्पनीज हो सकती हैं । लेकिन इसकी रेपुटेशन भी अच्छी थी । न तो मैं जर्मनी ही इस काम के लिये गया और न कोई राज का पैसा ही इसके लिये खर्च किया है । यह तो मैं वापिस लोट रहा था तो रास्ते में मैंने उनसे भी बात की थी । उन्होंने एग्रीमेंट का ड्राफ्ट भेज दिया उसे हमने एग्जामिन किया । जब उसके लिए मना कर दिया तो बात समाप्त होगई ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): अभी फैक्ट्री में जो सामान बनता है उसकी क्वालिटी कैसी है ?

श्री मथुरादास माथुर : अब बहनजी, मैं अपने मुंह से तो उसकी क्या तारीफ करूं; लेकिन मैं यह मानता हूं कि अभी जो वहां से ग्लास निकलता है वह बेस्ट क्वालिटी का ग्लास है । अगर आप इसको देखना चाहें तो सदन के माननीय सदस्य, पांच-सात वहां चल कर देख लें....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो माननीय सदस्य को ही दिखादें ।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्षजी, अब ग्लास की तरफ से शूगर पर आता हूं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने जो कहा कि टेक्नोलोजिस्ट का सिलेक्शन पी. एस. सी. से करवाया, तो क्या पब्लिक इण्टर प्राइजेज की पोस्ट्स का सिलेक्शन भी पी. एस. सी. के थ्रू होता ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने अपनी गल्ती को ठीक कर दिया कि उनका सिलेक्शन बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की बैठक में किया गया । सिलेक्शन करने से पहले पोस्ट एडवरटाइज की गई, एप्लीकेशन्स इन्वाइट की गई और उसके बाद ही सिलेक्शन किया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में कोई ग्लास टेक्नोलोजिस्ट भी थे क्या, जो यह बता सकें कि फलां ग्लास टेक्नोलोजी में एक्सपर्ट है ? आपने सिलेक्शन करते समय प्लानिंग कमीशन के ग्लास टेक्नोलोजिस्ट को क्यों नहीं बुलाया ?

Page No. 93

श्री मथुरादास माथुर : यह तो मैं नहीं कह सकता कि उसमें ग्लास टैक्नोलोजिस्ट थे या नहीं। आप इसका क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। लेकिन जो फिलिप्स ग्लास कम्पनी है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने जब एप्लीकेशन्स इन्वाइट की, तो यह तो देखा होगा कि इसने बी. एस. सी. टैक्नोलोजी कौन से ईयर में की या वहां से निकलते ही सोलह सौ रुपये में आकर बैठ गया।

श्री मथुरादास माथुर : मुझ से यह सवाल आप प्रश्न लिख कर पूछिए, फिर मैं आपको सारी जन्मपत्री दे दूंगा। मैं तो हाई-टैक के बारे में जानता हूं। मुझे मालूम नहीं कि वहां कौन काम करता है और उसकी क्या २ क्वालिफिकेशन्स हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप कह रहे हैं कि हम सवाल पूछें। इसके बारे में हम तीन दफा सवाल कर चुके हैं। यह हमेशा घाटे में चल रही है और घाटे में ही चलती जा रही है और आप जर्मनी, जैकोस्लोवाकिया जीना फीना कह कर इसको टालते जा रहे हैं। इसमें हमारा पैसा लग रहा है, वह पैसा बर्बाद होता जा रहा है, कम्पनी घाटे में चल रही है और आप इसको समझ नहीं रहे हैं। सवाल इस बात का है कि इतने प्रोफ्यूज़ली ये डाइरैक्टर्स पैसा बर्बाद कर रहे हैं और एक रॉ हैंड को, जिसने तीन दिन तक किसी कारखाने में काम नहीं किया, एक्सपर्ट बन कर सोलह सौ रुपये में आकर बैठ गया और वह भी उस हालत में जब कि कम्पनी में घाटा लग रहा है; कोई कमाई नहीं है; फिर भी इतना खर्चा किया जा रहा है। जब सदन इस बारे में जानना चाहता है तो आप कहते हैं कि प्रश्न पूछिए। मैं तैयार नहीं हूं तो आपको तैयार होकर आना चाहिए था।

श्री मथुरादास माथुर : एक एक आदमी की तनख्वाह और क्वालिफिकेशन के बारे में तैयार होकर आऊं, यह तो सम्भव नहीं है। आप प्रश्न पूछिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। जो फैक्ट्री की हालत है उसके बारे में बताने को मैं तैयार हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये तो साफ कहते नहीं हैं, मैं आपसे साफ कहता हूं। ये जानना चाहते हैं कि जो ग्लास टैक्नोलोजिस्ट है वह कौन है, यह आप बतायें ताकि जनता को मालूम हो जाय कि किसको ग्लास टैक्नोलोजिस्ट रखा है। मैं बताता हूं वह कौन है। वह श्री प्रतिभारानी का भाई है। मैं साफ कहता हूं और ये साफ कहते नहीं हैं, घुल-घुल कर रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : कौन क्या है, मुझे पता नहीं है। कोई किसी का भाई तो होता ही है। हमारा तो नौकर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और दुनियां में नौकर नहीं मिलते थे ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपके तो सभी नौकर हैं।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे माननीय सदस्य स्टेट एंटरप्राईजेज़ के सम्बन्ध में इतनी अधिक दिलचस्पी लेते हैं, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

अब मैं शूगर फैक्ट्री के बारे में निवेदन करूंगा........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ब्रेकेज के बारे में बता दीजिए।

श्री मथुरादास माथुर : यह तो १२,५००) रु० का है, ऑडिट रिपोर्ट में दर्ज है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैंने यह कल भी कहा था कि आप तो कहते हैं कि १२,५००) रु० का ब्रेकेज हुआ है। लेकिन आपकी स्टेट इन्टरप्राईजेज के कमिश्नर या डायरेक्टर जो भी उन्होंने अभी एक लैटर लिखा है श्री कृष्ण अग्रवाल को, उस लैटर में उन्होंने लिखा है कि एक लाख का ब्रेकेज हुआ है। वे एक्चुअल फिगर्स तो अभी मेरे पास नहीं हैं। लेकिन जो लैटर लिखा है वह उसी टाइम के लिए लिखा है। इन दोनों में अब किसे सही समझें ?

श्री मथुरादास माथुर : ऑडिट रिपोर्ट को ही सही समझा जाएगा। ऑडिटर्स ने ऑडिट किया है और अपनी ऑडिट रिपोर्ट दी है, तो उसको ही सही मानकर चलेंगे।

अब जहां तक शूगर फैक्ट्री का सवाल है, इस शूगर फैक्ट्री के पूरे इतिहास में जाने की जरूरत तो नहीं है। यह शूगर फैक्ट्री ६४ और ६५ के अन्दर, ६५-६६ का तो अभी सवाल पैदा नहीं होता, ६४-६५ के बारे में मैं निवेदन करूंगा इस साल यह शूगर फैक्ट्री करीब करीब चार महीने चलेगी। आज भी फैक्ट्री चल रही है, गन्ना क्रश कर रही है और उम्मीद है कि फैक्ट्री प्रोफिट में रहेगी। ६४-६५ के अन्दर कुल बोनस तीन लाख का देने के बाद और ४ लाख ८० हजार रुपये इन्कम टैक्स के बाद भी ५,२५,४८४) रुपये का प्रोफिट रहेगा.......

श्री भैरोंसिंह : इसमें आपका एक्साइज का पार्ट भी शामिल है या शूगर के बारे में ही कह रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : यह तो दोनों की कम्पोनेंट हैं। शूगर फैक्ट्री और डिस्टिलरी, दोनों एक में ही हैं। एक ओर हम शूगर पैदा करते हैं और दूसरी ओर शूगर फैक्ट्री में जो हमारे पास लिकर होता है, जो स्प्रिट होती है, उसके अन्दर शराब बनाकर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है उस पर एक्साइज ड्यूटी और दूसरे टैक्स देने के बाद उसको बेचते हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह जो आपने प्रोफिट बताया है, तो यह आपकी डिस्टिलरी का है या शूगर फैक्ट्री का ? अलग अलग बताइए।

श्री मथुरादास माथुर : इसमें कोई संदेह नहीं है कि शूगर के अन्दर घाटा है, यह बात तो सही है। लेकिन शूगर और डिस्टिलरी दोनों कम्पोजिट हैं, दोनों को साथ लेकर ही आपको चलना होगा........

श्री भैरोंसिंह : इसमें आपने क्या किया, शराब की कीमत को बढ़ा दिया, एक रुपये की शराब का दस रुपया वसूल करें तो अपने आप ही फायदा होगा। इसमें आपने क्या किया ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन कर रहा हूं कि यहां पांच डिस्टिलरीज हैं जो डिस्टिल करती हैं, उसमें लेबर काम करता है, मशीनें काम करती हैं। वहां पर जो शराब बनती है तो उसमें जब स्प्रिट कम पड़ जाती

(श्री मथुरादास माथुर)
तो वह भी जैसे जैसे कोटा अलॉट होता है वह हमको मिलता है और उससे हम शराब बनाते हैं। ये तो इसका कम्पोनेंट है। इसको हम पीसमील में करके नहीं चल सकते। मैं मानता हूं कि शूगर के अन्दर लोस रहा है, लेकिन इसके भी कारण हैं। पहले तो यह कि पचास दिन तक शूगर फेक्ट्री चली। घग्घर की बाढ़ आ गई जिसमें गन्ना बह गया, फेक्ट्री को पूरा गन्ना नहीं मिला। इसके अलावा यह फेक्ट्री भी कितने साल पुरानी फेक्ट्री है? २५ साल पहले की फेक्ट्री है। इसके अलावा शूगर की रेट्स में भी टाइम टु टाइम काफी चेंज किया गया है जिससे भी हमको काफी नुकसान हुआ है।

यह सारा नुकसान भुगतने के बाद भी इस साल में हमको पांच लाख और कुछ हजार का फायदा हो रहा है। मेरे कहने का मतलब यही है कि शराब को और शूगर को, दोनों को, मिलाकर शूगर फेक्ट्री एडवान्स कर रही है और इससे प्रोफिट मिल रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद भी, हम बराबर डिविडेन्ड दे रहे हैं और अगले साल के मुकाबले हम उम्मीद करते हैं कि इस साल फेक्ट्री १२० दिन तक चलेगी। अभी भी चल रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि शूगर फेक्ट्री इटसेल्फ में भी इस साल प्रोफिट होने की गुंजाइश है।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : शराब का कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या पड़ता है?

श्री मथुरादास माथुर : क्या कहा?

श्री अब्दुलजब्बार : जो आप शराब डिस्टिल करके मेन्युफेक्चर करते हैं तो उसकी पर लीटर क्या कोस्ट आती है और मार्केट में आप किस भाव से सप्लाई करते हैं?

श्री मथुरादास माथुर : यह तो मेरे पास फिगर नहीं है इस वक्त।

श्री अब्दुलजब्बार : जब आप शराब बनाकर मार्केट में बेचते हैं तो एक बोतल की कीमत आपको क्या पड़ती है?

श्री मथुरादास माथुर : शराब की बोतल में तो शराब के अलावा और भी चीजें होती हैं। बोतल है..........

श्री अब्दुलजब्बार : आठ आने की बोतल आती है। आप तो बोतल के कंटेन की कीमत बता दीजिए, ताकि लोगों को मालूम हो जाय कि शराब क्या भाव बनती है और क्या भाव बिकती है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि उसमें अलग–अलग किस्में हैं। गुड़ की कीमत अलग है और डिस्टिलरी से बनती है उसकी कीमत अलग है। आप क्या क्या पूछेंगे यह मैं कैसे बताऊं....

श्री भैरोंसिंह : केसर कस्तूरी का कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन बता दीजिए।

श्री मथुरादास माथुर : यह ट्रेड सिक्रेट है।

माननीय उपाध्यक्ष जी....

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कई दिनों से मैं यह देखता आ रहा हूं। कि सदन के काफी माननीय सदस्यों ने कई बार इस बात की मांग की है कि जितने भी स्टेट एन्टरप्राइजेज हैं और जिनमें हमारा इन्वेस्टमेन्ट है, उन सबकी डायरेक्टर्स रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट सदन को मिलनी चाहिए। जो

(श्री भैरोंसिंह)

भी रिपोर्ट डायरेक्टर्स के पास पेश हो जाय, उसके तुरन्त बाद जो विधान सभा का सेशन प्रारम्भ हो तो उसके अन्दर रखी जाय। इस सम्बन्ध में बार-बार इस सदन में प्रश्न उठाया गया है और चेयर की तरफ से भी बार-बार कहा गया है लेकिन इस समय तक भी सरकार ने स्टेट एन्टरप्राइजेज की ऑडिट रिपोर्ट या डायरेक्टर्स की रिपोर्ट, जिनके अन्दर कि हमारा इन्वेस्टमेंट है, जिनके अन्दर हमारा लाखों रुपया लगा हुआ है उनके डाइरेक्टर्स की या ऑडिट रिपोर्ट आज तक हमारे पास नहीं आई है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि चूंकि सरकार बार-बार कहने पर भी ध्यान नहीं देती है तो चेयर की तरफ से इस बात की रूलिंग देकर इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जानी चाहिए कि जो भी स्टेट एन्टरप्राइजेज के अन्दर हैं और जिनमें हमारा इन्वेस्टमेन्ट है उनके बारे में डायरेक्टर्स की रिपोर्ट या ऑडिट रिपोर्ट जो भी हो उसको इस सदन की मेज पर तुरन्त रखा जायगा जिससे मेम्बर्स उसको अच्छी तरह से स्टडी कर सकें और डिबेट में भाग लेते समय वे अच्छी तरह से अपने विचार व्यक्त कर सकें।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा ख्याल है कि गंगानगर शूगर फैक्ट्री की रिपोर्ट, ६३-६४ की रख चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह : ६४-६५ की रिपोर्ट रख दीजिए।

श्री मथुरादास माथुर : ३० तारीख को उनकी मीटिंग होने वाली है। मीटिंग होने के बाद रिपोर्ट रख दी जावेगी।

श्री भैरोंसिंह : एक और अर्ज कर दूं बीच में। मैंने ऑडिट रिपोर्ट्स और डाइरेक्टर्स की रिपोर्ट को देखा है। उसमें एक पैराग्राफ लिखा जाता है कि Other irregularities are reported in a separate note वह सेपरेट नोट इम्पार्टेन्ट होता है। उसमें सारी इर्रेगुलेरिटीज होती हैं। ऑडिटर्स और डाइरेक्टर्स की रिपोर्ट में मोटे मोटे आंकड़े होते हैं कि इतना क्रसिंग सीजन रहा, इतना गन्ना पेला गया, इतना शूगर कन्टेन्ट था, और इतनी बोरियां बनी। वह सब बना बना कर दे दी गई। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव इर्रेग्युलेरिटीज, लेप्सेज, मिसयूज ऑफ फन्ड्स, ये डाइरेक्टर्स की रिपोर्ट में शामिल नहीं करते हैं बल्कि उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। वह रिपोर्ट डाइरेक्टर्स के पास जाती है। हमेशा सदन में बाकी की इस रिपोर्ट को छिपाया जाता है। अभी ६३—६४ की रिपोर्ट जो आपके पास में है उसमें भी दो पेजज को छोड़कर देखें तो इसी में लिखा हुआ है; उसको देखें तो इस तरह के मामले हैं "other irregularities are reported separately वह पेश करें सदन में। उसी में तो हैं घोटाले। उसको आप छिपाकर चलते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : जो रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स पेश करते हैं उसको ही सदन में पेश कर देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : कम्पनी लॉ के अन्दर है उसको आप अच्छी तरह से देखें।

श्री मथुरादास माथुर : अगर आपने जो बात बताई है इसके अन्दर कि क्लेरिफिकेशन ऑफ दी डाइरेक्टर्स ऑन दी रिपोर्ट ऑफ दी ऑडिटर्स, ऑडिटर्स की रिपोर्ट पर जो क्लेरिफिकेशन डाइरेक्टर्स का रिपोर्ट में आता है वही तो खास चीज है।

Page No. 97

श्री भैरोंसिंह : जो बीच में लिखा हुआ है, पन्ना वही है, खास चीज है।

श्री मथुरादास माथुर : बीच के पन्ने में कुछ नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आप देखें।

श्री मथुरादास माथुर : यह दूसरी रिपोर्ट है।

श्री भैरोंसिंह : एक मिनट के लिए इसको आप मुझे दें तो मैं बता दूं। इसमें भी होगा।

श्री मथुरादास माथुर : इसके बीच में क्लेरिफिकेशन ऑफ दी डाइरेक्टर्स है। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपसे सहमत हूं कि रिपोर्ट रखनी चाहिए। हम बराबर रखते आए हैं। ६४–६५ की भी रखेंगे वह ३० तारीख की मीटिंग में पास होने के बाद।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्षजी, बीच वाले कागज के बारे में आप रूलिंग दें। वह है इम्पोर्टेन्ट, बाकी में तो केवल आंकड़े होते हैं। उन आंकड़ों के जाल में फंस भी गये तो मुश्किल है। वह पेश करिये।

श्री मथुरादास माथुर : इसमें बीच के और पहले दूसरे कागज का सवाल नहीं है। जो आप चाहते हैं वह कम्पनी लॉ के अन्दर, चाहें वे सबके सब नहीं होंगे तो भी हम उसके लिए हिदायत कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह : यों तो आपने जो रिपोर्ट पेश की है वह भी डिफेक्टिव है। कम्पनी लॉ के मातहत इस प्रकार के जितने भी सेपेरेट नोट्स हैं वे सबके सब एपेन्डिक्स बनते हैं, और आज तक आपने बनाकर दिये नहीं। इसमें आपने कम्पनी लॉ का वायोलेशन किया है।

श्री मथुरादास माथुर : जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट पेश होती है उसका एक पन्ना भी नहीं फाड़ते हैं और आपके यहां पेश कर देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : कम्पनी लॉ में यह है।

श्री मथुरादास माथुर : कम्पनी लॉ के अन्दर जो रखना है उसको एक्जामिन करा लेंगे और अगर लॉ डिपार्टमेंट कह देगा कि यह चीज आनी चाहिए तो रख देंगे।

अब, माननीय उपाध्यक्षजी, शूगर फैक्ट्री के बाद में यह स्टेट एन्टरप्राइज ...

श्री संतोशचन्द्र अग्रवाल : ४ बज रहे हैं डेढ़ घंटा हो गया है।

श्री मथुरादास माथुर : फिर उसके बाद मैं ग्लास फैक्ट्री का जिक्र कर चुका। शूगर फैक्ट्री और सोडियम सल्फेट का जिक्र कर चुका, और अब रोडवेज पर आता हूं। साल्ट के लिये ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। अब रोडवेज और पलाना, इन दो चीजों पर आ जाता हूं।

पलाना पर इसलिए पहले कह देता हूं कि सूक्ष्म में आप उसको समझ लें। पलाना की क्वेरी का काम चल रहा है। पहले भी चलता था और अभी भी चल रहा है। पलाना के अन्दर ओपन कास्ट माइनिंग की रिपोर्ट हमने १९६१ में बना ली थी। वह रिपोर्ट आ चुकी है। उस रिपोर्ट को हम भारत सरकार के सामने पेश कर चुके हैं, बल्कि प्लानिंग कमीशन के सामने पेश कर चुके

(श्री माथुरादास माथुर)

हैं। इसके साथ-साथ एक रिपोर्ट के जरिये पलाना माइनिंग की डिमाण्ड करते हैं और पलाना पॉवर प्रोजेक्ट पर विचार कर रहे हैं, वर्ना यह कोयला ऐसा है कि इसको माइन करके रखें तो इसमें आग लग जाती है। पॉवर सैक्टर के अन्दर पॉवर हाउस का प्रावधान रखा गया है और माइनिंग सैक्टर के अन्दर माइनिंग था रखा गया है। चूंकि अभी फोर्थ प्लान फाइनेलाइज नहीं हुआ है इसलिए यह प्रोजेक्ट भी फाइनेलाइज नहीं हो पाया है। पहले इसमें दो शिफ्ट्स चलती थीं। और अब एक शिफ्ट चलती है। इसमें अभी जितना कोयला निकलता है वह बेच देते हैं। यह १२–१३ करोड़ का प्रोजेक्ट है। प्लानिंग कमीशन की एप्रूवल के बिना इसको हम एक्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। प्रोजेक्ट रेडी है। एटोमिक पोवर कमीशन ने पानी है, इसकी रिपोर्ट दे दी है। इसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दे दी है। वह भारत सरकार के पास मौजूद है। वह फोर्थ प्लान में इनकोर्पोरेट हो जायगी। इसको हम चलायेंगे, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। पूरी तरह से हम इसकी कोशिश करेंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : एटोमिक पॉवर कमीशन ने जो जांच की वह जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट दे दी है?

श्री मथुरादास माथुर : एटोमिक पॉवर कमीशन ने जांच की है और जांच करने के बाद में यह कहा है कि पर्याप्त पानी है। और जो चार क्यूमेक्स पानी चाहिए, इतना पानी वहां पर है। अभी उनकी रिपोर्ट आने के बाद में दो–चार कूए बोर कर चुके हैं और उनसे काफी संतोष प्राप्त हुआ है। उनका कहना यह है कि पानी काफी है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : नहरों से पानी ले जाने की जरूरत नहीं है थर्मल पॉवर स्टेशन के लिए?

श्री मथुरादास माथुर : नहरों से पानी ले जाने का प्रश्न है वह अलग है, थर्मल पावर स्टेशन के लिए आयेगा, वूलन मिल के लिए आयेगा और लूणकरणसर के लिए भी आयेगा। वहां अन्डरग्राउन्ड पानी बताते हैं कि काफी पानी है, वहां चार क्यूसेक्स अन्डर ग्राउन्ड पानी है, यह अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने लिख कर दे दिया है और एटोमिक पॉवर कमीशन ने लिख कर दे दिया है, भाबा साहब ने भी लिख कर दे दिया था।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : राजस्थान में जो पॉवर का अकाल पड़ रहा है उसको देखते हुए राजस्थान सरकार प्लानिंग कमीशन पर और भारत सरकार पर जोर क्यों नहीं डालती?

श्री मथुरादास माथुर : हम तो बहुत जोर डालते हैं। आप भी साथ चलिये, पॉवर कमीशन पर जोर डालने के लिए। हम अपनी तरफ से काफी जोर डालते हैं। लेकिन अभी फोर्थ फाइव ईयर प्लान फाइनल तो हो। अभी तो वह फोर्थ फाइव ईयर प्लान फाइनल ही नहीं हो रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप दोनों मिलकर जोर डालिए।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रोडवेज के ऊपर निवेदन करना चाहता हूं। क्योंकि रोडवेज सबसे बड़ा सेक्टर है इसलिए सबसे पहले मैं रोडवेज के ऊपर हो, जो लोगों में भावना है कि रोडवेज घाटे में

(श्री मथुरादास माथुर)

चलता है, इस भ्रम को निकाल देना चाहता हूं। रोडवेज के सम्बन्ध में जो आंकड़े रखे गये हैं उनके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रोडवेज में नेट प्रोफिट १९६२–६३ के अन्दर २४ लाख रुपये का हुआ था, १९६३–६४ के अन्दर नेट प्रोफिट २५ लाख रुपये का हुआ था, १९६४–६५ के अन्दर नेट प्रोफिट २५ लाख रुपये का हुआ था और १९६५–६६ में नेट प्रोफिट घट कर सात लाख रुपये के करीब रह जाती है। इस नेट प्रोफिट में जो कमी आई है इसका कारण यह है, कुछ तो जब यह कोर्पोरेशन नहीं बना था उस वक्त यह एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट था तब यह इन्कम टैक्स से बरी था। इसके अलावा डेप्रिसियेशन अकाउन्ट और कॉमर्शियल अकाउन्ट्स नहीं रखे जाते थे। उसके बाद इन बाकी के वर्षों में, जब से यह कार्पोरेशन बना, आठ नौ फैक्टर्स, जो मैं अभी अर्ज कर रहा हूं, इन कारणों में और ऐड हो गये "Increase in D. A. by 15 rupees to all the staff, including workers" यह एक फैक्टर ऐड हुआ।

दूसरा "Grant of City Compensatory allowance.

Grant of House Rent Allowance to all the workers at the rate of Rs. 10|- per month.

Rise in minimum wages from Rs. 45 to Rs. 60 as the Minimum Wages Act has been applied to the transport industry.

Increase in price of supplies due to payment of sales tax at 10% instead of 2%.

Increase in diesel cost by five paise per litre, etc."

ये नौ फैक्टर्स और ऐड हो गये। यह फैक्टर्स कम्पोनेन्ट हैं। मैं नहीं कहता कि इन्हीं नौ फैक्टर ने नेट प्राफिट को कम करने में पार्ट प्ले किया है; लेकिन इन्होंने काफी पार्ट प्ले किया है। इसके अलावा हमने जो फेअर्स १९५८ में मुकर्रर किये थे तब से आज १९६६ हो गया है लेकिन वही फेअर्स हैं, Fares remaining the same ये कोम्पोनेन्ट्स ऐड होने की वजह से प्रोफिट अपने आप कम हो जायगा। दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, आपके फीलिंग्ज के साथ मैं भी शेयर करता हूं.......

(४. म. प.)

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू): जो गाड़ियां खरीदी गई थीं उनकी रकम चुक गई क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : इसके लिये डेप्रिसियेशन अमाउन्ट होता है, सिंकिंग फंड और डेप्रिसियेशन फंड कोर्पोरेशन एक्ट के अनुसार जितना होना चाहिये उतना होता है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इतना और बता दीजिये। आपने प्रोफिट बताया वह पिछले साल ज्यादा था, इस साल कम था; इसका कारण क्या यह था कि गाड़िया नहीं बढ़ीं और रूट भी नहीं बढ़े ?

श्री मथुरादास माथुर : इसका यह भी एक कारण था। उदयपुर वालों की तरफ से हाईकोर्ट में एक रिट हो गई। माइलेज नहीं बढ़ा, ट्रैफिक पोटेन्शियेलिटी बढ़ी है, लेकिन इसके साथ में जो फैक्टर्स कांट्रिब्यूट हुए हैं

(श्री मथुरादास माथुर)

उन्होंने नेट प्रोफिट में कमी डाली है। दूसरी बात मैं छिपाना नहीं चाहता, वह यह है कि हमारे पास जो गाड़ियां हैं, उनमें से २५-३० परसेंट ग्रोफ दी रोड़ रहती हैं इसलिये कि उनका माइलेज पूरा हो गया है, लेकिन रिपेयर्स की व्यवस्था नहीं होने से रिपेयर्स नहीं हो रहे हैं। मेजर रिपेयर्स के लिये हम पहले से इन्तजाम नहीं कर सके। अब इन्तजाम करना चाहते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। हमने बोर्ड को कहा है कि प्राइवेट तौर से कांट्रेक्ट बेसिस पर रिपेयर्स हो सके तो करवालो और बीच में एमर्जेन्सी की वजह से नयी गाड़ियां भी कम आई। अभी १५ गाड़ियां हमको मिली हैं जिनके चेसिस बम्बई में बन रही हैं। हम इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा नयी गाड़ियां लावें, पुरानों के एंजिन ठीक करावें। सबसे अधिक हमारा बोटलनेक यह है कि नयी गाड़ियां मिली नहीं और ओल्ड गाड़ियों को रिपेयर करने के साधन नहीं रहे, इसलिये यह क्राइसिस आ गया। पहले शुरू-शुरू में मुनाफा इसलिये हुआ कि नयी गाड़ियां थीं, रिपेयर्स की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज ३० परसेंट गाड़ियां ग्रॉफ दि रोड़ हो गयीं। इसलिये मुसाफिरों को तकलीफ होती है। शिड्यूल्ड टाइम से लेट भी गाड़ियां पहुंचती हैं, बीच में रुक भी जाती हैं। माननीय सदस्यों के पत्र इस सम्बन्ध में आते हैं, उनको मैं देखता हूं, पढ़ता हूं और तकलीफ दूर करने की कोशिश करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलता हूं कि हम सब इसमें लगे हुए हैं और तीन-चार महीनों में ठीक करके वापिस वही प्रोफिट आपको दूंगा जो पहले था और आपको तकलीफ नहीं होगी

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल: क्या आप इस बात की जांच करायेंगे कि २५/३० परसेन्ट गाड़ियां ऑफ दि रोड क्यों हो गई? २५/३० परसेन्ट कम नहीं होता है। आपकी गाड़ियां चलती हैं तो उनके फाटक बोलते हैं, पानी ऊपर से टपकता है, खिड़कियां बजती हैं। इन सबके लिए क्या आप जांच करवाने के लिये तैयार हैं कि जिसमें इतना पैसा लगाया, वे गाड़ियां इतनी जल्दी क्यों खराब हो गईं और इनकी इतनी खराब हालत क्यों है? आप प्राइवेट बसेज को देखिये और यू० पी० और मध्य प्रदेश की रोडवेज की गाड़ियों को देखिये, वे कितनी बढ़िया हैं, हम भी इनमें बैठते हैं। हमारी गाड़ियां इस तरह चलती हैं कि होर्न बजाने की भी आवश्यकता नहीं रहती; उनमें इतनी आवाज होती है। इसकी क्या वजह है?

श्री भैरूंसिंह: हमारी गाड़ियां हेलिकोप्टर की तरह आवाज करती हैं।

श्री मथुरादास माथुर: साइलेंसर लगा देंगे.......

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुंडावत: फ्लीट की गाड़ियों की हालत खराब होती जायेगी जैसे जैसे पुरानी होती जायेंगी, तो क्या आने वाले साल में और भी ज्यादा खराब होंगी?

श्री मथुरादास माथुर: उम्र होती है, तो हालत खराब होती है। फिर भी रिपेयर्स करायेंगे, रिप्लेस करेंगे। एक गाड़ी की उम्र होती है, उसके लिये डेप्रिसियेशन फंड होता है, उसमें से नयी खरीदेंगे। कॉमर्शियल अकाउंटिंग में इस तरह का प्रोविजन रखा जाता है इसलिए हालत खराब नहीं होने देंगे।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसिन्द): क्या व्यवस्था की वजह से हमको नुकसान नहीं हो रहा है या कर्मचारियों को पैसा ज्यादा देते हैं, टी. ए. डी. ए. देते हैं उसकी वजह से नुकसान होता है या जो रिटर्न मिलता है उसमें चोरियां होती हैं, उसकी वजह से नुकसान होता है ?

श्री मथुरादास माथुर: यह इतना बड़ा नहीं है कि जिसका परसैन्टेज पर असर पड़े।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल: आप चाहे कांग्रेस के तीन मेम्बर्स की ही कमेटी बनाइये लेकिन इसमें इतना बड़ा बंगलिंग हुआ है उसकी जांच तो करवाइये।

श्री मथुरादास माथुर: पहले मैं जांच कर लूं, फिर आपका सहयोग लूंगा। यह कोरपोरेशन है, मैं भी तो जरा जांच कर लूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानता हूं कि ये जो स्टेट एन्टरप्राइजेज हैं उसकी तरक्की के लिये, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिये आपको चिन्तित होना स्वभाविक है क्योंकि यह जनता की इन्डस्ट्रीज हैं, जनता की मिलकियत है और उस जनता के नुमायन्दे इस सदन के माननीय सदस्य हैं इसलिये वे अपनी जवाबदारी महसूस करते हैं; यह ठीक भी है, इसमें दिलचस्पी लेना राष्ट्र व देश के लिये अच्छी बात है। इसलिये राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि स्टेट एन्टरप्राइजेज में जो बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स होगा उसमें जिस तरह से पार्लियामेंट की पद्धति है। टी बोर्ड, काफी बोर्ड आदि में पार्लियामेंट के नुमायन्दे लिए जाते हैं, बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की तरह काम करने के लिये, उसी तरह मैं भी सोचता हूं और राज्य सरकार भी सोचती है कि आगे बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में सदन के नुमायन्दे हों जिससे वे डेमोक्रेटिक वे में वहां पर काम कर सकें और अच्छी तरह से सहयोग देकर इन एन्टरप्राइजेज को सुचारु रूप से चलाने में हाथ बंटा सकें। इसलिये मुझे उम्मीद है कि सदन के माननीय सदस्य जिसको इस बोर्ड में रखा जायगा अपना पूरा सहयोग देंगे। ....

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा: मैं समझता हूं आप जो अनाउन्स कर रहे हैं मैं व्यक्तिगत रूप से उसको गलत मानता हूं इसलिए कि मेम्बर्स को लाकर इन पचड़ों में नहीं डालना चाहिये। आप खुद इसकी अच्छी तरह से देख-भाल करें, बनिस्बत मेम्बर्स को इन्वोल्व करने के।

श्री मथुरादास माथुर: यह पार्लियामेंट की पद्धति है और माननीय सदस्य ऐसे हैं जो इन बातों को समझते हैं, उनका सहयोग इसमें होना चाहिये। आप मुझे कीचड़ में क्यों फंसाते हैं? मैं भी आपकी तरह से वहां बैठा हुआ हूं। .....

श्री भैरोंसिंह: ऐसा मत कहें। वे अपना सहयोग बिड़ा कर लेंगे।

श्री मथुरादास माथुर: राज्य सरकार ने इस बात का भी फैसला किया है कि राज्य के एन्टरप्राइजेज में जो मजदूर और वर्कर्स काम करते हैं उनका भी, नुमायन्दा बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में होना चाहिये। सरकार ने फैसला किया कि एक नुमायन्दा उनकी तरफ से होना चाहिए जिसको नोमिनेट किया जाय मजदूरों और काम करने वालों में होशियार आदमी हैं और इन बातों को समझने वाले भी हैं। ऑफिशियल नुमायन्दों और आपके नुमायन्दों के साथ साथ इनके नुमायन्दे भी हों और सब मिलकर इस बात

(श्री मथुरादास माथुर)

का प्रयत्न करें कि स्टेट एन्टरप्राइजेज सुचारु रूप से चलें, इन अरमानों को रखता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैने आपके सामने प्लान और स्टेट एन्टरप्राइजेज के बारे में जो निवेदन किया उससे माननीय सदस्यों को संतोष होगा।

श्री अब्दुलगफ्फार: मै जानना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोविन्दसहाय।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर): उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट वित्त मंत्रीजी के द्वारा पेश किया गया है उस पर सत्ताधारी दल की ओर से तथा विरोधी पक्ष के लोगों ने टेक्सेज लगाये गये हैं उनका विरोध किया गया है। टेक्सेज का कितना सदुपयोग होता है उसके बारे में आप यह कह कर चलें कि विरोधी पक्ष वाले सब लोग सिर्फ आलोचना ही करते हैं। बगैर टेक्स के सरकार चल नही सकती। यह कहना सत्य है कि बगैर टेक्स के आमदनी नहीं हो सकती और बगैर आमदनी के कार्य नहीं चल सकता।

किन्तु उन टेक्सों का, आप जितने टैक्स लगाते है उन टेक्सों का दुरुपयोग होता है। जो टैक्स लगाये जाते हैं वे वसूल सही तरीके से होते हैं या नहीं इसके बारे में कभी वित्त मंत्री महोदय ध्यान नहीं देते हैं।

वित्त मंत्री महोदय के सामने कई बार यात्री-कर के मामले आये हैं लेकिन वह यात्री कर प्रति वर्ष बढ़ाते जाते हैं और प्रति वर्ष बढ़ाते जाने के बाद जब उनसे रिपोर्ट मांगी जाती है कि कितना प्राइवेट रूट्स पर चलने वाली बसों के अन्दर टेक्स बाकी है तो उन्हें जानकारी नहीं होती है। वे इस ओर ध्यान नहीं देते हैं कि वह बकाया टैक्स वसूल क्यों नहीं होता है? वह इस ओर ध्यान नहीं देते हैं कि जो पहले से टैक्स लगे हुए हैं उन टेक्सों को सही तरीके से, ढंग से और ईमानदारी से वसूल कैसे कर लिया जाय? अगर वह वसूल कर लिया जाय तो गवर्नमेंट को इतना पैसा मिल जायगा कि दुबारा प्रत्येक वर्ष माननीय वित्त मन्त्री महोदय को यह कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि इतना घाटा रहा है। नहीं तो यह प्रति वर्ष घाटा रहेगा, यह घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता है क्यों कि जो टैक्स लगाये जाते हैं और जो टैक्स बढ़ाये जाते हैं उनके बारे में जो रिपोर्ट आती है उनके बारे में ध्यान नहीं देते। मैं तो यहां तक कहता हूं कि धन लेखा समिति की रिपोर्ट्स काफी पेश हुई हैं, लेकिन वित्त मंत्री महोदय ने कभी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया है, कभी उनको पढ़ा नहीं है और वैसे ही बैठ कर बजट बना देते हैं।

आपने पिछले सालों में जितने बजट बनाये और उनमें हर विभाग में जितनी धनराशि स्वीकृत की थी उसके बाद उतनी राशि खर्च नहीं हुई, और खर्च जिस काम पर करनी चाहिए थी उस पर नहीं हुई। आपने बजट में जो आंकड़े दिये कि इतना समाज कल्याण में खर्च होना चाहिए, लेकिन वह उस विभाग में खर्च नहीं होती है।

इसी तरह आप चिकित्सा के अन्दर देख लीजिये। चिकित्सा विभाग की ओर से आप डिस्पेंसरी खोलते हैं, आप इसमें आयुर्वेद विभाग की ओर से भी औषधालय खोलते हैं, जिसके लिए सरकार बड़ा ढिंढोरा पीटती है

(वैद्य श्री गोविन्दसहाय)

कि इस विभाग के लिए हमारे यहां अलग आयुर्वेद मन्त्री हैं और अलग से हमने आयुर्वेद डाइरेक्टर नियुक्त किया है। किन्तु आज उस विभाग की हालत यह है कि आयुर्वेदिक औषधालयों की संख्या बढ़ती जा रही है और आयुर्वेद के वैद्यों के लिए भी आप कहते हैं कि उनकी इतनी संख्या बढ़ा दी है। यह भी कहते हैं कि हमने अनुसन्धान केन्द्र खोल रखे हैं। मुझे अफसोस है कि ऐसे अवसर पर आयुर्वेद मन्त्री महोदय हमेशा गायब रहते हैं और जो बातें यहां कही जाती हैं उनका जवाब देते नहीं हैं, उनको इस विभाग की जानकारी नहीं है। उनको धन्वन्तरी की संज्ञा देकर इस विभाग के अधिकारियों ने उन्हें चढ़ा रखा है। वे कहते हैं कि हमने इतने आयुर्वेदिक औषधालय खोल रखे हैं, उनकी इतनी संख्या बढ़ा दी है। लेकिन मैं निवेदन करूं कि जहां औषधालय हैं वहां या तो औषधालय के लिए भवन नहीं हैं, या फिर वैद्यों के बैठने के लिए जगह नहीं है, कुर्सी वगैरह नहीं है। मैंने कई बार आयुर्वेद विभाग के डाइरेक्टर को और आयुर्वेद मंत्री को कहा है कि आप जाकर देखिये कि जो आप आयुर्वेदिक औषधालय खोल रहे हैं, जो उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं उसकी हालत क्या है, उनमें जो दवाईयां होती हैं उनकी हालत क्या है? इनमें जो पैकिंग होते हैं, मैने कई बार कहा है कि औषध निर्माण शाला को इन पैकिंग पर लिखना चाहिए कि कौनसी तारीख को चूरन बनाया गया है। मुझे इसकी जानकारी है इसलिए मैं कहता हूं कि बरसात के बाद चूरन होता है वह बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है, उसमें कोई असर रहता नहीं है। इस लिए आपकी निर्माण शाला में यह व्यवस्था की जाय कि निश्चित तारीख को बन कर निकले और पैकिंग पर एक तिथि होनी चाहिए जिस तिथि के बाद में वह बेकार हो जाती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तिथि तक वह बेकार हो जाती है तब तक वह औषधालय में पहुंचती है। इसके अलावा औषधालयों में बैठने की जगह नहीं है, औषधियां रखने की जगह नहीं है। वैद्यों के बच्चों के लिए एजुकेशन देने के लिए कोई व्यवस्था हो वह नहीं है। और देहातों में रहने के लिए रूरल अलाउन्स जो सरकार देती है वह किसको देती है? वह डाक्टरों को देती है जिनके लिए रहने को बिल्डिंग बनी हुई है। इस तरह वैद्यों और डाक्टरों में असमानता रहती है।

एक तरफ आप यह महसूस करते हैं कि जब ब्रिटिश शासन था, विदेशी हुकूमत थी तब हम महसूस करते थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार एलोपैथी को प्रोत्साहन देना चाहती थी, और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को समाप्त करना चाहती थी, इसलिए इसपर ध्यान नहीं देती थी। किन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर वर्तमान के अन्दर, जब कि देश को आजादी मिले काफी समय हो गया है, उसके बाद भी भारत सरकार और राजस्थान सरकार का यदि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का बजट देखा जाय तो उसमें कितनी असमानता है? आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के साथ इतना सौतेला व्यवहार हो रहा है कि मैं कहता हूं कि आयुर्वेद मंत्रालय खोलकर केवल मात्र एक ढकोसला किया है। आप आयुर्वेद कालेज में जाकर देखिये, जैसा अभी उप-मन्त्री महोदय ने बताया है

(वैद्य श्री गोविन्द सहाय)

कि वहां १५० छात्रों के अध्ययन की व्यवस्था है लेकिन आज स्वतंत्रता प्राप्ति के अठारह वर्ष बाद भी वहां पर छयालीस छात्रों के रहने की व्यवस्था है। इसके अलावा एक एक कोठरी में कितने छात्र रहते हैं यह पता नहीं है, उस कोठरी की लम्बाई चौड़ाई क्या है यह पता नहीं है, और बाकी के छात्र कहां रहते हैं इसका पता नहीं है। और कहते हैं कि आयुर्वेद के लिये अलग मन्त्रालय खोल रखा है अलग मन्त्री हैं। जो इस विभाग की प्रगति की रिपोर्ट आती है उसमें कहा जाता है कि अलहदा मन्त्री नियुक्त किया हुआ है, अलहदा डायरेक्टर नियुक्त किया हुआ है। लेकिन उनके द्वारा यह व्यवस्था की हुई है। इसके अलावा ग्रेड के बारे में गुजरात की ओर से लिख कर आया है कि आयुर्वेद का ५ वर्ष का कोर्स रखते हैं और वैद्य की योग्यता रखते हैं एम. बी. बी. एस. की ग्रेड उनको दी जानी चाहिये, लेकिन मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर नहीं है। जब हम मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हैं तो कहते हैं मैं क्या करूं, फाइनेन्स मिनिस्टर मेरी सुनते नहीं है, फाइनेन्स मिनिस्टर पैसा नहीं देता है। यह जवाब देकर चलते हैं। मैं कहता हूं कि इस प्रकार वैद्यों के जीवन के साथ, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, यह एक ढकोसला हो रहा है। आप जो नया कोर्स ला रहे हैं उसमें आप छः साल का कोर्स रखने जा रहे हैं लेकिन छः साल के कोर्स को रखने के बाद भी ग्रेड क्या रख रहे हैं। मैं आप को निवेदन करना चाहता हूं कि इससे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का ह्रास होगा और उसका विकास नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, आप इस कोर्स को छः साल का रख रहे हैं और आधुनिकता और प्राचीनता का समावेश करके उस कोर्स को रख रहे हैं और उसमें हायर सेकण्डरी और संस्कृत प्रथमा पास छात्रों को कालेज में एडमिट करेंगे, परन्तु उसके बाद जब छात्र भिषगाचार्य कर के निकलेंगे तो उसे स्टार्टिंग ग्रेड क्या देंगे, वे हायर सेकण्डरी स्कूल के मास्टर से कुछ अधिक हैं। कोई आदमी कौन ऐसा बावला होगा जो हायर सेकण्डरी करने के बाद एस. टी सी. ट्रेनिंग करने के बाद यह ग्रेड प्राप्त करता है तो वह भिषगाचार्य क्यों करेगा जब कि उसके बाद भी वही ग्रेड देते हैं। इस स्थिति में भी आपने प्रगति की रिपोर्ट के अन्दर ग्रेड के बारे में कोई बढ़ोतरी करने का उल्लेख नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के जरिये मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड के टाइम के सवाई माधोपुर में १२८ औषधालय थे जिनमें से सत्तर अस्सी औषधालय ऐसे हैं जिनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं हैं या फिर भवन अधूरे रह गये हैं। जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड समाप्त हो गये उसके बाद वे औषधालय राजस्थान सरकार के पास आये, फिर भी उन भवनों में से काफी में न पट्टियां पड़ी हैं, न छतें है और न उनकी मरम्मत होती है। न वहां वैद्य है और न दवाइयों की व्यवस्था है। उनके लिए बारबार कहने पर भी मन्त्री महोदय ध्यान नहीं देते हैं जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने जवाब में कहा कि आप मेरे साथ चलिए और वित्त मन्त्री और मुख्य मन्त्री को कहिए मैंने कहा यह आपका डिपार्टमेंट है हम क्यों कहें? आप आयुर्वेद मन्त्री हैं, आप जब आयुर्वेदिक कालेज में जाते हैं या किसी आयुर्वेद सम्मेलन में जाते हैं तो वहां लम्बा

Page No. 105

(वैद्य श्री गोविन्दसहाय)

चौड़ा भाषण देते हैं और कहते हैं कि हमने आयुर्वेद का इतना उत्थान किया है। मैं कहता हूं कि छात्रों के अध्ययन के बारे में, ग्रेड के बारे में और उनको दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में इतनी असमानता है और इतनी अव्यवस्था है लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है।

वैद्यों के तबादलों के बारे में इतना बुरा हाल है कि मन्त्रीजी का ऑर्डर कुछ है, डाइरेक्टर का ऑर्डर कुछ है तथा सेक्रेट्री का ऑर्डर कुछ निकलता है, जब तक एक ऑर्डर पास नहीं होता है तब तक चार दिन के अन्दर दूसरा ऑर्डर मिल जाता है। इस अव्यवस्था का, इस झगड़े का शिकार कोई हो सकता है तो वह वैद्य हो सकता है। वह ही परेशान है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद मन्त्री का, उप-मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यहां वैद्यों के साथ, आयुर्वेदिक पद्धति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, यह बच्चों का तमाशा जैसा हो रहा है। यह बहुत ही शर्मनाक है, यह आयुर्वेद मन्त्री महोदय के लिए शर्म की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी बातें किन की कार्यवाही के कारण होती हैं? एक वर्ष पहले मैंने आप से प्रश्न किया था कि भिषगाचार्य और भिषगवर्य के छात्रों को रजिस्ट्रेशन मिलता है वह इण्डियन मेडिकल बोर्ड से मिलता है, उन्होंने उसकी फीस का पैसा जमा कराया हुआ है लेकिन वह जो छात्र हैं उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है और जो पुराने लोग हैं उनके रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल कराने के नाम से उनका सर्टिफिकेट मंगवाया था वह उनको वापिस नहीं मिल रहा है। यह झगड़ा डाइरेक्टर और मंत्री का हो सकता है। आयुर्वेद मंत्री ने आश्वासन दिया था कि शीघ्रातिशीघ्र दो महीने में इन लोगों को रजिस्ट्रेशन मिल जायगा, परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि आज गांवों में वैद्यों और दूसरे लोगों को यह विभाग परेशान करता है और कहता है कि क्योंकि आपके पास प्रमाण-पत्र नहीं है इसलिए आप चिकित्सा नहीं कर सकते। इस सम्बन्ध में वे बार-बार विभाग को पत्र लिखते हैं लेकिन उनका जवाब नहीं देते हैं। मैं उप-मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वैसे मंत्री महोदय इसको ठेकेदारी लिये हुए बैठे हैं आयुर्वेद की प्रगति के लिए और आपको इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि ठेकेदार वह हैं, इसलिए उनको कहें कि आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप इस्तीफा दे दें; लेकिन आप यह न कहें कि मुख्य मंत्रीजी नहीं सुनते हैं, वित्त मंत्रीजी नहीं सुनते हैं इसलिए ग्रेड नहीं बढ़ा सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, अनुसन्धान केन्द्र आज दो जगह खोले हैं—उदयपुर और जयपुर में, लेकिन उनमें जो आदमी नियुक्त हैं उनको कुछ जानकारी नहीं है और ऐसे आदमी को आपने विशेषज्ञ करके बिठाया है। किसी जगह पर किसी आदमी के लिए डाइरेक्टर कहता है कि यह उपयुक्त नहीं है तो मंत्रीजी कहते हैं कि यह उपयुक्त है। यह झगड़ा है, इसलिए आज तक अनुसन्धान केन्द्रों की रिपोर्ट नहीं आती है कि जिस मामले में अनुसंधान कर रहे हैं उसकी प्रगति क्या है, कितने केस उन्होंने लिये हैं और कितने केसेज में सफलता मिली है—ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। इसके बाद भी कहा जाता है कि हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, रिपोर्ट

(वैद्य श्री गोविन्दसहाय)
जल्दी छपने जा रही है। फिर भी उस रिपोर्ट का पता नहीं है। जो आदमी इन अनुसन्धान केन्द्रों में बैठे हैं वे उपयुक्त नहीं हैं और वे काम करते नहीं हैं....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : एक व्यक्ति अनुसन्धान नहीं करता है तो वहां पर कई हैं।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : आपके सांगला, अम्ल-पित्त और नाहरू—तीन अनुसन्धान केन्द्र हैं; लेकिन इनकी प्रगति रिपोर्ट नहीं छपी है। अगर है तो इस सदन को जानकारी दें कि जो प्रगति रिपोर्ट आपके पास आई है उसमें कितनी प्रगति हुई बताई है।

माननीय मंत्री के निरंतर कहने के बावजूद भी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। मैं यह कहूंगा कि यह सारी व्यवस्था इतनी निकम्मी है, इसलिये मैं आयुर्वेद मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले वर्ष माननीय मंत्री ने हमें यह आश्वासन दिया था कि आयुर्वेदिक निर्माणशाला में जो गड़बड़ियां हैं उनके लिये एक कमेटी बनावेंगे। जब उनसे पूछा कि आया यह कमेटी बनाई या नहीं, तो कहा कि यह पूछकर बनावेंगे।

एक माननीय सदस्य : क्या आरोप थे ?

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : आपकी निर्माणशाला के बारे में ये आरोप लगाये गये थे कि निर्माणशाला में वंसलोचन जो काम में लिया जाता है वह ६०) सेर के बजाय ५) रु० सेर का वंसलोचन काम में लिया जा रहा है और इलायची, लौंग, केसर आदि चीजें जो शुद्ध रूप में दवाइयों में प्रयोग की जानी चाहिये थी नहीं हो रही हैं और उसमें बड़ा भारी गड़बड़-घोटाला है। दवाइयों में अफीम की जगह निशोत काम में ली जाती है। ये सारी बातें थीं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : वैद्यों में ही घोटाला हो !

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : वैद्यों में कोई घोटाले नहीं। सरकारी कर्मचारी ही यह सब करते हैं। वे डाइरेक्ट गड़बड़ी करते हैं। हम तो जानते हैं कि असली का क्या भाव है और नकली कितने रुपये सेर आता है। इसलिये हम तो किसी में घोटाला नहीं करते।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कमेटी बननी थी निर्माणशाला को देख-रेख के लिये, मगर पिछले सत्र में हालांकि माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दे दिया था मगर जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अगले साल कमेटी बनावेंगे। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार सारे वैद्यों के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ कर रही है। वैद्यों को ऐसी जगह जंगलों में स्थानान्तरित कर दिया जाता है जहां पर मैं कहूंगा कि यदि मंत्री महोदय को कहा जाए रहने के लिये तो वे एक दिन भी वहां नहीं रह सकते। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप उनके बाल-बच्चों पर रहम करें। आप देखेंगे कि वहां पर उन लोगों के लिये बैठने को स्थान नहीं, रहने को जगह नहीं, दवाइयों का इन्तजाम नहीं, आवागमन के मार्ग ठीक नहीं। ऐसी हालत में वे लोग वहां पर किस प्रकार काम करेंगे ? आप इस आयुर्वेद के नाम पर सिर्फ ढिंढोरा पीटते हैं....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : वहां पर विशेष कारण हैं जैसा आपने बताया तो क्या वहां पर वैद्य नहीं जाते हैं ?

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर वैद्य क्या नहीं जाते हैं ? मैं कहूंगा कि जाते हैं । आदमी की माली हालत खराब होती है और खाने को रोटी नहीं मिलती है तो रोटी के लिए जंगलों में तो क्या महाजंगलों में भी जाना पड़ता है और रहना पड़ता है । आपने एक व्यक्ति को पांच साल पढ़ाया और उसका आपने एक निश्चित ग्रेड कर दिया । मैं आपसे यह कहूंगा कि एक आदमी है जो मैट्रिक पास कर लेता है और अगर आप उसको बाद में कहें कि फावड़े चलाओ तो वह फावड़े नहीं चला सकता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह आयुर्वेद का प्रश्न है । जरा समय इनको दिया जाय ।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : कर लगाते हैं आप, इसके बारे में मैं कुछ निवेदन करूंगा । सवाई माधोपुर का जिला आबादी के दृष्टि-कोण से करीब पांचवां जिला है । वहां पर पानी की क्या व्यवस्था है ? अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वहां पर पानी की बड़ी किल्लत है । वहां पर किसी का हुक्म चलता नहीं, मिर्धा साहब का भी नहीं जाता । वहां पर तो वहां के एक अधि-कारी का चलता है । काली बांध में से पानी निकालने का था और उससे सवाई-माधोपुर को पानी देने की बात थी, मगर वहां के एक अधिकारी ने लिख दिया और उसके लिखने के अनुसार सब कुछ हो गया और वह पानी नहीं दिया गया, हालांकि वह कमान्डेड एरिया है । ऊपर वाले कुछ कर नहीं सकते । नीचे वाले अधिकारी ने जो कुछ लिख दिया वह ठीक लिखा है । वहां पर एक ट्यूब वेल है जिसके लिए पंचायत समिति को ४५ हजार की मंजूरी हुई थी । मैं यह निवेदन करूंगा कि आप सारी की सारी सुविधायें शहरों को देते हैं और टैक्सों का भार गांवों पर पड़ता है । कम से कम आप जितने टैक्सेज लगावें और खास कर घी और तेल पर लगावें, लगावें मगर पानी तो गरीब जनता के लिए आप मुहैय्या करें । मैं यह नहीं कह सकता कि आपने इन पिछले १८ वर्षों में इसके लिए क्या किया ? मैं यह कह सकता हूं कि उत्पादन की दृष्टि से और रेवेन्यू की दृष्टि से इस जिले का स्थान ५ वां या छठा है । राजस्थान की तरफ से सुरक्षा कोष में पिछले साल सातवां नम्बर था और इस वर्ष आठवां नम्बर रहा है । जो जिला हमेशा ऐसे कार्यों में अग्रसर रहा है वहां पर पानी तक उपलब्ध नहीं होता और वह इसलिए नहीं होता कि वहां पर मंत्री महोदय का कहा नहीं होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं हमारे यहां की खाद्य स्थिति के लिए निवेदन करूंगा । खाद्य मंत्री महोदय का ध्यान हमारे यहां पर जो सरकार की नीति थी उसके बारे में आकर्षित किया था और खाद्य मंत्री से कहा था कि लोग चोरी से ९०) रु० क्विन्टल के भाव से नाज हासिल करते हैं जहां आपने ५२) रु० की रेट रखी है । ८० परसेन्ट किसानों की शुभचिन्तक कहलाने वाली सरकार को चाहिए कि इसको रोके । मगर उस वक्त नहीं रोका । उससे किसानों की और दूसरे लोगों की बरबादी हुई और उन लोगों को ब्लेक से ८० और ८२ रुपये क्विन्टल के भाव से नाज बाजार से खरीदना पड़ा ।

(वैद्य श्री गोविन्दसहाय)

मैं यह भी कहूंगा कि सप्लाई ऑफिसरों ने अपना व्यवहार ऐसा कर रखा है कि किसी बात का ठीक तरह से उत्तर नहीं देते । अगर मि. हावा साहब से कोई बात भी करें और उनको उनकी पॉलिसी के बारे में पूछें तो कुछ भी पता नहीं चलता । अभी चावलों की लेवी का आपने सिस्टम निकाला है, वह सिस्टम इतना निकम्मा है कि जिसकी कोई हद नहीं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं कि आपने उसमें क्या किया? आपके बाजार के भाव बहुत ऊंचे जा रहे हैं । मैंने उसके बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आप को क्या जरूरत है । मैंने पूछा कि रेट के बारे में पूछता हूं, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं; मगर उन्होंने कोई बात का उत्तर नहीं दिया। आज १८४)के भाव का चावल किसानों से व्यापारियों ने खरीदा । २७ तारीख को ऑर्डर जाता है कि हम मिलऑनरों से लेवी वसूल करेंगे । मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यू. पी. का सिस्टम अलग था और हमारे यहां पर अलग सिस्टम है । हर जगह के आढ़तिए होते हैं । यू. पी. में सारे मिल मालिक खोल कर बेचते हैं । मगर आज गंगापुर में आपके व्यवहार से १५ लाख के चावल सील कर दिये गये । आप उनको बाद में कहते हैं कि हम ६४ में लेंगे । आप देखें कि जब उन्होंने १८४) के भाव से खरीदा तो वे आपको इस भाव से कैसे दे सकते हैं? उन लोगों ने आखिर १६ हजार रुपया खर्च करके १६ तारीख को ऑर्डर निकलवाया कि २६ तारीख तक खरीदा हुआ हो उस पर कोई लेवी नहीं ली जावेगी । ये ऐसे फीगर्स हैं जो अगर आप जांच करावें तो मैं आपको बता सकता हूं। मंत्री महोदय ने यह नहीं सोचा कि १५ लाख की कीमत का माल सील किया जाय तो उसका कितना ब्याज लगता है और उससे व्यापारियों को कितना नुकसान होगा । आपने अनाज के व्यापार को खत्म कर दिया और अब आप दूसरे व्यापारियों को भी खत्म करना चाहते हैं । आपको अगर लेवी लेनी है तो आप लेवी लीजिए । मगर व्यापारियों ने चावल १८४) रुपये के भाव के खरीदे और आपने रेट ६४) रुपये मुकर्रर की तो उनके माल को आपने सील कर दिया, तो यह कैसे हो सकता है कि वे आपको इतना घाटा खा कर माल दे दें । आपने ९ फरवरी को गजट निकाला, उसमें आपने लिखा है कि २६ तारीख तक के खरीदे हुए चावल पर लेवी नहीं ली जावेगी । गंगानगर की मण्डी से १६,०००) रुपये आपके विभाग ने खाये हैं । मैं उसकी एन्ट्रीज आपको बता सकता हूं ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): यह कौनसा विभाग है ?

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : विभाग तो फूड का ही है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : फूड विभाग से किसने खाये हैं ? आप गोल-मोल कह कर आरोप लगाना चाहते हैं; इससे कुछ नहीं हो सकता ।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : ऑर्डर जारी कौन करता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऑर्डर जारी मैं करता हूं ।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : प्रकाशित कौन कराते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : प्रकाशित अधिकारी करते है ।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : वे रोक कर बैठ गये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : वे एक मिनिट भी रोक कर नही बैठ सकते हैं ।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : आपने यह कहा कि एक मिनिट भी नहीं रोक सकते, तो फिर यह ९ फरवरी को क्यों निकला ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी तरह से कई दलाल लोग फिरते हैं। कई लोग मेरे पास आये थे और मैंने उनसे यह कहा था कि चन्दा उन्होंने जो इकट्ठा किया है उस चन्दे को वे किसी को न दें और मैं यह कहूंगा कि उनको इस बात के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा । उनकी वकालत आप जैसे कई लोग करते हैं, करिए, मगर मैंने उनको साफ कह दिया था कि आपने जो चन्दा इकट्ठा किया है उसमें से एक पैसा भी किसी को मत देना । मुझे मालूम हुआ था कि चन्दा एकत्रित किया गया है।

उन्होंने पचास हजार का चन्दा इकट्ठा किया था, मुझे मालूम है, लेकिन मैंने इस बात का ध्यान रखा कि इनका एक पैसा भी कहीं नहीं जाय ।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : यह बहुत बड़े घोटाले की बात है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप उनकी वकालत करना चाहते हैं, लेवी के कानून को उठाना चाहते हैं, आप चाहें तो २५ दलीलें दें । आप अपने वोट व्यापारियों से लेने की कोशिश करें, मुझे एतराज नहीं है, पर अंट-शंट बातें नहीं करें ।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : मैं कोई व्यापारियों की वकालत नही करता, जैसा मंत्री महोदय ने कहा, क्योंकि वे तो आपके साथ रहेंगे । नाजायज फायदा तो आपसे ही लेंगे, मेरे पास क्या रखा है ? मैं इस प्रश्न के मामले में वकालत की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं । वे मेरे पास आये कि हम लोग चंदा दे रहे हैं। मैंने कहा, भारी भूल कर रहे हो, आप डाइरेक्ट बात करो ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप उनको बुला दीजिए कि किस आदमी को कितना चंदा दिया है। मैं सारी जांच करके रिजल्ट बता दूंगा कि यह गलत और बे-बुनियाद बात है । जो कहता है कि हमने दिया उसको मेरे पास ले आओ ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आप सुनते तो जाइए ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं फालतू बात सुनने का आदी नहीं हूं ।

श्री मानसिंह महार : हम फालतू बात करते ही नहीं ।

(शोरगुल-घंटी)

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को लेकर आपकी तरफ से प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है, कोई आपत्ति नहीं की जा रही है। माननीय सदस्य अपने विचार रख रहे हैं, उनको इन्टरप्ट किया जाता है, व्यापारियों का दलाल कहा जा रहा है ।

Page No. 110

श्री नाथूराम मिर्धा : गलत बात को कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस प्रकार आप बातों को तोड़-मरोड़ नहीं सकते। आप सुनने का माद्दा रखें।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : मंत्री महोदय को गलतफहमी हुई है और कुछ भावुकता में आकर कह गए। मेरे पास जिस समय यह बात आई कि दो रुपया बोरी के हिसाब से १९ हजार बोरियों का ३८,०००) चंदा मांगते हैं, तो मैंने कहा डाइरेक्ट मंत्री महोदय मांगते हैं तो दे दो और दलालों के झगड़े में मत पड़ना।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : यह आंकड़ा कहां से मिला ?

(शोरगुल)

श्री मानसिंह महार : इस तरह से ये लोग करेंगे तो हम भी आपको नहीं बोलने देंगे।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : आप व्यापारियों की कैश बुक्स मंगवा लीजिए। जो कुछ मंत्री महोदय कहते हैं वह सही नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे इस बात का पता है कि उन्होंने चंदा इकट्ठा किया था। आप कह रहे हैं २८ हजार और २० हजार मैं कहता हूं ५०,०००, लेकिन मैंने इस बात का एहतियात बरता कि इनका एक पैसा भी चंदे का कहीं नहीं लगाना चाहिए। सारी बातों को समझकर फिर आदेश जारी किये थे और मैंने उनसे कहा था कि जो आपका २६ तारीख का स्टॉक है और २७ तारीख से जो हमने लेवी लगाई है, २६ तक के पहले के स्टॉक को एग्जेम्प्ट करके जो पहले से सीज कर लिया है, इसलिए एक पैसा भी मत खर्च करना और अगर तुम खर्च करोगे तो तुम्हारी गलती है और तुम किसी को मत देना। यह बात मैंने और मुख्य मंत्रीजी ने साथ बैठकर कही।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसका मतलब स्पष्ट हो गया और चार्ज आप पर बिल्कुल नहीं लगाए।

श्री नाथूराम मिर्धा : इल्जाम मुझ पर नहीं लगाए। मेरे विभाग के किन्हीं लोगों के लिए कहा कि जिन्होंने लिया है। आप चुपचाप उन व्यापारियों को मेरे पास लाएं और बता दें कि किसको यह पैसा उन्होंने दिया है। यह बात अगर मुझे पहले कन्विन्स करें, बजाय सदन में कहने के, तो मैं आपको समझा दूं कि मैंने इस बात का एहतियात बरता है।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : भावावेश में आकर आपने कहा है कि वकालत करते हो। वोट तो आपको भी लेने पड़ते हैं और हमें भी लेने पड़ते हैं। आपके विभाग की बात करता हूं। आप सुनते नहीं हैं और आप कहते हैं कि माधोपुर में कोई खाद्य समस्या नहीं है। रोज आपके सामने प्रदर्शन होते हैं। आप तो ऐसे कहते हैं जैसे आपके पास कोई सर्वाङ्गीण यंत्र है। आप पानी के बारे में बताइए, बांधों की स्थिति बताइए, सिंचाई की अव्यवस्था है........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वहां हमारे क्षेत्र में झगड़ा हुआ, आपके विभाग का आदमी ४००) रुपए खा गया, आपके विभाग को तार भेजे........

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री कृष्णकुमार गोयल : उनको अपनी बात समाप्त करने दें ।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : सिर्फ दो मिनट निवेदन करूंगा । लेवी वाले मामले, जिसके बारे में मंत्री महोदय ने कहा........

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! श्री ज्वालाप्रसाद ।

श्री मानसिंह महार : पॉइन्ट आॅफ आॅर्डर, सर........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मेरा नाम ले लिया गया है ।

श्री मानसिंह महार : पॉइंट आॅफ आॅर्डर । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पॉइंट आॅफ आॅर्डर यह है कि मेरी पार्टी का समय बहुत है । अभी बहुत........

श्री उपाध्यक्ष : आज आपकी पार्टी के ही अधिकतर सदस्य बोले हैं । अब भी जो समय है उसमें से भी दिया जायगा ।

श्री मानसिंह महार : यह अन्याय है । जब सरकार का रिप्लाई होगा, फिर आप कहेंगे कि तुम अव्यवस्था फैलाते हो, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं । आपको पूर्ण अधिकार है, जिसको आप बोलने दें; लेकिन हमारी पार्टी का समय है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपको समय दिया जायगा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं जब भी खड़ा होता हूं तो ये महाशय कुछ न कुछ हरकत करते हैं, उसके लिए कट मोशन्स के समय बात करूंगा । मैं एक बात सदन में कहना चाहता हूं कि बजट के डिस्कशन के समय हमको देखना है कि आज स्थिति क्या है....

श्री मानसिंह महार : भुखमरी है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस सिलसिले में इस सदन को सही तौर से अपना कर्त्तव्य अदा करना चाहिए । हमें सोचना होगा कि किस तरह के हालात है और आम लोगों के अन्दर एक अव्यवस्था फैल रही है, लाॅ और आॅर्डर की पोजीशन पैदा कर रहे हैं उसके लिए । यह अच्छी बात है कि राजस्थान के लोग समझदार हैं, लेकिन चारों तरफ से जिस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं उन स्थितियों के अन्दर उससे राजस्थान को बचाना है । तो इस सदन के सब सदस्यों का कर्त्तव्य है कि वे अपनी जिम्मेदारी महसूस करें । जब गरीबी आम लोगों में होती है तो इस तरह के लोग जनता के अन्दर होते हैं जो अपने को नेता कहते हैं, जिन्होंने अपनी जिन्दगी का उसूल बना लिया है कि किस तरह झगड़ा पैदा हो; विरोधियों के वे दलाल हैं जिनसे दुश्मनों को मौका मिलता है । मैंने जुलूस भी देखे और नारेबाजी भी सुनी । जहां सरकार सुचारु रूप से काम कर रही है, बढ़ावा देकर कुछ लोग ऐसी अव्यवस्था पैदा करते हैं, जनता और सरकार के बीच में एक केआॅस पैदा करना चाहते हैं, उससे सरकार को आगाह होना चाहिये और इस बजट के समय में आज राजस्थान में जो स्थितियां हैं उन पर सोचना चाहिये । यहां के अफसरों को सबक लेना चाहिये कि जनता का विश्वास प्राप्त करें । आज सरकार को, लेजिस्लेटिव असेम्बली के मेम्बर्स को इस प्रकार के काम करने चाहिये

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कि जिनसे जनता में इनके प्रति विश्वास पैदा हो, डेमोक्रेसी को पनपाने के लिये, जनता के हित के लिये हम काम करते हैं इस प्रकार का पूरा विश्वास सरकार को, सरकारी अफसरों को और लेजिस्लेटिव असेम्बली के मेम्बर्स को जनता में पैदा करने चाहिये। इस प्रकार के कदम उठाने चाहिये, इस प्रकार का व्यवहार सरकार को करना चाहिये, मेम्बर्स को इस प्रकार का वातावरण पैदा करना चाहिये। इस प्रकार का वातावरण सरकारी अफसर, सरकार और मेम्बर्स जनता में पैदा करेंगे तभी जो क्राइसिस हमारे मुल्क के सामने हैं उनसे हमारा मुल्क निकल सकता है।

आज और बातों पर ज्यादा न कह कर इस बजट के सिलसिले में मैं कुछ आपके सामने कहना चाहूंगा। इस बजट को जो पहनावा पहनाया गया है वह देखने में, सुनने में, अच्छा लगता है; इसका तरीका तो ऐसा है जिससे मालूम होता है टैक्सेज बहुत नहीं लगाये हैं। जिन मजबूरी की हालात से राजस्थान निकल रहा है उसको देखते हुए ज्यादा टैक्सेज नहीं लगाये गये हैं, यह कहा गया है कि सरकार जानती है कि जनता और टैक्सेज के भार को उठाने में नाकाबिल है, पर साथ ही तरीका दिया गया है कि २३३ करोड़ रुपयों का घाटा; पर २५५ करोड़ रुपये का माल सरकार के पास मौजूद है; इसलिये यह घाटा नहीं है। इसके मजाज से यह सिद्धान्त बताया गया है कि जो कर्जदार जितना ज्यादा होता है उसमें उतना ही ज्यादा जनता का विश्वास है, यह कर्जदारी हमारे विश्वास की द्योतक है, हमारे विकास की द्योतक है, इससे मैं इत्तफाक नहीं करता। सरकार को कोशिश यह करनी चाहिये कि टैक्सेज के बजाय स्टेट एन्टरप्राइजेज को बढ़ाये, कुदरत ने जो खजाना हमें दिया है, जो पोटेन्शियेलिटी कुदरत ने राजस्थान को दी है, जो चीजें हमारे पास हैं, उनका प्रॉपर एक्सप्लॉइटेशन करके उनसे अपनी इन्कम को बढ़ा कर जनता के फायदे के कार्य करें, जनता को फायदा पहुंचायें। आपके हाथ में ऐसा प्रॉविन्स है जिसके मुकाबले किसी की पोटेन्शियेलिटी नहीं, हम हिन्दुस्तान के किसी भी प्रोविन्स से पिछड़े हुए नहीं हैं। हमारे खेतों में, हमारी खानों में इतनी पोटेन्शियेलिटी है कि हम नॉन-टैक्स रेवेन्यू से राजस्थान की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इस ओर राज्य सरकार का सही तौर से रुख होना चाहिये, बजाय इसके कि जनता बजट के समय इस बात से डरे कि सरकार कहीं और टैक्स नहीं लगा दे। जनता का सहयोग और विश्वास प्राप्त करके सरकार को पब्लिक सेक्टर में इन्कम के रिसोर्सेज पैदा करने चाहिये ताकि जनता बजट के समय यह सोचे कि पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देकर हमने देश की सेवा की है जिससे सरकार टैक्सेज को छोड़ेगी, हम पर टैक्सेज का वजन कम होगा।

मैं इसके साथ ही साथ और पॉइन्ट्स को छोड़ते हुए इस बात पर आता हूं कि आज हमारे राज्य के कर्मचारी की क्या हालत है? मंहगाई से उत्पीड़ित गरीब राज्य कर्मचारी को यह कहा जाय कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम टैक्सेज लगा नहीं सकते, हम हमारे छोटे-छोटे कर्मचारियों को, उनके घर के खर्चे को चलाने के लिए, जो उनके घरों में पीड़ा और दुःख है, उनके दुखों को दूर करने के

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

पैसा नहीं दे सकते और उधर आई. ए. एन., आई. पी. एस. अफसर हैं १२०० से २२०० रुपया माहवार पाने वाले उनको १०० रु. डियरनेस अलाउन्स सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, उनको अपने एक्सचेकर से देने वाले आप कौन ? आप ऐसी केपिटेलिज्म और शोषण की पॉलिसी चलायेंगे, एक चौकीदार और जमादार को आप नहीं दे सकते क्योंकि आप कहते हैं, हम गरीब हैं, पर जितने आई. ए. एस., आई. पी. एस. ऑफिसर्स हैं १२०० से २२०० तक पाने वाले हैं, उनका १००) रु० बढा देंगे, एक इशारा होगा सेन्ट्रल गवर्नमेंट का। आज पुलिस राज्य नहीं, वेलफेयर स्टेट है, सोशियेलिज्म की ओर बढ़ने की बात है। आप ने १००) बढाने की बात कैसे मानी ? इन छोटे-छोटे चौकीदार और क्लर्कों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया ? आप टैक्स नहीं लगा सकते तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट देगी। ये छोटे-छोटे लोग तो आपकी दुनिया नहीं मांगते, जरा-जरा सी तरक्की से खुश होने वाले लोग हैं। इनको अपने घर का खर्चा चलाने में जो पीड़ा हो रही है, इनको अपने बच्चों का पेट पालने में जो उत्पीड़न हो रहा है उनको आप कुछ नहीं देना चाहते। फाइनेन्स मिनिस्टर साहब जवाब दें कि कैसे १२०० से २२०० रुपया पाने वालों को १०० रुपया देने का सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेअर किया। उनको राज्य सरकार पैसा देगी पर गरीब नौकरों को एक पैसा नहीं मिलेगा और फिर क्या बोलते हैं ?

प्यास बुझाना चाहते हैं जो ओस हरी घास पर पड़ी है उससे ! कहते हैं हम कन्ज्यूमर्स स्टोर्स खोलेंगे, इसके लिए एक करोड़ रुपया रखा है। कन्ज्यूमर्स स्टोर्स हैं क्या चीज ? स्टोर्स मत खोलिए, मैं गरीब नौकरों की तरफ से कहता हूं। आप इन्डेक्स फीगर निकालिए ६४–६५ का कि नेसेसिटीज की चीजों की क्या कीमत थी ? नेसेसिटीज की चीजों में चीनी, गुड़, तेल, दालें अनाज और साबुन, ये पांच चीजें हैं जिनको गरीब रोज काम में लेता है। ये ५ चीजें स्टोर्स में रख दीजिये। जो इन्डेक्स निकालें उसको ६४ की कीमत पर दीजिये। तो मांग सिर्फ यह है कि इन स्टोर्स में ये पांच चीजें मिलें। सरकार सब्सक्राइब करे, जो घाटा हो सरकार दे और उनको फिक्स प्राइस पर जब तक कि मंहगाई का चक्कर है हर नौकर को सरकार ये चीजे दे पहले भी यह हुआ है, लड़ाई के टाइम में हुआ है और इस प्रकार बढ़ती हुई कीमतों को पहले रोका गया है, रेल्वे ने किया है; जो हाहाकार बढ़ रहा था, उसको रोका है। मैं तीन साल से इस पर जोर दे रहा हूं, आपने माना। तो कन्ज्यूमर्स स्टोर्स का रखा। आपने तारीखें लगाई हैं जुलाई में यह खोला जायेगा, अक्टूबर मे यह खोला जायगा, रोटी तो उसको आज चाहिए।

तो इस प्रोब्लम पर सरकार सही तरीके से सोचे और समझे। आज देश में जिस प्रकार की स्थितियां पैदा हो रही हैं उनसे निकालने वाले ये सिपाही हैं, चौथे नम्बर के क्लास फोर्थ सर्वेन्ट्स है, ये ही इस देश को बचायेंगे। इस आदमी को जरूरत है घर में शान्ति की। शान्ति के लिए जरूरी है कि हर पुलिस वाले को, हर गरीब नौकर को जरूरत की सब चीजें एक फिक्सड प्राइस पर मिलें। इस भाव से मिले कि वह अपनी तनख्वाह में अपने घर का खर्चा चला सके,

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

चाहे सरकार का कितना ही पैसा लगे उसको निश्चित रखना चाहिये कि उसके बच्चों को, उसके घर वालों को उसकी तनख्वाह में पूरी रोटियां मिल जायेंगी।

इस सदन को बराबर इस बात का नोटिस लेना होगा कि जो बराबर घाटा दे रहे हैं, चाहे डाइरेक्टर हो, चाहे कोई हो, उसका नाम लेकर आप बच नहीं सकते। ८ लाख की गारन्टी आपको बैंक से मिलेगी, बैंक की गारन्टी स्टेट गवर्नमेंट शेड करेगी। ८ लाख रुपया तक उनको उधार दे दो, वह नहीं देंगे तो हम देंगे। कोआॅपरेटिव सेक्टर में क्या होता है, कोई गारन्टी कोआॅपरेटिव सेक्टर को नहीं दी जा सकती। कोई काम करे, कोआॅपरेटिव का जिससे सोशियेलिस्टिक पैटर्न आॅफ सोसाइटी कायम करना चाहते हैं। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि लेखन का काम करने वाले हैं, इससे जिनकी रोजी चलती है, उन्होंने एक कोआॅपरेटिव बनायी। रजिस्ट्रार के पास गये। उनकी शर्त थी कि तीन डाइरेक्टर्स कोआॅपरेटिव डिपार्टमेंट के होने चाहिये। ४० आदमियों ने सोसाइटी बनायी और जगह प्रेस का लेखन का काम करने वालों को सब्सिडी दी। सभी जगह शेयर्स खरीदे। जितने मेम्बर्स हैं वे लेखन कला पर हैं और दूसरे धन्धे पर नहीं रहते हैं, दूसरे हैं धन्धे भी करते हैं, उनको सब्सिडी दी और शेयर केपिटल दी, लेकिन यहां के रिप्रेजेन्टेटिव हैं, मैं अपनी जानकारी से कहता हूं कि बहुत से अपना धन्धा चलाते हैं, उन्हीं की स्कीम के मातहत उन्होंने कोआॅपरेटिव बनायी तो पहले तो उनको सेन्क्शन देने में आनाकानी की, लेकिन जैसे तैसे कानून बना दिया, तीन महीने में जवाब देना होगा, जो कानून बनाये उनको एक्सेप्ट किया, डाइरेक्टर होगा यह एक्सेप्ट किया। कोआॅपरेटिव डिपार्टमेंट १००) रु० के शेयर खरीदेंगे, इसके लिये तैयार नहीं हुए। कानून के खिलाफ अन्डरटेकिंग ली गई। कुछ नहीं मानेंगे। कुछ भी लिखवा लीजिये, कोअर्शन से लिखवा लीजिये, उसकी कोई कानूनी कीमत नहीं। गवर्नमेंट आॅफ इन्डिया से रुपया लिया जाय, गवर्नमेंट आॅफ इन्डिया ने रुपया रखा है उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। वे कहते हैं कि आपको गवर्नमेंट रिकमन्ड कर दे तो सेन्क्शन करने के लिये तैयार हैं। वे पालथी मांड कर बैठे हुए हैं। कोआॅपरेटिव एक वे आॅफ लाइफ है, सोशियेलिज्म को लाने वाली चीज बन जाय, लॉ बन जाय फिर भी उनकी दया पर कोआॅपरेटिव बनती है। कोआॅपरेटिव एक धर्म है, सोशियेलिज्म लाने के लिये कांग्रेस ने माना है। उसके लिये ऐसी वृत्ति को मैं एक निकम्मी वृत्ति मानता हूं। ये जो सारी जनता की समाजसेवी संस्थायें हैं उनके साथ कोआॅपरेटिव डिपार्टमेंट का ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए और सेन्ट्रल गवर्नमेंट लाखों रुपया देती है तो उनको रुपया दिलाना चाहिये। और गारन्टी! कोआॅपरेटिव को इयोरिटी नहीं मिलेगी; इन्डिविजुअल को मिलेगी। कोई सेठ आजाय तो आप कहेंगे तुम्हारे तो बाका हम ही हैं। कोटा की स्ट्रॉ बोर्ड फैक्टरी में क्या हुआ? कोआॅपरेटिव को कोई गारन्टी न दी जाय, यह कहते हैं: क्यों नहीं? गवर्नमेंट के आठ डाइरेक्टर्स रहते हैं, गवर्नमेंट का कन्ट्रोल रहता है, सेक्रेटरी अपॉइन्ट कर सकते हैं लेकिन कोआॅपरेटिव को गारन्टी नहीं, उसके लिये गारन्टी की बात क्यों? इन्डिविजुअल के लिये नहीं; उनके लिये आगे से आगे तैयार। इस लिहाज से इस पर जोर दिया है कोआॅपरेटिव

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
एक धर्म है हमारा, एक वे ऑफ लाइफ है, गरीबी को दूर करने की कोई चीज है। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट, उसकी जड़ों में स्वार्थ का पानी दिया तो हमारी आशा ही मिट जावेगी। कोऑपरेटिव हमारा सहारा है। कोऑपरेटिव से ही दिमाग से काम कर सकते हैं। यही सहारा नहीं रहा तो जनता के इन्कलाब का इस देश को सामना करना पड़ेगा; इसमें मुझे कोई शक-शुबहा नहीं है।

दूसरी चीज आपके सामने रखूं। १२४ करोड़ रुपयों का ऋण और उस पर ६ करोड़ रुपया ब्याज के बनते हैं। १ करोड़ १० लाख ब्याज का बताया। ब्याज किस पर है? जो ब्याज दे सकते हैं। सिक्योर्ड अमाउन्ट है उसका ब्याज नहीं आता है। मकानों की तरफ दे रखा है, उनकी तरफ निगाह नहीं जाती है। सुराख बन्द करने के लिये तो और घी। ३ परसेन्ट लगा कर सुराख बन्द करना चाहते हैं।

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) : गलत कह रहे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : बैठो लाला; बैठो।

श्री गंगासिंह राठौड़ : तेल, घी के सुराख बन्द नहीं हो सकते।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कौन कर सकते हैं? इस विषय में मैं यह तो नहीं कहता कि टैक्सेज मत लगाओ। मैं यह भी नहीं कहता कि प्रगति को रोक सकते हैं। मैं यह भी नहीं कहता कि प्रगति रुके। यह सरकार काम चलाने के लिये बैठी है, दबाने के लिये नहीं बैठी है और इस उम्मीद में बैठी है कि हम फिर आवें। जनता में विश्वास है। आप इलेक्शन के दिन हैं, टैक्स से हट जाओ। जिम्मेदारी है। खाली तालियां पिटाने के लिये काम नहीं करने वाले हैं। विकास और प्लानिंग के जरिये जो बोझा उठाना पड़े तो सरकार उठायेगी और बराबर उठाना चाहिये। आप यह देखते हैं कि किसान का दर्द हमारे ऊपर ही है। अपोजीशन को नींद नहीं आती है। कोई दर्द है तो इधर वालों को है....

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन—सु.) : यह तो मन्त्रियों से पूछो कि दर्द उनके है या नहीं?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यें यें यें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि ऐसी हालत में आम जनता जिसके हम रिप्रेजेन्टेटिव्ज हैं उनके बारे में यहां कोई दम भरना और कोई पार्टी दम भरती है, यह सरकार किसान का पूरा ख्याल रखती है और गाड़ी चल रही है; नीचे नीचे मैं ही घसीट रहा हूं कोई बैल नहीं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एक बात बता दीजिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तू भी धीरे बोल, कहीं चक्कर आ गया तो आफत हो जावेगी।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आज यह सरकार आपकी वजह से नहीं, इधर जो लोग बैठे हैं और उनकी दरख्वास्त सुन रही है, सरकार कुछ बतला नहीं सकती क्योंकि बजट का सवाल है; हमारे मेम्बरों ने मांग की है कि टैक्स हम चाहेंगे सो लगेंगे, हम नहीं चाहेंगे सो नहीं लगेंगे।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : पहले पूछ लो।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : बैठ जा, बैठ जा।

तेल और घी की बात। कोल्हूवाला है। गांव-गांव में बैठा है। गरीब कुछ नहीं रखता है। आपका अधिकारी कोल्हू वाला, तेल वाला और घाणी वाला से कहेगा तो क्या मिलेगा ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह घंटी मेरे ऊपर ही पड़ती है। आपकी छुरी गरीब पर चलती है।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनिट सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) : आधा घंटा बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Five minutes.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह तो आपकी कृपा है, पांच मिनिट और तीन मिनिट का क्या हाल होता है। आधा घंटा बढ़ा दें तो बात करूं।

कुछ टैक्सेज के बारे में मैं कहना चाहता हूं। टैक्सेज आप लगाते हैं तो आप वे कानून के अनुसार लगाना सीखें। मैं तो यह कह सकता हूं कि टैक्सेज के बारे में आपके सारे डिपार्टमेंट्स जानबूझ कर कोई न कोई खामी रखते हैं, कुछ न कुछ नुक्ता रख देते हैं, जिससे हाई कोर्ट में चैलेन्ज हो सकें, सुप्रीम कोर्ट में जा सकें। यह जो इस बात का घुन लगा हुआ है, लॉ डिपार्टमेंट नहीं जानता, आप नहीं जानते, यह इतना पुराना डिपार्टमेंट होते हुए, हर टैक्सेज के मामले हम देखते हैं कि हाई कोर्ट में चैलेन्ज हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेन्ज हो जाते हैं। उस पर आपको दो-दो, तीन-तीन दफा अध्यादेश निकालने पड़ते हैं। कम से कम आप इस जलालत से तो बचाइये।

पर्चेज टैक्स और पैसेन्जर टैक्स के बारे में मैं कानूनी आपत्ति करता हूं। जब तक प्रेसीडेन्ट की कन्सेन्ट न हो, आपके पास राज्यपाल की कन्सेन्ट है, प्रेसीडेन्ट ने अब तक कन्सेन्ट नहीं भेजी है, यह आपका कहना गलत है।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : आ गई है और इसके साथ है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं जो मांग कर लाया हूं, उसमें नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : आप कौन से बिल की बात करते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप क्या इनको बचाने आये हैं पैसेन्जर टैक्स के लिये, राज्यपाल महोदय की स्वीकृति है। सैल्स टैक्स के लिये, प्रेसीडेन्ट की स्वीकृति लेना आवश्यक है...

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : सैल्स टैक्स के लिए जरूरत नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जरूरी है। मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। संविधान के आर्टीकल ३०४ के मातहत जरूरी है। आर्टीकल ३०१ में लिखा है :

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

"Subject to the other provisions of this Part, trade, commerce and intercourse throughout the territory of India shall be free."

इसके मातहत जो ३०४ है उसका रिलेवेन्ट पोर्शन आपको सुना देता हूं :

"(B) impose such reasonable restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse with or within....''

इस राज्य में और राज्य के बाहर

"......that State as may be required in the public interest."

पब्लिक इन्ट्रेस्ट में आप लगा सकते हैं।

"Provided that no bill or amendment for the purposes of Clause (b) shall be introduced in the legislature of a State without the previous sanction of the President."

आप कहते हो कि इसके मातहत जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके बाद भी आप यह कहते हैं जरूरत नहीं, तो यह सरकार जाने। मुझे जो मालूम हुआ है वह मैंने बता दिया है। खैर, जब आप तीस लाख रुपया वापिस कर सकते हैं, आपको यहां तक पता नही रहता कि कौन सा वकील बना था। आप तो सो रहे हैं; लॉ डिपार्टमेंट ने आपके घर में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बना रखा है, इस तरह की स्थिति आपने खुद ने पैदा करदी है।

इसके साथ-साथ, मैं आपको बकरी और पशुओं पर जो टैक्स लगाया गया है उसके बारे में अर्ज करना चाहता हूं, इसमें गधों को भी छोड़ा नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : वे तो इन्हीं की बिरादरी के हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह सरकार तो गधों को भी नहीं छोड़ रही है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : गधों को तो छोड़ रखा है। मैं इस सिलसिले में यह कहूंगा कि जहां जानवरों को पालने का किसानों को प्रोत्साहन मिला है; पशु-पालन द्वारा वह अपनी आमदनी बढ़ा रहा है, आज उसका सहारा पशु हैं, नीचे उसके धरती है, ऊपर आसमान है; इस बीच में वह पशुओं के सहारे अपनी आजीविका चलाता है। ऐसे लोग हैं जो घूम-घूम कर इस अकाल के वक्त में सौ-सौ और दो-दो सौ माइल से जाकर पशुओं को पालते हैं, उनको खिलाते-पिलाते हैं। आज सरकार ने एग्रीकल्चर विभाग के जरिये किसानों को प्रोत्साहन दिया है। पशुओं की ब्रीड को सुधारा है, लोग उसमें काम कर रहे हैं; तो आप इस तरह से इन पर टैक्स लगाकर अपने दामन पर धब्बा मत लगाइये। एक तरफ तो सरकार उनकी, पशुओं की, नस्ल सुधारने में मदद करती है और दूसरी तरफ जब वे बच्चे पैदा करते हैं, ज्योंही दो-चार बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं तो आप उन पर टैक्स लगाकर उनको दबोच लेना चाहते हैं। यमदूत की तरह उनसे टैक्स वसूल करने की सोचते हैं, इस तरह से आपको इन पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन को कार्यवाही म. प. ५ बज कर ६ मिनट पर दिनांक १६ मार्च, १९६६ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक १५ मार्च, १९६६)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
२५३९	अन्तिम पंक्ति	हांजी।	जी हां।
२५४०	३	श्री अब्दुलजब्टर	श्री अब्दुल जब्बार
२५४२	१४	ध्यान	ध्यान
२५४४	४	कही	कहीं
२५४५	५	(श्री चन्दनमल) वैद :	(श्री चन्दनमल वैद) :
२५४६	अन्तिम से २	हा	हो
२५४९	८	श्री मथुरेशबिहारी माथुर।	श्री अध्यक्ष : श्री मथुरेश-बिहारी माथुर
,,	१०	श्री अध्यक्ष :	--
२५५१	४	जानकारो	जानकारी
,,	१९	वार्गरियों	बार्गरियों
२५५२	१७	श्री दोलतराम	श्री दौलतराम
२५५३	२२	श्री हरिराम धारू (सिवाना सु०)	श्री हरिराम धारू (सिवाना-सु०)
२५५४	१४	(बरकतुल्ला खां)	(श्री बरकतुल्लाखां)
,,	१६	उन्होंने	उन्होंने
,,	१७	म्युनिसिपेलिटि	म्युनिसिपेलिटी
२५५५	शीर्ष	(श्री वरकतुल्ला खां)	(श्री बरकतुल्ला खां)
,,	४	वहां	वहां
,,	१२	स्टेट आॅर्डर	स्टे आॅर्डर
,,	२४	श्री वरकततुल्ला खां	श्री वरकतुल्ला खां
,,	,,	सम्वन्घ	सम्बन्ध
२५५७	१७	डवल्यू०	डब्ल्यू
२५५९- २५६०	शीर्षक	माच	मार्च
२५५९	अन्तिम से ८	क्रि	कि
२५६०	१	श्री कृष्णक्रुमार	श्री कृष्णकुमार
,,	२०	चुंडावत	चूंडावत
,,	अन्तिम से २	द्वारा	द्वारा
२५६१	३	मे	में
,,	अन्तिम से ४	हा	हो
,,	अन्तिम	विच राधीन	विचाराधीन
२५६२	अन्तिम से ४	स	से
२५६५	अन्तिम से १०	खड्डी वने	खड्डी से वने

१	२	३	४
२५६६	४	आर	अगर
२५७१	२	: (प्रतापगढ) :	(प्रतापगढ) :
२५७३	अन्तिम	-वेश	प्रवेश
२५७६	अन्तिम	[illegible]	इस प्रकार की
२५७७	अन्तिम	ओर	और
२५७८	अन्तिम से ८	श्री अभृतलाल	श्री अमृतलाल
,,	अन्तिम	नहों	नहीं
२५७९	१८	छापवृत्ति	छात्रवृत्ति
२५८०	अन्तिम	हो हैं	होते हैं।
२५८१-२५८२	शीर्षक	माच	मार्च
२५८२	अन्तिम से २	श्रो	श्री
२५८५-२५८६	शीर्षक	प्रश्नोत,- १५ मर्च,	प्रश्नोत्तर-१५ मार्च,
३५८६	२०	द्वार ।	द्वारा
२५८७	८	अथाप्त	अवाप्त
२५८८	अन्तिम से २	त्रा	श्री
२५९०	१२	फ्लांट	प्लांट
,,	१८	लिग्लाइट	लिग्नाइट
२५९१	६	श्री गोविन्दसिंह	२७४. श्री गोविन्दसिंह
२५९२	१४	मार्गी	मार्गो
,,	१६	मार्मो	मार्गो
२५९३-२५९४	शीर्षक	माच	मार्च
२५९६	११, १३, १४ व २८	प्राफिट	प्रॉफिट
२५९७	२	इन्वेस्टमेंट	इन्वेस्टमेन्ट
,,	३-४	इवे स्मेंट	इन्वेस्टमेन्ट
२५९९	१४	मे	में
२६०१	१३	हैं। लेकिन	हैं लेकिन
,,	१७	कक्ट	कलेक्ट
२६०४	१६	बह	वह
२६०५	१६	औरों	औरों
,,	१९	हैं, तो	हैं तो
२६०६	अन्तिम से २	अधिसूचन	अधिसूचना
,,	अन्तिम	ल० जस० जी०	एल० एस० जी०
२६०७	अन्तिम से ४	का	की
२६०८	२१	हिसाब जावे	हिसाब लगाया जावे
२६१०	२२	सर्बक्षण	सर्वेक्षण
२६१२	६	मंजूरी	मंजरी
२६१३	१३	नरख कर	न रह कर
२६१४	१४	कव	कव

१	२	३	४
२६२१	अन्तिम से ५	एग्रीकन्चरल	एग्रीकल्चरल
२६३०	अन्तिम से ८	ेश	पेश
२६३६	अन्तिम से ५	्यान	स्थान
२६३७	१७	देव,	देवें,
२६३८	२४	प्रॉपटी	प्रॉपर्टी
२६३९	अन्तिम से ७	फार्मिग	फार्मिग
२६४१	१७	तवज्जह	तवज्जोह
२६४२	५	आदमा	आदमी
२६४६	२२	सरकांर	सरकार
२६४७	२०	में	में
,,	२१	जागेरुक	जागरूक
,,	२४	साथियो	साथियों
२६४८	२५	परसॅन्ट	परसेन्ट
२६४९	१	काफो	काफी
२६५०, २६८२, २६९८	शीर्षक	अग्रेतर	अग्रेत्तर
२६५४	३	वा े	बारे
२६६५	अन्तिम से ३	खुदाकश्त	खुदकाश्त
२६६८	२०	श्री चन्द्रसिह बर्फा	श्री चन्द्रसिंह वर्फा
२६७१	शीर्ष	(श्रो लक्ष्मीचन्द)	(श्री लक्ष्मीचन्द)
२६७९	,,	(श्री चन्द्रसिंह वर्फा)	(श्री चन्द्रसिंह वर्फा)
२६८१	१५	आय	आप
२६८२	१८	इरीगेशन	इर्रिगेशन
,,	२२	इरीगेट	इर्रिगेट
२६८४	अन्तिम से ६	ग	यह
२६..	३	डाल्डा	डालडा
,,	१२	ज्याद्या	ज्यादा
२६८९	१०	डेवेलपमेंट	डेवलपमेन्ट
२६९१	११	फर्टीलाईजर	फर्टीलाइजर
२६९५	६	क्योकि	क्योंकि
२६९६	४	वढ़ोतरी	बढ़ोत्तरी
,,	६	म	में
,,	अन्तिम से १०	श्री दुर्गालाल ब ढ़दार	श्री दुर्गालाल बाढ़दार
२६९८	१९	beck wardness	back wardness
२७०५	५	म थुर	माथुर
,,	अन्तिम	इन्डेटेडनेस	इन्डेटेडनेस
२७११	१७	इसना	इतना
२७१६	१७	अभि	अभी
२७१७	८	फ्रस्ट	फर्स्ट
,,	अन्तिम	श्री सतीशचन्द्रे	श्री सतीशचन्द्र

१	२	३	४
२७१९	शीर्षक	आयन्व्ययक	आय-व्ययक
,,	१६	श्रो	श्री
२७२०	१३	श्री सा शिचन्द्र	श्री सतीशचन्द्र
२७२१	५	ओर	और
२७२३	१	श्री मथु ।दास	श्री मथुरादास
२७२५	६	श्री भरोंसिह	श्री भैरोंसिह
,,	१९	आंडिट	ऑडिट
२७३०	४-५	irreguldrities	irregularities
२७३२	अन्तिम से १६	श्री मथुर दास	श्री मथुरादास
,,	अन्तिम से २	के हैं, चुरक	कर चुके हैं
२७३७	१४	में	में
२७३८	१८	श्री भैरूंसिह	श्री भैरोंसिह
२७३९	१	(आसिन्द)	(आसीन्द)
२७४०	अन्तिम से १२	सरका	सरकार
२७५१	५	र टी	रोटी
२७५५	१	श्री न थू राम	श्री नाथूराम
,,	७	श्री गोविं सहाय	श्री गोविन्दसहाय
२७५६	शीर्षक	अ्रेतर	अग्रेत्तर
,,	३	श्री गोन्विदसहाव	श्री गोविन्दसहाय
२७५७	१	श्री ना ू र म	श्री नाथूराम
२७६०	अन्तिम से १४	झाड़ा	झगड़ा
,,	अन्तिम से ७	च हते	चाहते
२७६२	अन्तिम	करने के	करने के लिए
२७६३	अन्तिम से ११	जा	जो
२७६४	१६	क	के
२७६६	अन्तिम से ११	काई	कोई
२७६७	शीर्षक	माच	मार्च
२७६८	१८	आर	और
,,	२०	ाड़ी	गाड़ी
२७७१	३	thro ghout	throughout
,,	अन्तिम से ११	क न सा	कौन सा
२७७२	४	ता	तो
,,	अन्तिम से ६	सिए	लिए